यूनियन धारा
Union Dhara

जिल्द. 46, सं. 3 Vol.XXXXVI No.3, मुंबई जुलाई– सितंबर, 2020

गृहपत्रिका • HOUSE MAGAZINE OF

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम
A Government of India Undertaking
आन्ध्रा Andhra
कार्पोरेशन Corporation

अनुक्रमणिका
Contents

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
जुलाई–सितंबर, 2020 JULY-SEPTEMBER 2020
प्रकाशन तिथि : 14–11–2020

मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन)
ब्रजेश्वर शर्मा
Chief General Manager (HR)
Brajeshwar Sharma

संपादक
डॉ. सुलभा कोरे
Editor
Dr. Sulabha Kore

संपादकीय सलाहकार
कल्याण कुमार
नितेश रंजन
शैलेश सिंह
अम्बरीष कुमार सिंह

Editorial Advisors
Kalyan Kumar
Nitesh Ranjan
Shailesh Singh
Ambarish Kumar Singh

Printed and published by **Dr. Sulabha Kore** on behalf of Union Bank of India and printed at **JAYANT PRINTERY LLP** 352-54, Murlidhar Temple Compound, Near Thakurdwar Post Office, J.S.S. Road, Mumbai-400002. and published at Union Bank Bhavan, 'Nariman Point, Mumbai-400021.

Editor - Dr. Sulabha Kore
E-mail : sulabhakore@unionbankofindia.com
Our Address : Union Dhara,
11th Floor, Union Bank Bhavan,
239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point, Mumbai - 400 021.

E-mail : uniondhara@unionbankofindia.com
Mob. No. 9820468919
Tel.: 22896595 / 22896545 / 22896590

- परिदृश्य 3
- संपादकीय 4
- आत्मनिर्भर भारत – स्वतंत्र भारत 5
- साहित्य जगत से... 6–7
- काव्यधारा 8–9
- आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम 10–11
- Self Reliant India It's need and effectiveness 12–14
- Self Reliant India : A ray of hope 15–17
- आत्मनिर्भर भारत : बैंकों का योगदान 18–19
- Liberalization, Globalization & Privatization 20–21
- आत्मनिर्भर भारत : एक स्वतंत्र उड़ान 22–23
- Steps of Aatmanirbhar Bharat 24–26
- शिखर की ओर 27
- आत्मनिर्भर भारत : भारतीय भाषाओं का महत्व 28–29
- नई तकनीक का उपयोग/बधाई 30–31
- स्वदेशी आंदोलन एवं आत्मनिर्भर भारत 32–33
- आत्मनिर्भर भारत : समस्याएं एवं व्यवधान 34–35
- Aatmnirbhar Bharat: Initiatives & Incentives 36
- डिजिटल आत्मनिर्भरता 37
- Quiz Atmanirbhar Bharat 38–39
- सेंटर स्प्रेड : लद्दाख 40–41
- Self – Reliant India Independent India 42-43
- आत्मनिर्भर महिलाएं – जागरुक महिलाएं 44–47
- आत्मनिर्भर भारत – लोकल के लिए वोकल 48–49
- Aatmnirbhar Bharat- Problems & Interventions 50
- Aatmnirbhar Bharat : How helpful are the NRIs 51-53
- यूनिवन 54-55
- What's new 56-57
- चरक का कोना 58
- गांवों का विकास 59
- Face in UBI crowd 60-61
- प्रतियोगिता क्र. 155/परिणाम 62
- Aatmnirbhar Bharat : where are the possibilities 63
- शुभमस्तु / हमें गर्व है 64
- पुरस्कार और सम्मान 65
- समाचार दर्शन 66–74
- The Self Reliant Woman 75
- सेवानिवृत्त जीवन से... 76–77
- हेल्थ टिप्स/व्यंजन 78
- आपकी पाती 79
- बैंक कवर 80

इस पत्रिका में व्यक्त विचारों से प्रबंधन का सहमत होना अनिवार्य नहीं है.

Designed and Printed at **JAYANT PRINTERY L.L.P.**, Mumbai-400002.

परिदृश्य
PERSPECTIVE

प्रिय यूनियनाइट्स,

'आत्म निर्भरता' का गुणगान करते अरस्तू से लेकर गांधी जैसे विभिन्न विचारकों ने इसे सदमार्ग बताया है. आत्मनिर्भर बनने की अभिलाषा कोई नई बात नहीं है. स्वाधीन भारत ने अपनी प्रारम्भिक विकास यात्रा में सीमित सफलता के साथ आत्म निर्भरता प्राप्त की थी. तब 'आत्म निर्भरता' का लक्ष्य 'आयात प्रतिस्थापन' द्वारा दुर्लभ विदेशी विनिमय की बचत करना था. वर्तमान में 'आत्म निर्भरता' की दिशा में हमारे प्रयासों का संदर्भ दूसरा है. विगत तीन दशकों से हमारे विकास का अवलोकन बाजारोन्मुख सुधारों से प्राप्त अच्छे नतीजों का अनुसमर्थन करता है. आज भारत विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हमारा लक्ष्य 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त करना हैं. हम व्यापार के लिए सबसे मुक्त देशों में से एक हैं. पूंजी प्रवाह में कुछेक गतिरोधों के साथ हमारे पास पर्याप्त फॉरेक्स रिजर्व उपलब्ध है. भारत आज विश्व व्यवस्था में अपना उचित स्थान प्राप्त करने की दिशा में अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए एक निर्यात शक्ति बन रहा है.

कोविड महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में बाधा पहुंचाई है, इसने व्यापार प्रतिस्पर्धाओं की वर्तमान विशेषज्ञता हासिल करने के सम्मुख चुनौतियाँ उत्पन्न कर दी हैं. विश्व राष्ट्रीयताओं में बंटा हुआ है, जिससे नीतिनिर्माता अन्य मुद्दों पर राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं, प्रमुख क्षेत्रों में घरेलू उद्योगों को खड़ा करना अनिवार्य हो गया है. हमें अपने रचनात्मक उपक्रमों के प्रवाह को बनाए रखते हुए समस्याओं को सुलझाना चाहिए, देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए एवं विश्व की हमसे जो अपेक्षाएँ हैं उससे और बेहतर कोशिश करनी चाहिए. सरकार ने इसे भारत के लिए मौके के तौर पर लिया है एवं सभी क्षेत्रों में हमारे जनसांख्यिकीय अवसरों का लाभ उठाने के उद्देश्य से कई सुधारों की घोषणा की है. चूंकि देश 'आत्मनिर्भर' बनने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है, ऐसे में समाज के कमजोर वर्गों को समर्थ बनाने, उद्यमों को समय के साथ उच्च स्तर प्राप्त करने एवं वैश्विक बाज़ार में प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धी बने रहने हेतु हमारे बैंकों का एक बड़ा दायित्व एवं भूमिका है. भारत निश्चित तौर पर वायरस के विरुद्ध जीत हासिल करेगा और शीघ्र ही 'आत्मनिर्भर' बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा.

मुझे प्रसन्नता है कि हमारी द्विभाषिक गृह पत्रिका 'यूनियन धारा' का यह अंक 'आत्मनिर्भर भारत' को समर्पित है. यह हमारे देश की आकांक्षाओं को पूरा करने के व्यापक परिदृश्य, नीतिगत पहल और बैंकिंग उद्योग के लिए अवसरों को समाहित किए हुए है. टीम यूनियन धारा और सभी योगदानकर्ताओं को मैं बधाई देता हूँ. आप सभी को अत्यंत सूचनाप्रद पठन हेतु शुभकामनाएं.

शुभकामनाओं के साथ,

राजकिरण रै जी

राजकिरण रै जी.

Dear Unionites,

'Aatm-nirbharta', i.e. self-reliance, has been extolled as a virtuous path by thinkers from Aristotle to Gandhi. Aspirations of becoming self-reliant is not new. India actively pursued self-reliance in her early developmental journey with limited success. The erstwhile 'self-reliance' pursuit, however, was motivated by desire for saving scarce foreign exchange through "import substitution". Our quest for "Aatm-nirbharta" has a different context today. Our growth experience for last three decades is validation of pro-market reforms bearing fruit. India is now the fifth largest economy with aims of becoming USD 5 trillion in gross domestic product. We are among the most open countries for trade, having sizable forex reserve and with few checks on capital flows. India today wished to gain her rightful place in global order, becoming the export powerhouse while meeting her domestic needs.

The Covid Pandemic has disrupted economies, challenging the extant wisdom of pursuing specialization for trade competeveness. With world divided along nationalities, policy-makers prioritizing national interest over others, building domestic industries in key sectors has become imperative. We must let our creative enterprises flow and solve the problems, meeting the needs of the country and raising the expectations of the world. Government is seized of India's opportunity as it announced several reforms across sectors to harness our demographic opportunity. As the country focuses on becoming "Aatm-nirbhar", our banks have a greater role and responsibility to empower weaker sections of society, help enterprises gain scale over time, and compete effectively in global markets. India will win against the virus, for sure, and realize her goal of becoming 'Aatm-nirbhar', sooner than later.

I am happy to see our in-house bi-lingual magazine, "Union Dhara" dedicating an issue to "Aatm-nirbhar Bharat" theme. It covers a broad spectrum of ideas, policy initiatives, and opportunities for banking industry to help realize the aspirations of our Nation. My compliments to the team Union Dhara and all the contributors. Wish you all a very informative reading ahead.

With best wishes,

Rajkiran Rai G.

संपादकीय
EDITORIAL

प्रिय दोस्तो,

आत्मनिर्भर का अर्थ स्वयंपूर्णता है. व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए क्योंकि दूसरों पर निर्भरता, उसकी प्रगति एवं विकास में रुकावट बन जाती है, जबकि आत्मनिर्भरता उसे स्वतंत्रता एवं आजादी प्रदान करती है. यदि कोई देश आत्मनिर्भर है तो वह विकास की ओर बाधारहित कदम बढ़ा सकता है.

आत्मनिर्भर भारत एक नया अभियान है जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश एवं इसके नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य के साथ नए भारत के निर्माण के विजन को ध्यान में रखकर प्रारंभ किया गया है. यह अभियान भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड-19 सहित सभी विषमताओं से लड़ने में सहयोग प्रदान करता है. यह पाँच स्तंभों जैसे अर्थव्यवस्था, आधारभूत, तंत्र, जीवंत जनसांख्यिकी एवं माँग के साथ पाँच चरणों एमएसएमई सहित व्यापार, प्रवासी एवं किसानों सहित गरीब, कृषि, विकास के नए आयाम एवं आखिरी तथा बहुत महत्वपूर्ण सरकारी सुधार एवं समर्थन पर आधारित है. इन पांच स्तंभों एवं पाँच चरणों के साथ, भारत आत्म निर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा रहा है. भारत ने कोविड-19 के लिए अपनी पीपीई किट्स का विकास किया है और इसे दुनिया को उपलब्ध करवाया है. देश ने इसकी वैक्सीन भी तैयार की है और इस वैश्विक आपदा से निपटने के लिए अन्य देशों की सहायता हेतु प्रयत्न भी कर रहा है. नए उद्योगों को स्थापित कर, नई तकनीकी का प्रयोग कर, सुई से लेकर जहाज तक के निर्माण की योजना बनाकर, शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन कर, चिकित्सकीय उपचारों एवं अस्पतालों का आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण आदि कारक बहुत प्रभावी तौर पर कार्य करेंगे और भारत एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उभरेगा.

आत्म निर्भरता का अर्थ दूसरों से अलग-थलग रहना नहीं है अपितु इसका अर्थ यह है कि जीवन में सफलता के लिए किसी अन्य पर निर्भर न रहें या हम अपनी आजीविका के लिए दूसरों से सहायता की अपेक्षा न करें. मुझे विश्वास है कि आत्मनिर्भर बनना व्यक्तिगत तथा देश के लिए भी सबसे अच्छी विशेषता है.

दोस्तो, आत्मनिर्भर बनें और यूनियन धारा का यह आत्मनिर्भर विशेषांक आपको कैसा लगा इससे हमें अवगत कराएं.

शुभकामनाओं सहित.

आपकी,

डॉ. सुलभा कोरे

Dear friends,

Aatm Nirbhar means self-sufficient or self-reliant. One has to be Aatma Nirbhar as it gives you independence and freedom from dependency on others which may hamper your progress and development. If a country is self reliant then it will have an unhindered march towards development.

Aatm Nirbhar Bharat is a new campaign launched on 12th May, 2020 by our PM Mr. Narendra Modi having vision of new India with the aim to make the country and its citizens self reliant. This campaign supports Indian Economy to fight against all odds including COVID-19. It works with Five pillars such as Economy, Infrastructure, System, Vibrant Demography and Demand with Five phases such as Business including MSMEs, the Poor including migrants and farmers, Agriculture, New horizons of growth and last but not least, Govt. reforms and enablers. With these 5 pillars and 5 phases, India is marching ahead in pace with Self Reliance. India developed its own PPE kits for COVID-19 making it available to the world. It also developed a Vaccine on it trying to help other countries to overcome this worldly disaster. By establishing new industries, using new technology, planning for production from needle to plane, giving importance to agriculture making changes in education policy, modernising medical treatment and hospitals, digitalisation etc. All these factors are going to work very effectively and soon India will be emerging as a self reliant country.

Self reliant doesn't mean isolation from others but it means no one should depend on others for success in life or we should not expect help from others to run our livelihood. I believe being self reliant is the best quality for both the individual and the country.

Friends, be self reliant and let us know how you like this Self Reliant special issue Of Union Dhara.

With Best wishes.

Yours truly,

Dr. Sulabha Kore

आत्मनिर्भर भारत 'स्वतंत्र भारत'

आज की अर्थ आधारित दुनिया में वही राष्ट्र स्वतंत्र हैं जो आर्थिक रूप से समृद्ध है. यदि किसी देश की आर्थिक निर्भरता दुनिया के किसी अन्य देश पर है तो आप राजनैतिक, वैचारिक और सामाजिक रूप से स्वतंत्र होने की कल्पना नहीं कर सकते हैं. कहने का तात्पर्य यह है कि भारत स्वतंत्र तभी होगा जब जीवन के लिये आवश्यक क्षेत्रों में उसकी आत्मनिर्भरता होगी. आत्मनिर्भरता न होने की स्थिति में वैश्विक आर्थिक ताक़तें आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावित करती रहेंगी.

आत्मनिर्भर होना हर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का स्वप्न होता है. हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि 'एक राष्ट्र की शक्ति उसकी आत्मनिर्भरता में है, दूसरों से उधार लेकर काम चलाने में नहीं.' आत्मनिर्भर राष्ट्र ही अपने राष्ट्र को सर्वोपरि बना सकता है क्योंकि जो राष्ट्र आत्मनिर्भर होता है वो अपने पैरों पर खड़ा होता है और वही अपने आप में सबसे अच्छा होता है.

बीते दिनों आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की मार से चरमराती अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए की थी. इस अभियान के द्वारा भारत में लोगों को काम-काज करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और यह प्रयत्न किया जाएगा कि अगले कुछ सालों में भारत अपनी जरूरतों की अधिकतर वस्तुएं अपने देश में ही तैयार करें अर्थात् आत्मनिर्भर बने.

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक सत्र 2020 को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया है. आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत भारत को उस बाज की तरह ऊंची उड़ान भरनी चाहिए जो कि सबसे ऊपर पहुंच कर भी हर जीव पर नजर रखता है.

हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी यही सपना था कि भारत स्वदेशी चीजों को अपनाए तथा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएं.

हम यहाँ पर यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि आत्म निर्भरता का अर्थ यह नहीं है कि हम चीन के सामान या अन्य किसी देश के सामान का आयात बंद कर दें, इसका मतलब है कि हमारा खुद का सामान इतना सस्ता और अच्छा हो कि लोग विदेश के सामान को त्यागकर, स्वदेशी सामान को खरीदें.

आत्मनिर्भर भारत या self-reliant इंडिया का यह मतलब है कि अब अधिक से अधिक चीजों को अपने देश में ही बनाने का प्रयास होगा. साथ ही, जो चींज़े इस अभियान के अंतर्गत भारत में बनाई जाएगी, उसका दूसरे देशों में निर्यात भी किया जाएगा. उदाहरण के लिये पहले हमारे देश में hydroxychloroquine नामक दवाई का ज्यादा उत्पाद नहीं हुआ करता था लेकिन कोविड-19 के समय हमारे देश ने इसका उत्पाद कई गुना बढ़ाया और ना सिर्फ इसे हमारे देश तक ही सीमित रखा बल्कि दूसरे देशों को भी इस दवाई को इस्तेमाल करने का मौका दिया.

कोविड-19 की वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था भले ही कई साल पीछे चली गई है पर इसी आपदा के दौरान ही हमें पता चला कि हमारे देश में किस चीज की कमी है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिये. इन चीजों को बहुत ही बारीकी से समझते हुए और समय की मांग पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरे देश को दिखाया. अभी कुछ ही महीनों पहले जो 20 लाख करोड़ का पैकेज, सरकार द्वारा पेश किया गया था उसमें से कुछ आत्मनिर्भर भारत अभियान पर भी खर्च किया जाएगा ताकि हमारा देश जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बने.

माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में यह भी कहा था कि ''जरूरी नहीं कि हम एक साथ जितनी भी दूसरे देशों की चीजें हैं उसका उपयोग करना छोड़ दें पर आज से यह जरूर प्रयास करें कि जो भी चीज लें वह भारत में बनी हो जिससे उसका जितना भी पैसा होगा वह भारत सरकार के पास ही जाएगा और वह लोगों की सुविधाओं के लिए ही खर्च होगा''.

आत्मनिर्भर भारत अभियान निम्नलिखित 5 स्तंभों पर आधारित है.

1) अर्थव्यवस्था 2) आधारभूत संरचना 3) प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली 4) जनसंख्या संरचना 5) मांग

उपरोक्त स्तंभों के आधार पर देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे देश की सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान राहत पैकेज के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र को महत्वपूर्ण माना है और उसमें परिवर्तन पर बल दिया है-

* मेक इन इंडिया * निवेश को प्रेरित करना * सरल और स्पष्ट नियम कानून * नए व्यवसाय को प्रेरित करना * उत्तम आधारिक संरचना * समर्थ और संकल्पित मानवाधिकार * बेहतर वित्तीय सेवा * कृषि प्रणाली में सुधार

अंत में यह याद रखना चाहिए कि हम जिस राष्ट्र की मिट्टी में पले बढ़े हैं, क्यों न उस राष्ट्र का कर्ज हम कुछ इस प्रकार उतारें कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर भारत को विकसित देशों की कतार में शामिल करें. इससे हमारा राष्ट्र आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से स्वतंत्र राष्ट्र हो सकेगा.

मनु
क्षे.म.प्र.का., अहमदाबाद

प्रसिद्ध मराठी हिन्दी साहित्यकार : दत्तात्रेय वामन पोतदार

हिन्दी साहित्य एक सागर के समान है जिसके विकास तथा प्रयोग को बढ़ावा देने में विभिन्न राज्यों तथा विभिन्न साहित्यकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. हिन्दी कभी भी भारतीयों से दूर नहीं रही. इसी का परिणाम है कि देश के सभी राज्यों में हिन्दी को मान-सम्मान प्राप्त हुआ है. वैसे राज्य जहां की मातृभाषा वहां की अपनी भाषा है वहाँ भी हिन्दी को सहर्ष स्वीकारा गया है तथा हिन्दी के विकास में भी उनकी अहम भूमिका रही है. इसी श्रेणी में आते हैं महाराष्ट्र के प्रसिद्ध हिन्दी एवं मराठी साहित्यकार दत्तात्रेय वामन पोतदार.

हिन्दी को महाराष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी भाषा बनाने में वामन जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है. इसी कारण उन्हें महाराष्ट्र का 'साहित्यिक भीष्म' भी कहा जाता है. इस महान कार्य के लिए वामन पोतदार जी आजीवन अविवाहित रहने का दृढ़ निश्चय का कठिन निर्णय लेते हुए हिन्दी एवं मराठी साहित्य की सेवा दिन-रात करते रहे.

परिचय : दत्तात्रेय वामन पोतदार का जन्म दिनांक 05 अगस्त, 1890 को महाराष्ट्र राज्य के बीरबंडी नामक स्थान पर हुआ था. वे केवल लेखक ही नहीं बल्कि बहुत बड़े समाज सेवी भी थे. वामन पोतदार जी ने वर्ष 1906 ई. में नूतन मराठी विद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की. उन्होंने मराठी के अलावा इतिहास विषय का भी गहरा अध्ययन किया. उन्होंने शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए बहुत ही सार्थक एवं सफल प्रयास किया तथा उनके प्रयासों के बदौलत महाराष्ट्र में शिक्षा व्यवस्था को व्यापक दिशा मिली. उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में शिक्षण संस्थाएं स्थापित कराई तथा सभी शिक्षण संस्थाओं में पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था करवाई. आज भी पूरे महाराष्ट्र के शिक्षण संस्थाओं में पुस्तकालय एवं वाचनालय की उपलब्धता का श्रेय वामन पोतदार जी को जाता है.

वामन पोतदार को एक प्रसिद्ध मराठी इतिहासकार, लेखक तथा वक्ता के रुप में जाना जाता है. उन्होंने शिक्षा के विकास में प्रमुख भूमिका निभाते हुए स्वतंत्र्योत्तर भारत में पुणे विश्वविद्यालय के कुलपति के रुप में भी वर्ष 1961 से 1964 तक अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया. उनकी विद्वता तथा प्रसिद्धी को इस बात से जाना जा सकता है कि उन्हें ब्रिटिश हुकुमत ने वर्ष 1946 में महामहोपाध्याय की उपाधि से सम्मानित किया. हिन्दी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार की ओर से उन्हें वर्ष 1967 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था. हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें साहित्य वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया

गया. इन्हें बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा पुणे विद्यापीठ की ओर से डी.लिट. की उपाधि से भी सम्मानित किया गया.

वामन पोतदार जी वर्ष 1922 में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग मुंबई की बैठक में स्वीकृत सदस्य बने. वर्ष 1940 में वे भारत सरकार के प्रतिनिधि के रुप में आयोग के सदस्य नियुक्त हुए. वर्ष 1933 से 1936 तक महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका के संपादक रहे. आप वर्ष 1939 में अहमदनगर स्थित मराठी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी बनाए गए. आप वर्ष 1946 से 1950 तक पुणे शिक्षण प्रसारक मंडल के अध्यक्ष बने. आप वर्ष 1948 में महाराष्ट्र विद्यापीठ के कुलपति बने. वर्ष 1950 से 1953 तक आप हिन्दी शिक्षण समिति के अध्यक्ष बने तथा इसी वर्ष संस्कृत महामंडल के अध्यक्ष भी बने.

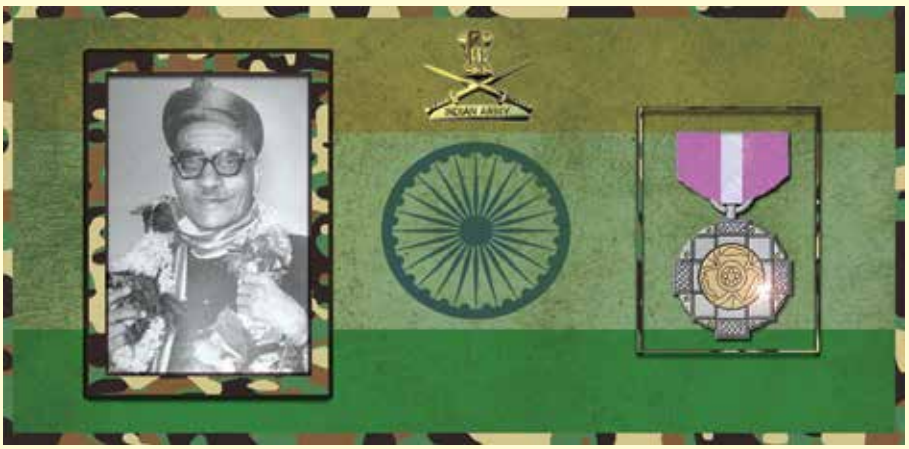

वामन पोतदारजी ने इतिहास विषय के शोध में निरंतर योगदान हेतु लोगों को जोड़ने के लिए भारतीय इतिहास संशोधक मंडल की स्थापना की. अभी भी यह संस्थान इतिहास के शोध संस्थान के रुप में देश के शीर्ष संस्थानों में जाना जाता है. मराठी भाषा में उनके सैकड़ों लेख, निबंध किताबें जोकि मान्यता प्राप्त हैं आज भी पूरे देश में पढ़ी जाती हैं.

राजभाषा हिन्दी के विकास हेतु उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है.

रचनाएं : वामन पोतदार जी ने इतिहास, मराठी एवं हिन्दी की कई पुस्तकें लिखी हैं. आपकी कुछ प्रमुख पुस्तकें निम्नलिखित हैं:

'ऐतिहासिक चरित्र लेखन', 'दगडांची कहानी', 'पुरोगामी वाङ्मय', 'पोतदार विविध दर्शन', 'प्रांतिक भाषांचे भवितव्य', 'भारताची भाषा समस्या', 'भाषावार विद्यापीठे', 'मराठी इतिहास व इतिहास संशोधन', 'महाराष्ट्र साहित्य परिषद-इतिहास', 'वृत्त विभाग व साधन विभाग', 'देवदास कृत संतमालिका', 'सुमन सप्तक', 'श्रोते हो' आदि.

अपने पूरे जीवन में मानव समाज, शिक्षा तथा हिन्दी साहित्य की सेवा करते हुए पोतदार जी दिनांक 06 अक्टूबर, 1979 को हमसे विदा हो गए. वामन पोतदार द्वारा लिखित पुस्तक 'वाङ्मय लेखन व जीवन' से उनके व्यक्तिगत चरित्र के बारे में विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होती है.

कहा जाता है कि वामन पोतदार जैसे महापुरुष धरती पर आकर जनसेवा एवं साहित्य सेवा के माध्यम से एक उदाहरण प्रस्तुत कर जाते हैं. महाराष्ट्र में जन्म लेने के बाद भी हिन्दी के प्रति उनकी निष्ठा यह दर्शाती है कि वे हिन्दी साहित्य से कितना लगाव रखते हैं. उनका बहुआयामी व्यक्तित्व हर क्षेत्र में रोशनी प्रदान करता है. वे आधुनिक युग में एक युगद्रष्टा के रुप में गगन पर विद्यमान हैं. उनकी अमिट पहचान हिदी भाषा के विकास में आज भी प्रेरणादायी संदेश प्रदान करता है. इनके कार्य हम सब के लिए प्रेरणा का स्त्रोत बनकर अमिट रुप से लगातार दिशा प्रदान करते हैं. उनकी साहित्य सेवा पूरे भारत वर्ष के लिए अनुकरणीय है. उन्होंने दिन-रात मराठी एवं हिन्दी साहित्य की सेवा के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में हिन्दी को ऊच्च दर्जा प्राप्त कराने में प्रमुख भूमिका का निर्वहन किया. उनके लेख, निबंध, रचनाएं हिन्दी एवं मराठी साहित्य की अमूल्य निधि हैं. वामन पोतदार हम सब के लिए प्रेरणास्त्रोत हैं.

डॉ. विजय कुमार पाण्डेय
क्षे.का., पटना

छोटी सी ख्वाहिश

बस एक छोटी सी ख्वाहिश,
आसमान को छूने की
बस एक छोटी सी चाहत
मंजिल को पाने की,

मंजिल मिली तो किस्मत,
नहीं मिली तो फिर से मेहनत,
रास्ता पता है मगर कठिन है थोड़ा,
कोई बात नहीं मगर सबने साथ छोड़ा।

अकेले ही तो चले हैं आज तक
बस अपनों की ज़रा कमी खलेगी,
हौसला कम न हो,
फिर तो होंगे रास्ते आसान, मंज़िल भी मिलेगी।

मोनालिसा मार्ग्रेट तिरकी
चांपा शाखा, बिलासपुर

आत्मनिर्भरता

निहित है आत्मबल में, बलशाली का वैभव
आत्म सम्मान से ही होता गरिमा का उद्भव

निर्भरता दूजे पर, मानसिकता की बेड़ियाँ जैसे
सफलता पाना, बीच में किन्तु
अनुभव की खाड़ियाँ जैसे

अपने हाथ को जगन्नाथ जाना है हमने
परिश्रम को ही तो प्रार्थना माना है हमने
कर्मवीरों की गाथा है,
इतिहास के चमकते ललाट पर
सदियों पहले शून्य दिया था, गंगाजी के घाट पर

हमसे पाया है संसार ने
शल्यक्रिया, खगोल, योग का ज्ञान
प्रक्षेपण, गणित, ललित कला की
हम ही से थी पहचान

सब कुछ तो था पास तेरे,
अब भी सब कुछ है पास
फिर से उसे जगाना होगा, जो सुसुप्त पड़ा था विश्वास,
रचना होगा फिर से तुझे अपना स्वर्णिम भविष्य
दे आगामी पीढ़ियों को गौरवशाली इतिहास

सम्मान करना होगा तुझे अपनी इस स्वतन्त्रता का
पराश्रित होना परिचायक है
पराधीनता का, परतंत्रता का

अपना आत्मबल पहचान, स्वयं लिख महागाथा
गाड़ ध्वज शिखर की छाती पर
ऊंचा कर देश का माथा

पुरानी साख है नए सरोकार हैं
सक्षम को संभावनाएं अपार हैं
साथ हो अनुभव का कुछ ऐसे उत्साह से
तरंगिणी जैसे मिलती है अविरल प्रवाह से

ज्ञान की बाती हो, हो परिश्रम का तेल
होगा भविष्य उजियारा, जब होगा ऐसा मेल
नए संकल्प लेकर, समेटे अमिट स्मृतियाँ
बढ़ाना है देश का गौरव
निहित है आत्मबल में बलशाली का वैभव
आत्म सम्मान से ही होता गरिमा का उद्भव

शफ़ीक़ ख़ान
क्षे.का., रायपुर

आत्म विश्वास

खुद पर विश्वास तो कर तू,
तू क्या नहीं कर पाएगी,
इस संसार की कोई परेशानी,
तेरे आगे नहीं टिक पाएगी।
पर कदम तुझे बढ़ाना होगा,
हिम्मत तुझे दिखानी होगी,
बिना तेरी इच्छा के,
पतवार भगवान से भी नहीं हिल पाएगी।
फिर देर किस बात की है,
किसका है इंतजार, आज संभल जाएगी,
तो होगा तेरा हर सपना साकार।
समय जो बीता, नहीं लौटता,
रह जाता है पछतावा,
आज का महत्व समझ,
दे अपने कल को आकार।
कर्म में जो ताकत है,
जो बदल दें हाथों की लकीरों को,
लकीरों के भरोसे बढ़ेगी
तो हाथ मलती रह जाएगी।
जरूरत है एक छोटी सी चाह की,
जो बन जाए चिंगारी,
चमक उठेगी प्रतिभा तेरी,
पहचान जाए दुनिया सारी।
एक कदम तू बढ़ा,
रास्ते का हमसफर भी मिल जाएगा,
खुदा भी सहारा देगा तुझे
अगर विश्वास है तेरा भारी।

मेघना फरसोदिया
मिड कॉर्पोरेट शाखा, भोपाल (सें.)

आत्मनिर्भर भारत

जब, खत्म होगा अमीरी का अहम,
मिट जाएगा गरीबी का डर
तब, बनेगा आत्मनिर्भर भारत।

जब, होंगे नौकरी लेने वालों से ज्यादा,
हर एक को नौकरी देने वाले
तब, बनेगा आत्मनिर्भर भारत।

जब, मिलेगा किसानों को उचित दाम,
कामगारों को उचित काम और
पेशेवरों को उचित नाम
तब, बनेगा आत्मनिर्भर भारत।

जब तक, रहेगी सिक्कों की खनक,
नेताओं की धमक और
दूसरे देशों की चमक
तब तक, कैसे बनेगा आत्मनिर्भर भारत।

जब,मिलेगा हर समस्या का तुरंत समाधान,
होगा हर महिला का सम्मान
तब, बनेगा आत्मनिर्भर भारत।

जब, मिलेगी कार्यकारी शिक्षा,
होगी इस मुद्दे पर हर रोज समीक्षा
तब, बनेगा आत्मनिर्भर भारत।

जब, देश में सब की जरूरतें पूरी होंगी,
खाने को रोटी और सोने को जगह होगी
तब, बनेगा आत्मनिर्भर भारत।

जब, अपनी जिम्मेदारियां हम खुद निभाएंगे,
हर अवसर को आत्मनिर्भरता में बदल पाएंगे
तब, बनेगा आत्मनिर्भर भारत।

मोहम्मद शाद
दोंडाईचा शाखा, नासिक

मजदूर

सोचा ना कल के सपनों का
आज को खुल के जीते जरूर हैं
जीने की चंद ज़रूरतों से दूर हैं
हाँ, हम मजदूर हैं।।

जोड़कर बना दें हम घर सभी का
पर झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं
नाता अपना खुशियों से बाबत दूर हैं
हाँ, हम मजदूर हैं।।

दिन की दैनिक दिनचर्या ही श्रम है
गम का बोझ उठाने को मशहूर हैं
रखते खुद को महत्ताओं से भी दूर हैं
हाँ, हम मजदूर हैं।।

उलझे हालातों से हँसकर लड़ लेना
करते सामना, होते न थक के चूर हैं
फिर भी दिल की गरीबी से कोसों दूर हैं
हाँ हम मजदूर हैं।।

विक्रम सिंह
सादात मुख्य शाखा, गाजीपुर

अन्नदाता

कहना मुश्किल है कि बात क्या है?
आवाजें बहुत हैं पर जज़्बात क्या है?
वो देता है जो सबको दोनों हाथों से
आज आखिर उसके हाथ क्या है?

तपती धूप हो या कडकड़ाती सर्दी।
बेशर्म सूखा हो, या बाढ़ बेदर्दी।
एड़ी से चोटी का वह ज़ोर लगाता है
तभी हमारी तश्तरी में, ताज़ा खाना आता है।
बात सुन मेरी, बोला मासूम माँ से,
पर माँ, ये तो आशीर्वाद का आटा है।
माँ ने भी जवाब दिया नटखट का, नम आँखों से,
बेटा, जिसका यह आशीर्वाद है
वह किसान कहलाता है।

किसकी इतनी औकात,
जो उसको आशीर्वाद देगा
जितनी मर्ज़ी होगी, उतना प्रसाद वो देगा
अन्नदाता-विधाता है इस मंदिर का
अरे, कोई पुजारी क्या उसकी सेवा करेगा?
वो कहते हैं कि भला होगा
हम कहते हैं कि खाली दुआओं से क्या होगा
करना है तो ये वादा करो,
कम से कम तो कोई इरादा करो
वरना सोचो, आधी आबादी का
मुस्तकबिल क्या होगा
'बात क्या है?' अब यह कहना मुश्किल नहीं है
आधी से ज्यादी आबादी के, जज़्बात यही है।

अमन सक्सेना
क्षे.का., बड़ौदा

आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम

आओ, मिलकर अखंड भारत बनाना है,
स्वदेशी उत्पादों को अपनाना है,
भारत को आत्मनिर्भर बनाना है.

हर व्यक्ति के लिए आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ा और अच्छा गुण होता है. इसके साथ ही, यह उसके लिए बड़ा सहारा भी बनता है. यदि व्यक्ति आत्मनिर्भर रहेगा तो उसे किसी दूसरे की बहुत ही कम जरूरत पड़ेगी और वह खुद बड़ी से बड़ी मुश्किलों का आसानी से मुकाबला कर सकता है. आत्मनिर्भर होना जितना जरूरी व्यक्ति के लिए है उतना ही जरूरी एक देश के विकास के लिए भी है.

आत्मनिर्भर भारत अभियान : देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी ने, 12 मई 2020 कोरोना संकट के इस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया था. इस पैकेज को 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' का नाम दिया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी का कहना है कि इस बड़े राहत पैकेज से भारत में, लोगों को कामकाज करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और यह कोशिश की जाएगी कि अगले कुछ सालों में भारत अपनी जरूरत की अधिकतर चीजों के लिए खुद पर निर्भर हो जाए. इसलिए इस अभियान का नाम 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान रखा गया है.

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत देश को आत्मनिर्भर बनाना है. आत्मनिर्भर बनाने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों का उत्पादन देश में ही हो और सभी भारतवासी अपने देश में बने या अपने देश की कंपनियों द्वारा बनाए गए सामानों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें. आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विदेशी उत्पादों/कंपनियों पर देश की निर्भरता को कम से कम करना है.

आत्मनिर्भर भारत अभियान – नई अपडेट

केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत स्कूल और उच्च शिक्षण के छात्रों के लिए टोल फ्री नंबर 8448440632 जारी किया है. इस टोल फ्री नंबर की सहायता से देश के समस्त नागरिकों के बच्चों की पढ़ाई में यदि कोई परेशानी आती है तो वे इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया है. आत्मनिर्भर भारत ऍप को आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत स्टार्ट-अप और टेक कम्युनिटी की मदद के लिए लांच किया गया है. इस ऐप के माध्यम से देश के युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित किया जायेगा. भारत में एक गतिशील प्रौद्योगिकी और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र है जिसने भारत को राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है.

भारत ने डिजिटल स्ट्राइक करते हुए चीन के 59 ऐप्स को बैन कर दिया है जिसके बाद भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत ऐप को लॉन्च किया गया है. आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज दो ट्रैक पर काम करेगा. ट्रैक-1 मिशन मोड में काम करते हुए अच्छी क्वालिटी के ऐप्स की पहचान करेगा. ट्रैक-2 के तहत नए ऐप्स और प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आइडिएशन के स्तर से लेकर बाजार की पहुंच तक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी. इस ऐप के माध्यम से मौजूदा ऐप्स को प्रोत्साहन मिलेगा, जैसे कि ई-लर्निंग, वर्क फ्रॉम होम, गेमिंग, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, ऑफिस यूटिलिटीज और सोशल नेटवर्किंग की श्रेणियों वाले ऐप्स को सरकार गाइड करने के साथ सहायता करेगी.

आत्मनिर्भर भारत अभियान राहत पैकेज के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्र

* कृषि प्रणाली * सरल और स्पष्ट नियम कानून * उत्तम आधारित संरचना * समर्थ और संकल्पित मानवाधिकार * बेहतर वित्तीय सेवा * नए व्यवसाय को प्रेरित करना * निवेश को प्रेरित करना * मेक इन इंडिया

आत्मनिर्भर भारत अभियान से लाभान्वित होने वाले क्षेत्र

इसमें सबसे पहले कृषि क्षेत्र, खनन क्षेत्र, मत्स्य पालन क्षेत्र शामिल किए गए हैं.

दूसरे जो निर्माण क्षेत्र, विनिर्माण और उपयोगिताओं के साथ-साथ, एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम), कुटीर उद्योग आदि जो दिन रात देश के लिए कार्य कर रहे हैं.

तीसरा सेवा क्षेत्र है जिसमें खुदरा, पर्यटन, बैंकिंग, रियल एस्टेट, मनोरंजन, संचार, आतिथ्य और अवकाश, आईटी सेवाएं आदि शामिल की गई हैं.

20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज से गरीबों को फायदे:-

एक करोड़ 70 लाख रुपए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तरह गरीबों को दिया जाएगा.

इंश्योरेंस कवर, जो स्वास्थ कर्मी और पुलिस कोरोना कमांडोज की तरह कोरोना वायरस से देश के लिए लड़ रहे हैं, उन स्वास्थ कर्मियों

को विशेष लाभ दिया गया है. इस योजना के तहत यदि किसी स्वास्थ्य कर्मी की इस कोरोना वायरस से लड़ाई के दौरान जान चली जाती है तो उस स्वास्थ कर्मी के परिवार को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे.

'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना के तहत मजदूर चाहे देश के किसी भी कोने में हो, वहां के राशन डिपो से अपने हिस्से का अनाज ले सकता है. इसका फायदा उन सभी प्रवासी मजदूरों को मिल पाएगा जो रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं.

आठ करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. उन सभी प्रवासी मजदूरों को भी मुफ्त अनाज दिया जाएगा जिसके पास राशनकार्ड नहीं है.

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आठ करोड़ गरीब परिवार जो कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें अगले 3 महीनों तक मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया जाएगा.

20 करोड़ महिलाओं के पास जन धन अकाउंट है, उन्हें अगले 3 महीनों तक प्रतिमाह ₹500 दिए जाएंगे.

मनरेगा के मजदूरों की दिहाड़ी 182 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है.

रेहड़ी-पटरी पर काम करने वालों और घरों में काम करने वालों को 10 हजार रुपये तक का कर्ज मिल सकेगा. इसके लिए पांच हजार करोड़ रुपये की सहयोग राशि का ऐलान किया गया है.

आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा देश के किसानों की आय दोगुना करने के लिए मुख्यतः विभिन्न प्रकार की घोषणा की गई है. यह घोषणाएं कोरोना वायरस कोविड-19 की आपदा के मद्देनजर किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए की गई है. कृषि अवसंरचना की स्थापना के लिए 11 लाख करोड़ रुपये का कोष दिया जाएगा और किसान को सुविधात्मक कृषि उपज के माध्यम से मूल्य और गुणवत्तापूर्ण आश्वासन दिया जाएगा.

आत्मनिर्भर भारत के पाँच स्तंभ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने की रूपरेखा पेश करते हुए कहा कि नया भारत पांच मजबूत स्तंभों पर बनेगा. उन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना, प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली, जनसंख्या संरचना, मांग हमारे पांच मजबूत स्तंभ होंगे.

1. **अर्थव्यवस्था (Economy):**- एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो वृद्धिशील परिवर्तन नहीं बल्कि बड़ी उछाल लाए.

2. **आधारभूत संरचना (Infrastructure):**- भारत की सरकार आधारभूत संचरना में ज़रूरी निवेश के साथ सुधार करेगी जिससे कि स्वदेशी वस्तुएं बाहर से आने वाले उत्पादों का मुकाबला कर सकें.

3. **प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली (Technology operated system):**- आने वाले समय में ऑनलाइन सर्विस को बढ़ावा दिया जायेगा. 21वीं सदी में विकास के लिए भारत को टेक्नोलॉजी ड्रिवेन सिस्टम की आवश्यकता है. जिससे सरकारी काम में पारदर्शिता बढ़ जाये और लोगों का सरकार पर विश्वास स्थापित हो सके.

4. **जनसंख्या संरचना (Vibrant demography):**- भारत की जनसंख्या में 18 से 35 वर्ष की आयु के लोग सबसे ज्यादा है. इसलिए उन्हें जनसंख्या संरचना नाम से संबोधित किया है. हमारे पास युवा शक्ति का विशाल भंड़ार है. इस जनसंख्या के भार को मुनाफे में तब्दील करने के लिए हमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम देना होगा. उन्हें रोजगार तभी मिल सकता है. जब हम लोकल निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करेंगे और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देकर भारत का सामान दूसरे देशों तक पहुचांएगे.

5. **मांग (Demand):**- 137 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत देश में वस्तुओं की मांग की कोई कमी नहीं है. हमें इस भारी मांग का उपयोग अपने देश में निर्मित चीजों की बिक्री बढ़ाने के लिए करना है. हमें अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करना होगा.

निष्कर्ष:

स्वतंत्रता से लेकर आज तक भारत की विकास यात्रा शानदार रही है, चाहे क्षेत्र कोई भी हो. कृषि से लेकर अंतरिक्ष तक, संचार क्रांति से लेकर ट्रेन बनाने तक, हर काम में भारत धीरे-धीरे आत्मनिर्भर हो रहा है. नित नए-नए आविष्कारों और तकनीकी विकास को जन्म देकर, भारत ने विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई है.

एक ओर जहां भारत ने आत्मनिर्भर बनने के लिए अभूतपूर्व विकास का मार्ग अपनाया वहीं दूसरी ओर भारत अपने पूर्वजों के द्वारा दिए गए आदर्श मूल्यों, संस्कारों, समृद्ध परंपराओं को भी साथ लेकर चला है. भारत 'वसुधैव कुटुंबकम' की संकल्पना में विश्वास करता है. भारत को अगर एक महाशक्ति के रूप में उभरना है तो उसे हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना ही होगा.

एक ऐसा भारत, जो आत्मसात हो,
जिसके शब्दकोश में असंभव
जैसा न कोई बात हो,
एक ऐसा भारत हो, जो कौशल प्रधान हो,
जहां श्रमिक भी अभिमान हो,
अन्नदाता हर किसान हो,
जनजन का सम्मान हो.
एक ऐसा भारत हो,
जहाँ स्वदेशी ही विज्ञान हो,
जिसकी लोकल धरोहर का जगत में गुणगान हो,
एक ऐसा भारत हो, जो आत्मनिर्भर हो.

जयश्री गणेशराव भांगे
क्षे.का., नागपुर

Self Reliant India : It's need and effectiveness

As rightly said by Mahatma Gandhi that every one wants to be stronger and self sufficient but few are willing to take part in the work necessary to achieve worthy goals. At a time when the world is suffering from a deadly pandemic, India plans to convert this crisis into an opportunity and strengthen its fight by becoming **Atmanirbhar Bharat or Self - Reliant India.**

The term **Atmanirbhar Bharat or Self - Reliant India** was first coined by the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi during his address to the nation on May 12, 2020. He said we have to save ourselves from the virus and move forward at the same time. It is our dream and responsibility that the 21st century must belong to India. **'The development of each one is the identity of a self-reliant India'** we have to take steps of self reliance slowly and improve ourselves. There is only one way to achieve what India needs to be self sufficient. It is time to become vocal about our local products and make them global. The five pillars of **Atmanirbhar Bharat or Self - Reliant India are difined :-**

1. Economy - Quantum jumps not incremental changes.

2. Infrastructure - one that represents modern India.

3. System - Technology driven to fulfil dreams of 21st century.

4. Demography - Vibrant demography of the largest democracy that will strengthen our capacity further.

5. Demand - Full utilization of power of demand & supply chains.

The finance ministry on 11th Dec.2020 provided details of the progress achieved under schemes announced in the Atmanirbhar package. It noted that around 50% of the loans have been disbursed under the Rs. 3 lakh crore collateral free guaranteed loan schemes for business, as part of the package announced in May 2020.

'Loans worth Rs. 2.05 lakh crore have been sanctioned to over 80 lakh accounts, of which Rs. 1.58 lakh crore has been disbursed to over 40 lakh accounts.'

The scheme provides fully guaranteed and collateral-free loans for amounts up to 20% of outstanding loans to all business enterprises, individuals seeking credit for business purposes and MUDRA borrowers.

The government had announced a special re-finance facility of Rs. 30,000 crore sanctioned by NABARD during Covid - 19 to Regional Rural Banks(RRBs) and Cooperative Banks.

The ministry stated that 169.77 lakh Kisan Credit Card (KCC) holders with KCC limit of about Rs. 1.54 lakh crore have been covered under the Special KCC Saturation Drive for farmers. The Government has announced to cover 2.5 crore farmers under the Kisan Credit Card (KCC) scheme with a credit boost of Rs.2 lakh crore through a special saturation drive.

The finance ministry further noted that Rs.775 crore has been released to Small Industries Development Bank Of India (SIDBI) under the Rs.1500 crore interest subvention schemes application from the Micro Units Development and Refinance Agency (MUDRA) 'Of this Rs.206.73 crore was already disbursed to Member Lending Institutions (MLIs)'.

The ministry noted 39 proposals worth Rs.11,120 crore have been approved under the Rs.30,000 crore Special Liquidity Scheme for non banking finance companies (NBFCS) and housing finance companies (HFCs). The scheme was launched to improve the liquidity position of NBFCs/HFCs through a Special Purpose Vehicle (SPV) to avoid any potential systemic risks to the financial sector.

Under the Atmanirbhar Bharat Rojgar Yojana, the Government for two years will provide employee and employer contribution to the retirement fund for new hirees by business and entities, as announced by Labour Ministry.

The scheme till 2023 would entail an outgoing of Rs. 22,810 crore and would benefit around 58.5 lakh employees. The registration for the scheme will be effective from October 1, 2020 to June 30, 2021.

'Government will reimburse 24%, 12% each for employees and employers, for two years for all new formal jobs created in enterprises having up to 1000 employees between October 1st and till June 30th 2021,'

Finance minister Nirmala Sitharaman had announced in Nov the Atmanirbhar Package 3.0 containing a dozen measures to lift the economy hit hard by the covid-19 pandemic, including the scheme to generate employment.

The SBI research report had said almost 15-20 lakh employees will benefit from this scheme by March 2021, if one goes by the current trend based on EPFO data. The latest scheme is expected to aid hiring by companies and address the situation.

A similar scheme Pradhan Mantri Rojgar Prohatsan Yojana, launched in 2016 and valid till 2019, had created 1.21crore formal jobs.

The Finance ministry had approved Rs. 9,879 crore for capital expenditure for 27 states under the Atmanirbhar Bharat package.

All states except Tamil Nadu have availed benefits of the newly announced scheme for 'special assistance to states for capital expenditure'. Capital expenditure has a higher multiplier effect, enhancing the future productive capacity of the economy, which results in a higher rate of economic growth.

The scheme has received a good response from the state governments. An amount of Rs. 4,939.80 crore has already been released to states as the first instalment under the scheme. The capital expenditure projects have been approved in diverse sectors of economy such as health, rural development, water supply, irrigation transport, education and urban development. The scheme has three parts. Part I of the scheme covers the north-eastern region under this, Rs.200 crore allocated to seven north-eastern states. In view of higher population and geographical area, Assam has been allocated Rs.450 crore under the scheme. Part II of the scheme is for all other states not included in Part -I. An amount of Rs.7500 crore is earmarked for this. This amount has been allocated amongst these states in proportion to their share of central tax as per the interim award of the 15th finance Commission for 2020-21. The third part of the scheme is aimed at pushing various citizen-centric reforms in the states. Under this plan, an amount of Rs. 2000 crore has been set aside. This amount will be available only to those states who carry out at least three out of the four reforms specified by finance ministry regarding reform linked additional borrowing per person. Reforms are- one nation one ration card, ease of doing business reform, urban local body/utility reform and power sector reform.

Ministry of Finance & Corporate Affairs, announced under Atmanirbhar related to various sectors split under five tranches and giving detailed information about the steps being carried out by the Government.

Tranche-1 (Business including MSMEs) - The first measure being focused on was the idea of getting back to work i.e., facilitating employees and employers, business, especially MSMEs, to get back to production and workers back to gainful employment. Plans to strengthen Non-Banking Financial Companies(NBFCs), Housing Finance Companies (HFCs), Micro Finance Sector and Power Sector were also unfolded.

Pradhan Mantri Garib Kalyan Package (PMGKP was introduced in April 2020 in order to provide relief to underprivileged and help them fight the battle against COVID-19. The budget allocated to the scheme was Rs.1.70 lakh crore (US$2412 billion). The support was given in the form of: Insurance cover of Rs.50 lakh (US$ 70,932) per health worker. Five kg (Kilogram) wheat or rice per person and one kg pulses for each household will be given free to 80 crore people for the next three months. Rs.500 (US$7.09) to be transferred in the account of 20 crore women Jan Dhan account holders for the next three months. 8 crore poor families provided with gas cylinders, free of cost, for the next three months. MNREGA wage increased to Rs.202 (US$2.86) a day from Rs.182 (US$2.58) to benefit 13.62 crore families. Three crore poor senior citizens, poor widows and poor Divyang given ex-gratia of Rs. 1,000 (US$14.18). Front-loaded Rs. 2,000 (US$28.37) being paid to farmers under existing PM-KISAN to benefit 8.7 crore farmers.

Building and Construction Workers Welfare Fund allowed to be used to provide relief to workers.24 per cent of monthly wages to be credited into PF accounts for the next three months for wage-earners below Rs 15000 (US$212.79) per month in businesses having less than 100 workers. Five crore workers registered under Employee Provident Fund (EPF) to get non-refundable advances of 75 per cent of the amount or three months of the wages, whichever is lower, from their account.Limit of collateral free lending to be increased from Rs10 to Rs 20 lakh (US$ 0.01 TO 0.03 million) for Women Self Help Groups supporting 6.85 crore households. District Mineral Fund (DMF) to be used for supplementing and augmenting facilities of medical testing, screening etc.

Tranche-2 (Poor, including migrant and farmers) - Migrant workers are being provided additional free food

grains and chana for two months in the State/Union Territory they are stranded in at present. Government has allocated Rs. 3500 crore and also plans to introduce affordable rental housing complexes in order to provide social security and quality life to migrant labour, urban poor, and students etc. Government will also provide relief to small businesses under MUDRA-Sishu loans by providing interest subvention of 2 percent for one time payees for a period of 12 months. Street vendors will also get easy access to credit under a special scheme that will provide them initial working capital up to Rs.1000 for each enterprise. Urban and rural vendors doing business in the adjoining urban areas will be covered under the scheme. Around 50 lakh street vendors are expected to benefit and credit of Rs.5000 crore would flow to them.In order to provide a boost to the housing sector and increase the demand for steel, cement, transport and other construction material, Government has extended Credit Linked Subsidy Scheme for middle income group (annual income between Rs. 6 and 18 lakh) up to March 2021. Around 2.5 lakh middle income families are estimated to benefit.

Employment for Tribals via Rs 6000 crore using Compensatory Afforestation Management & Panning Authority (CAMPA) Funds. This will for create job opportunities in urban, semi-urban & rural areas for afforestation and plantation works. National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) will provide additional re-finance support of Rs.30000 crore for meeting crop loan requirement of Rural Cooperative Banks. Government is also investing Rs 2 lakh crore in the farm sector and is providing concessional credit to PM-KISAN beneficiaries through Kisan Credit Cards. The scheme will also include fishermen and animal husbandry farms.

Tranche-3 (Agriculture) - During the lockdown period, Minimum Support Price (MSP) purchases of amount more than Rs.74,000 crore, PM KISAN fund transfer of Rs. 18,700 crore and PM Fasal Bima Yojana claim payment of Rs 6,400 crore have been made. Government plans to strengthen infrastructure logistics and capacity building. It is providing Rs.1 lakh crore financing facility for funding Agriculture Infrastructure Projects at farm gate and aggregation points (Primary Agricultural Cooperative Societies, Farmers Producer Organizations, Agriculture Entrepreneurs, start-ups etc.)

Tranche-4 (New Horizon of Growth)- Coal Sector : Government plans to focus on evacuation of enhanced Coal India Limited's (CIL) target of 1 billion tonnes coal production by 2023-24.

Mineral Sector : In order to increase efficiency in mining and production 500 mining blocks would be offered through an open and transparent auction process.

Defence Sector: Government has increased the Foreign Direct Investment (FDI) in Defence manufacturing under automatic route from 49 percent to 74 percent. 'Make in India' for Self-Reliance in Defence Production will be promoted by notifying a list of weapons/ platforms & for ban on import with year wise timelines, Indigenisation of imported spares and separate budget provisioning for domestic capital procurement.

Tranche-5 (Government Reforms and Enablers) - Employment Generation: Mahatma Gandhi Employment Guarantee Act (MGNREGS) has been awarded Rs. 40,000 crore. including returning migrant workers in monsoon season as well.

Healthcare Sector : Strengthening lab network and surveillance-integrated public health labs in all districts and blocks. The National Digital Health Mission plans to prepare India for any future pandemics.

Education Sector: Government has launched PM eVIDYA, a programme for multi-mode access to digital/online education. New National Curriculum and Pedagogical framework for early childhood, schools and teachers will be launched, integrated with global and 21st century skill requirements.

Ease of Doing Business for Corporate : Lower penalties for all defaults for Small Companies, One-person Companies, Producer Companies and Start-ups.

Walmart on 10th December 2020 announced that it was tripling its commitment to India by sourcing $10 billion worth of goods from the country annually by 2027 to support its 'Make in India' initiative. 'As an international retailer that brings value to customers and communities worldwide, Walmart understands that local entrepreneurs and manufacturers are vital to the success of the global retail sector

The world is now looking towards humanity centric globalization. The Prime Minister praised India's ancient culture saying that the wisdom of age old principles such as Vasudha Kutumbakam and harmony with nature ensure that world progress is central to India's conception of progress and expressed confidence that Atmanirbhar Bharat could lead the way.

Ajitkumar
R.O., Sambalpur

SELF RELIANT INDIA : A RAY OF HOPE

Unlike every crisis, the present pandemic of COVID-19 has changed various possibilities into opportunities. So far, India has acted profoundly to combat with the present pandemic in comparison to both developed and developing nations. The major difference between the Global Financial Crisis 2008 (GFC) and present COVID 19 pandemic is a translation of challenges from financial system to Economy and vice versa. As the prior crisis was meant for translating financial problems to the global economy the later is due to spillover effect of supply chain disruption on financial system. We have not observed a major impact of GFC on Indian Financial System due to insulated regulation of Central Bank which had helped in developing the financial immunity and resilience towards the crisis. However the present situation is completely antagonistic as both demand and supply shock has disrupted the global economic value chain. As the impact is still under evaluation but its effect cannot be undermined for a long period. Recovery may be either 'V-shape' or 'U-shape' but economic drivers are showing green shoots mainly due to fiscal and monetary stimulus as extended by Central Government and Reserve Bank of India (RBI) respectively. RBI acted proactively and became successful in managing both ends of the yield curve. India is uniquely positioned in the global value chain as its fragmented presence in aforesaid spectrum with available demographic dividend from rest of the world. In the extant scenario, 'Self reliant India' or 'Atmanirbhar Bharat' is a ray of hope to bridge the gap between untapped potential to leverage potential and has forced multiplier effect for global economy. This 'Self reliant India' has given impetus to 'vocal for local' in order to support the indigenous product and services.

Atmanirbhar Bharat Abhiyaan or Self-reliant India campaign is the vision of new India envisaged by the Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi. On 12 May 2020, our PM raised a clarion call to the nation giving a kick start to the Atmanirbhar Bharat Abhiyaan (Self-reliant India campaign) and announced a Special economic and comprehensive package of Rs 20 lakh crores - equivalent to 10% of India's GDP - to fight COVID-19 pandemic in India. The aim is to make the country and its citizens independent and self-reliant in all senses. He further outlined five pillars of Aatma Nirbhar Bharat - economy, Infrastructure, System, Vibrant Demography and Demand. Finance Minister further announced Government Reforms and Enablers across Seven Sectors under Aatmanirbhar Bharat Abhiyaan. The government took several bold reforms such as Supply Chain Reforms for Agriculture, Rational Tax Systems, Simple & Clear Laws, Capable Human Resource and Strong Financial System.

Highlights of key measures are as under:

Government Reforms (Policy Highlights) : (1) **Increase in borrowing limits:** The borrowing limits of state governments were increased from 3% to 5% of Gross State Domestic Product (GSDP) for the year 2020-21. (2) **Privatization of Public Sector Enterprise (PSEs):** To minimize wasteful administrative costs, number of enterprises in strategic sectors will ordinarily be only

one to four; others will be privatized/merged/brought under holding companies.

Measures for businesses (including MSMEs) (Financial Highlights) : (1) **Collateral free loans for businesses:** MSMEs can borrow upto 20% of their entire outstanding credit as on February 29, 2020 from banks and NBFCs. Borrowers with up to Rs 25 Crore outstanding and Rs 100 Crore turnover were eligible for such loans. (2) **Corpus for MSMEs:** A fund of funds with a corpus of Rs 10,000 Crore to be set up for MSMEs. (3) **Subordinate debt for MSMEs:** Under the scheme, promoters of MSMEs had been given debt from banks, which infused into the MSMEs as equity. The government has facilitated Rs 20,000 Crore of subordinate debt to MSMEs. (4) **Schemes for NBFCs:** A Special Liquidity Scheme was announced under which Rs 30,000 Crore of investment to be made by the government in both primary and secondary market transactions in investment grade debt paper of Non-Banking Financial Companies (NBFCs)/Housing Finance Companies (HFCs)/Micro Finance Institutions (MFIs). The existing Partial Credit Guarantee Scheme (PCGS) was extended to partially safeguard NBFCs against borrowings of such entities. (5) **Employee Provident Fund (EPF):** Under the PM Garib Kalyan Yojana, the government paid 12% of employer and 12% of employee contribution into the EPF accounts of eligible establishments. (6) **Statutory PF contribution:** Statutory PF contribution of both the employer and employee has been reduced from 12% to 10% each for all establishments covered by EPFO for next three months. (7) **Street vendors:** Bank credit had been provided to each vendor for an initial WC of up to Rs 10,000.

Policy Highlights : (1) **Expediting payment of dues to MSMEs:** Payments due to MSMEs from the government and CPSEs to be released within 45 days. (2) **Insolvency resolution:** A special insolvency resolution framework for MSMEs under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 to be notified. (3) **Disallowing global tenders:** To protect Indian MSMEs from competition from foreign companies, global tenders of up to Rs 200 crore will not be allowed in government procurement tenders. (4) **Reduction in TDS and TCS rates:** Tax Deduction at Source (TDS) for the non salaried specified payments made to residents and Tax Collected at Source (TCS) was reduced by 25% from the existing rates. (5) **Ease of doing business for corporate**

Legislative Highlights : (1) **Definition of MSME:** The investment limit has been increased from Rs 25 lakh to Rs 1 Crore for micro enterprises, from Rs 5 Crore to Rs 10 Crore for small enterprises, and from Rs 10 Crore to Rs 20 Crore for medium enterprises. (2) **Initiation of insolvency proceedings:**

- Minimum threshold to initiate insolvency proceedings have been increased from one lakh rupees to one crore rupees.
- Suspension of fresh initiation of insolvency proceedings.
- COVID-19 related debt has been excluded from the definition of 'default'.

Agriculture and Allied sectors (Financial Highlights) : (1) **Concessional Credit Boost to farmers:** Farmers were provided institutional credit facilities at concessional rates through Kisan Credit Cards. (2) **Agri Infrastructure Fund:** A fund of one lakh Crore rupees to be created for development of agriculture infrastructure projects at farm-gate and aggregation points. (3) **Emergency working capital for farmers:** An additional fund of Rs 30,000 Crore to be released as emergency working capital for farmers. (4) **Support to fishermen:** Under this scheme, Rs 11,000 Crore to be spent on activities in Marine, Inland fisheries and Aquaculture and Rs 9,000 Crore has been spent for developing infrastructure. (5) **Animal Husbandry infrastructure development:** An Animal Husbandry Infrastructure Development Fund of Rs 15,000 Crore to be set up, with the aim of supporting private investment in dairy processing, value addition, and cattle feed infrastructure. (6) **Employment push using CAMPA funds:** The government has announced the approval plans worth Rs 6,000 Crore under the CAMPA to facilitate job creation for tribals/adivasis. (7) **Amendments to the Essential Commodities Act:** Commodities covered under the amended Act include edible oil and seeds,

pulses, sugarcane and its products, and rice paddy.

Legislative Highlights : (1) **Agriculture marketing reforms:**

• Adequate choices to farmers to sell their produce at remunerative prices. • Barrier free inter-state trade. • A framework for e-trading of agriculture produce. (2) **Agriculture Produce Pricing and Quality Assurance:** A facilitative legal framework has been created to enable farmers to engage with processors, aggregators, large retailers, and exporters in a fair and transparent manner.

Migrant Workers (Policy Highlights) : (1) **One Nation One Card:** The scheme has been introduced the inter-state portability of access to ration for migrant labourers. (2) **Free food grain Supply to migrants:** 5 kg of grains per person and 1 kg of chana per family had been provided to migrant workers. (3) **Affordable Rental Housing Complexes (ARHC) for Migrant Workers / Urban Poor:** The migrant labour/urban poor has been provided living facilities at affordable rent under Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY).

Civil Aviation (Policy Highlights) : (1) **Efficient airspace management:** Restrictions on utilisation of the Indian Air Space were eased so that civilian flying becomes more efficient. (2) **Public Private Partnership (PPP) model for airports:** World-class airports will be built through PPP model. In the first round, the Airport Authority of India (AAI) had awarded three airports (Ahmedabad, Lucknow and Mangaluru) out of six bid for operation and maintenance on PPP basis.

Defence (Policy Highlights) : FDI limit in defence manufacturing under automatic route has been increased from 49% to 74%.

Energy (Financial Highlights) : (1) **Liquidity support for distribution companies (discoms):** A liquidity support of Rs 90,000 Crore has been provided to power discoms. (2) **Coal evacuation:** Rs 50,000 Crore has been spent on infrastructure development for evacuation of coal.

Housing (Financial Highlights) : **Credit Linked Subsidy Scheme for Middle Income Group (MIG):** The Credit Linked Subsidy Scheme for Middle Income Group (annual income between Rs 6 lakh and Rs 18 lakh) has been extended by one year up to March 2021.

Policy Highlights : **Support to real estate sector:** An extension of six months has been given on registration and completion dates of all registered projects expiring on or after March 25, 2020 without individual applications.

Social Sector (Policy Highlights) : (1) **Public Health:** The investment in public health has been increased along with investment in grass root health institutions of urban and rural areas. (2) **Public Health:** The investment in public health has been increased along with investment in grass root health institutions of urban and rural areas. (3) **Public Health:** The investment in public health has been increased along with investment in grass root health institutions of urban and rural areas. (4) **Allocation for MGNREGS:** To help boost rural economy, an additional Rs 40,000 Crore has been allocated under MGNREGS. (5) **Viability Gap Funding:** Viability Gap Funding (VGF) for social infrastructure projects was increased by up to 30% of the total project cost.

Conclusion:

The Central Government and RBI both are continuously watching the impulse of the economy and are ready to take all steps in order to support the growth of economy. The measures taken by them are in line of self reliant India campaign and a ray of hope to build a better tomorrow. As Mahatma Gandhi said – "Everyone wants to be strong and self sufficient but few are willing to put in the work necessary to achieve worthy goals."

A holistic effort has been put forward to focus on development and capacity building of the nation and self reliant India campaign is a ray of hope in this direction.

Paritosh Kumar
Treasury Dept., Co.

आत्मनिर्भर भारत में बैंकों का योगदान

समय के साथ बदलाव इस जगत का नियम है. जब-जब मानव समाज के सामने गंभीर चुनौतियां आती हैं. मानव ने मिल-जुलकर उन चुनौतियों का सामना किया है तथा हर कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की है. कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है. यह बिल्कुल ही सच है तथा हमने वर्तमान परिस्थिति में इस तथ्य को व्यवहारिक रुप से महसूस किया गया है.

अभी भी कोविड-19 के प्रभाव से दुनिया चिंतित है. परंतु वैश्विक महामारी कोविड-19 के विस्तार के साथ ही लॉक डाउन के कारण स्थानीय सामानों की जरुरतों को समझा गया तथा आत्मनिर्भर की दिशा में प्रयास की बात की जाने लगी. भारत सरकार, राज्य सरकारें, विभिन्न बैंकों द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिए एमएसएमई, कृषि आधारित परियोजनाओं तथा अन्य जरुरत की वस्तुओं के उत्पादन हेतु स्थानीय स्तर पर मशीनरी कारखाना स्थापित करने की योजनाओं हेतु वित्तीय सहायता/ऋण प्रदान कर संभावित उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है. इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के दिशानिर्देशों के साथ सभी बैंक निरंतर इस योजना को फलीभूत करने हेतु प्रयासरत हैं.

लॉक डाउन के दौरान देश के संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने हेतु आत्मनिर्भरता पर फोकस करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया. इसके बाद भी उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि आज हम अरबों रुपए का सामान आयात करते हैं. यदि इन सामानों का उत्पादन स्थानीय स्तर पर होने लगे तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी सुरक्षित रहेगा तथा इन सामानों हेतु दुसरों पर निर्भरता भी समाप्त हो जाएगी. यदि देखा जाए तो ऊर्जा से संबंधित उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, खाद्य तेल अन्य सामान्य वस्तुएं एवं खनिज आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमें अधिकांश वस्तुओं को आयातित करना पड़ता है. यदि हम प्रयास करें तथा नियमित रुप से कठिन परिश्रम के साथ उद्यम का संचालन करें तो आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में हम काफी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं.

हम यहां आप सभी को 70 के दशक को याद दिलाना चाहेंगे जब भारत में दूध की कमी, एक व्यापक समस्या थी. देश में दूध का उत्पादन इतना कम था कि इसकी उपलब्धता प्रति व्यक्ति 110 ग्राम ही था. भारत में दूध का बड़े पैमाने पर आयात होता था. इसी समय भारत के डेयरी वैज्ञानिक डॉ. वर्गिस कुरियन द्वारा देश भर में दुग्ध सहकारी समितियों के सफल अमूल मॉडल को दोहराने के लिए हितधारकों, नीति निर्माताओं और राजनीतिक नेतृत्व द्वारा एक प्रतिबद्धता व्यक्त की गई. पूरे देश में ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से श्वेत क्रांति चलाई गई जिसका नतीजा हम सबके सामने है. आज भारत पूरे विश्व में दूध उत्पादक देशों की श्रेणी में अव्वल बना हुआ है. आज भारत दूध उत्पादन में न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि दूध एवं डेयरी उत्पादों का निर्यात भी कर रहा है.

मेरे कहने का मतलब है कि आत्मनिर्भरता एक प्रक्रिया है जिसे हासिल करने के लिए हमें निरंतर परिश्रम तथा प्रयास करने की आवश्यकता है. वर्तमान परिस्थिति भी कोविड 19 के कारण हमारे सामने चुनौती के रुप में उत्पन्न हुआ है. विश्वव्यापी बाजार बंद होने के कारण कई आयातित वस्तुओं की कमी होने लगी. ऐसे में यह महसूस किया जाने लगा कि हमें हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था में हमें किसी के आसरे की जरुरत न पड़े.

हमने कोविड-19 में यह भी देखा है कि शुरुआती समय में पूरे देश में मास्क, पी.पी.ई. किट तथा सैनेटाइजर की कमी थी. परंतु भारत ने यह ठाना तथा बहुत कम समय में मास्क, किट तथा सैनेटाइजर की कमी को हमने पूरा कर लिया. आज स्थिति ऐसी है कि इन सामानों का निर्यात भी किया जाने लगा है. हमने यह दुनिया को दिखाया कि आत्मनिर्भर होने में भारत कितना सक्षम है.

भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक सतत प्रक्रिया के तहत पूरे देश में उद्योगों के जाल बिछाने की जरुरत है. यह उद्योग कुटीर, लघु, सूक्ष्म या फिर बृहद भी हो सकते हैं. पूरे देश में कारखानों का जाल बिछे, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना चाहिए. हम यह भी जानते हैं कि उद्यम, उद्यमियों तथा उद्योग की स्थापना तथा इसके नियमित परिचालन हेतु धन की आवश्यकता होगी. आर्थिक मदद तथा वित्तीय सहायता एक ऐसा समर्थन होता है जिसके माध्यम से आत्मनिर्भरता के लिए नियोजित कार्यक्रमों को सार्थक बल मिलता है. बैंक एक ऐसी संस्था है जो उद्यम, उद्यमियों तथा उद्योगों के लिए आर्थिक मदद एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु सक्षम है.

बैंकों की भूमिका : उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता : हम जानते हैं कि किसी देश की आत्मनिर्भरता वहां के उद्योगों की स्थिति, सेवाएं तथा प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करता है. उद्योगों की स्थापना हेतु अत्यधिक आर्थिक मदद की जरुरत होती है. यदि हम बैंकों द्वारा प्रदत आर्थिक मदद की बात करें तो आज सभी बैंक कुटीर, लघु, सूक्ष्म एवं वृहद उद्योगों को स्थापित करने

में आगे बढ़कर काम कर रहे हैं. यदि हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ही बात करें तो इसके माध्यम से पूरे देश में एमएसएमई से संबंधित उद्यमों को लगातार प्रश्रय दिया जा रहा है. सभी बैंककर्मी भारत सरकार, राज्य सरकारें, भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड के निर्देशानुसार नए उद्यमियों को स्थापित करने में मदद कर रहे हैं. उन्हें आर-सेटी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा उद्योग स्थापना हेतु हर प्रकार की आवश्यक आर्थिक मदद प्रदान की जा रही है. बैंकों द्वारा ग्राम स्तर से लेकर बड़े आधार पर जरुरतमदों को सहयोग किया जा रहा है.

इन मदद को आज के परिप्रेक्ष्य में एक उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है तथा इसका परिणाम भी सार्थक प्रतीत हो रहा है. यदि हम उदाहरण के तौर पर देखें तो कोविड-19 महामारी के संक्रमण के साथ हमारे देश में पी.पी.ई. किट तथा सैनेटाइजर की उपलब्धता काफी कम थी परंतु आवश्यकता के अनुसार बैंकों की मदद एवं सरकार की पहल के परिणामस्वरुप पूरे देश में पी.पी.ई. किट एवं सैनेटाइजर भरपूर मात्रा में उपलब्ध होते दिख रहे हैं या यूं कहें कि हम पी.पी.ई. किट एवं सैनेटाइजर के क्षेत्र में कमोबेश आत्मनिर्भर हो गए हैं.

कृषि क्षेत्र : हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है. हमारे देश की 70% जनता आज भी कृषि पर आश्रित है. वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बैंकों की पहुंच अब गांव-गांव तक हो चुकी है. ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत बैंक शाखाएं कृषि आधारित ग्राहकों को दिन-रात आर्थिक मदद प्रदान कर रही है. कृषि उपकरणों तथा कृषि के लिए आवश्यक कच्चे सामग्रियों के लिए बैंक कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है. इससे एक तरफ किसानों की आय में वृद्धि होने की उम्मीद है तो दूसरी तरफ भारतीय जीड़ीपी में कृषि क्षेत्र की भागीदारी बढ़ना निश्चित है. यहां यह भी कहना उचित होगा कि कृषि क्षेत्र तथा कृषक हमारे देश के अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी हैं. बैंकों के द्वारा कृषकों तथा कृषि क्षेत्र में प्रदत वित्तीय सहायता आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण कदम है तथा यह सम्पूर्ण रुप से भारतीय आत्मनिर्भरता की दिशा में सकारात्मक कदम है.

खुदरा तथा सेवा क्षेत्र : हम जानते हैं कि खुदरा एवं सेवाएं क्षेत्र हमारे देश की अर्थव्यवस्था में प्रमुख स्थान रखता है. इन क्षेत्रों में उछाल तथा वृद्धि सीधे रुप से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को परिलक्षित करता है. खुदरा क्षेत्र देश की आर्थिक प्रगति की भी पहचान है तो सेवा क्षेत्र हमारे जीडीपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है. बैंकों द्वारा खुदरा क्षेत्र में वित्तीय सहायता कर इस क्षेत्र को मजबूती प्रदान की जा रही है तो सेवा क्षेत्र में उद्यमियों को लगातार मदद किया जा रहा है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने विभिन्न उत्पादों के माध्यम से नागरिकों को खुदरा क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र में आर्थिक मदद पहुंचा कर उन्हें सहायता प्रदान कर रहा है. हम उम्मीद कर सकते हैं कि बैंकों की यह भूमिका भारत के आत्मनिर्भरता के लिए मिसाल कायम करेगा तथा देश आत्मनिर्भरता की राह पर मजबूती से आगे बढ़ सकेगा.

महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन प्रदान करना : महिलाएं हमारे देश की आबादी की लगभग 50% भागीदारी रखती हैं. जब तक हमारे देश की महिलाएं स्वावलंबी नहीं होंगी तथा अपने पैरों पर खड़ी नहीं होंगी तब तक भारत का आत्मनिर्भर होना बहुत ही मुश्किल है. आज हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना के माध्यम से जुड़ी देश की आधी आबादी को केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा विभिन्न बैंकों द्वारा सीधे तौर पर मदद दी जा रही है. देश में महिलाओं के द्वारा स्थापित विभिन्न जीविका समूहों को हर संभव वित्तीय मदद प्रदान की जा रही है. महिलाएं अपने बल पर उद्योगों, व्यवसाय तथा अपनी पसंद के पेशों की स्थापना कर रही हैं तथा बैंकों से जुड़कर वित्तीय सहायता प्राप्त कर अपने घर को आर्थिक मदद पहुंचा रही हैं या यूं कहें तो वह आर्थिक रुप से स्वावलंबी बन रही हैं तथा अपने परिवार को आर्थिक सहायता पहुंचाकर प्रति व्यक्ति आय में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं. यह सब बैंकों द्वारा दी जाने वाली आर्थिक एवं वित्तीय मदद के उपरांत ही संभव हो पा रहा है.

विद्यार्थियों को शिक्षा में मदद : आज बैंकों के द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण प्रदान कर उन्हें कुशल तथा शिक्षा के लिए अनुकूल बनाया जा रहा है. बैंकों के द्वारा प्रदत शिक्षा ऋण के बदौलत छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तथा अपने पैरों पर खड़ा होकर उद्यम और व्यवसाय भी कर रहे हैं. यहां तक कि उनकी उपस्थिति विदेश स्थित प्रतिष्ठित संस्थानों तक दर्ज की जा रही है. बैंकों द्वारा प्रदत यह वित्तीय मदद देश के आत्मनिर्भर अभियान की दिशा में सार्थक कदम प्रतीत हो रहा है.

कुल मिलाकर कहा जाए तो आत्मनिर्भर भारत, एक बहुत ही विशाल मिशन है जिसकी प्राप्ति हेतु सम्पूर्ण देशवासियों तथा संस्थानों का अपना दायित्व होता है. ऐसे में यदि हर संस्थान अपने दायित्व का निर्वहन सुनिश्चित करें तो हमारा देश अवश्य आत्मनिर्भर बनकर वैश्विक शक्ति के रुप में उभरेगा. कहा जाता है कि विपत्ति की स्थिति अवसर की भी स्थिति होती है. विपत्तिकाल में नेतृत्वकर्ता अवसर की चाह रखता है. उभरता भारत एक नया भारत है जो हर चुनौती को अवसर में बदलने में समर्थ है. इस अवसर को हासिल कर उसे सशक्त बनाने में बैंकों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है. हमें उम्मीद है कि आज का भारत सशक्त भारत, समर्थ भारत तथा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में चल पड़ा है जहां बैंक अपनी भूमिका के साथ आगे बढ़ रहे हैं. हमारा आह्वान रहेगा कि ''चलो एक ऐसे भारत का भविष्य देखें जो आत्मनिर्भर भारत हो तथा भारतवासी को गौरवान्वित करने वाला भारत हो. जैसा भारत का अतीत रहा है वर्तमान भी उतना ही स्वर्णमयी हो.''

हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय भारत का होगा तथा पूरी दुनिया में अपने प्रयास के द्वारा आत्मनिर्भर की पहल का उदाहरण प्रस्तुत करेगा. आत्मनिर्भर भारत बनाने में बैंकों तथा बैंककर्मियों की भूमिका को भी स्वर्णिम अक्षरों में उल्लिखित किया जाएगा.

सुमित कुमार सिंह
क्षे.का., पटना

LIBERALIZATION, GLOBALIZATION AND PRIVATIZATION

India entered in the process of globalization by 1991, when there was a severe economic crisis in the country. To overcome the economic crises, India approached the International Monetary Fund for financial assistance. IMF granted assistance on the condition that India would make some structural changes and reforms in the Economy. In 1994, 124 countries along with India signed the Dankel Proposal, giving a final pass to the proposal. The World Trade Organization was established in January 1995. The member countries involved themselves in globalization through WTO. These reforms and changes were broadly classified into three areas: Liberalization, Privatization and Globalization (LPG). It included withdrawal of government control from the market, privatising public sector organizations and reducing export subsidies and import barriers to enable free trade. India signed GATT too and opened up its economy to the world market. Initially this process was restrained by the barriers to trade and investment but after liberalizing it, the pace of globalization speeded up. Liberalization, Privatization and Globalization were positive and a development based policy was implemented by the Government in the year 1991.

Liberalization : Liberalization refers to the slackening of government regulations. The economic liberalization in India denotes the continuing financial reforms which began since July 24, 1991. Liberalization means elimination of state control over economic activities. It implies greater autonomy to the business enterprises in decision-making and removal of government interference. It was believed that the market forces of demand and supply would automatically operate to bring about greater efficiency and the economy would recover.

Objectives : ➢ To boost competition between domestic businesses. ➢ To promote foreign trade and regulate imports and exports. ➢ Improvement of technology and foreign capital. ➢ To develop a global market of a country. ➢ To reduce the debt burden of a country. ➢ To unlock the economic potential of the country by encouraging the private sector and multinational corporations to invest and expand. ➢ To encourage the private sector to take an active part in the development process. ➢ To reduce the role of the public sector in future industrial development. ➢ To introduce more competition into the economy with the aim of increasing efficiency.

Reforms under Liberalization : ➢ Deregulation of the Industrial Sector. ➢ Financial Sector Reforms ➢ Tax Reforms ➢ Foreign Exchange Reforms ➢ Trade and Investment Policy Reforms ➢ External Sector Reforms ➢ Foreign Exchange Reforms ➢ Foreign Trade Policy Reforms

Impacts of Liberalization in India:

Positive changes of liberalization:

1. Free flow of capital: Liberalization has improved flow of capital into the country which makes it inexpensive for the companies to access capital from investors. **2. Stock Market Performance:** Generally, when a country relaxes its laws, taxes, the stock market value also rises. **3. Political Risks Reduced:** Liberalization policies in the country lessen political risk to investors. **4. Diversification for Investors:** In a liberalized economy, Investors get benefit by being able to invest a portion of their portfolio into a diversifying asset class. **5. Impact on Agriculture:** In the area of agriculture, the cropping patterns have undergone a huge modification, but the impact of liberalization cannot be properly measured. It is observed that there are still all-pervasive government controls and interventions starting from production to distribution for the produce.

Negative changes of liberalization:

Destabilization of the economy: Tremendous redistribution of economic power and political power leads to Destabilizing effects on the entire Indian economy.

Threat from Multinationals: On account of liberalization, competition has increased for the Indian firms. Multinationals have turned out to be a threat to local Indian Firms.

Mergers and Acquisitions: Acquisitions and mergers are increasing day-by-day. In cases where small companies are being merged by big companies, the employees of the small companies may require exhaustive re-skilling.

Impact of FDI in Banking sector: Foreign direct investment allowed in the banking and insurance sectors

resulted in decline of Government's stake in banks and insurance firms.

Privatization : Privatization refers to the participation of private entities in businesses and services and transfer of ownership from the public sector (or government) to the private sector as well. The term for privatization is Disinvestment.

Objectives : ➢ Providing strong momentum to the inflow of FDI. ➢ Aims at providing a strong base to the inflow of FDI. ➢ Increased inflow of FDI improves financial strength of the economy.

Ways of Privatization: Government companies are transformed into private companies in two ways:

a) Transfer of Ownership

b) Disinvestment

However, there are six methods of Privatization:

➢ The public sale of shares ➢ Public auction ➢ Public tender ➢ Direct negotiations ➢ Transfer of control of State or controlled enterprises ➢ Lease with a right to purchase

Positive changes of privatization:

1. Improved efficiency: The main argument for privatization is that private companies have a profit incentive to cut costs and be efficient. Since privatization, companies such as BT, and British Airways have shown improved efficiency and higher profitability. **2. Lack of political interference:** It is argued that governments make poor economic managers. They are motivated by political pressures rather than sound economic and business sense. **3. Short term view:** A government may think only in terms of the next election. Therefore, they may be unwilling to invest in infrastructure improvements which will benefit the firm in the long term. **4. Shareholders:** It is argued that a private firm has pressure from shareholders to perform efficiently. If the firm is inefficient then the firm could be subject to a takeover. **5. Increased competition:** Often privatization of state-owned monopolies allows more firms to enter the industry and increase the competitiveness of the market.

Negative changes of Privatization:

1. Natural monopoly: A natural monopoly occurs when the most efficient number of firms in an industry is one. Therefore, in this case, privatization would just create a private monopoly which might seek to set higher prices and exploit consumers. **2. Public interest:** There are many industries which perform an important public service, e.g., health care, education and public transport. In these industries, the profit motive shouldn't be the primary objective of firms and the industry. **3. Government loses out on potential dividends:** Many of the privatized companies are quite profitable. This means the government misses out on their dividends, instead it goes to wealthy shareholders. **4. Problem of regulating private monopolies :** Privatization creates private monopolies. **6. Short-termism of firms :** The government being motivated by short term pressures, this is something private firms may do as well.

Globalization: The concept of globalization has been explained by the IMF (International Monetary Fund) as 'the growing economic interdependence of countries worldwide through increasing volume and variety of cross border transactions in goods and services and of international capital flows and also through the more rapid and widespread diffusion of technology.'

Positive changes of Globalization:

1. Increase in Employment: With the opportunity of Special Economic Zones (SEZ), there is an increase in the number of new jobs availability. **2. Increase in Compensation:** After Globalization, the level of compensation has increased as compared to domestic companies due to the skill and knowledge a foreign company offers. **3. High Standard of Living:** With the outbreak of Globalization, in the Indian economy the standard of living of individuals have increased.

Negative changes of Globalization:

1. Inequality: Globalization has been linked to rising inequalities in income and wealth. Evidence for this is the growing rural–urban divide in countries such as China, India and Brazil. **2. Inflation:** Strong demand for food and energy has caused a steep rise in commodity prices. Food price inflation (known as agflation) has placed millions of the world's poorest people at great risk. **3. Vulnerability to external economic shock:** National economies are more connected and interdependent; this increases the risk of contagion i.e. an external event somewhere else in the world coming back to affect you has risen/making a country more vulnerable to macro-economic problems elsewhere. **4. Trade Imbalances:** Global trade has grown but so too have trade imbalances. Some countries are running big trade surpluses and these imbalances are creating tensions and pressures to introduce protectionist policies such as new forms of import control. **5. Unemployment:** Concern has been expressed by some that capital investment and jobs in advanced economies will drain away to developing countries as firms switch their production to countries with lower unit labour costs. **6. Standardization:** Some critics of globalization point to a loss of economic and cultural diversity as giant firms and global multinational brands dominate domestic markets in many countries.

Ankita Bajpai
R.O., Kanpur

आत्मनिर्भर भारत - एक स्वतंत्र उड़ान

किसी ने सच ही कहा है कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. जब किसी चिड़िया का बच्चा अपनी पहली उड़ान भरता है तो उसे अपने हुनर से ज्यादा हौसले की आवश्यकता होती है. एक बार अपने हौसले के साथ यदि उसने आसमान नाप लिया तो पूरा आसमान उसकी मुट्ठी में होता है. स्वनिर्भरता सहित आत्मविश्वास की उड़ान का तो अंदाज ही कुछ निराला होता है. तभी तो कोई भी परिंदा पिजड़े में कैद नहीं होना चाहता है.

तथ्य किसी पक्षी, व्यक्ति या किसी संस्था तक सीमित नहीं होता है. एक संप्रभु देश भी अपने विकास हेतु स्वतंत्र उड़ान चाहता है. प्रत्येक शांतिप्रिय देश की यही आकांक्षा होती है कि बिना किसी रोकटोक के निर्बाध गति से प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकें. परंतु उस देश की उड़ान पूर्णतया उसकी आत्मनिर्भरता की स्थिति पर आश्रित होती है. आत्मनिर्भरता का तात्पर्य किसी पर निर्भर न होकर खुद पर निर्भर होना होता है. यदि देश आत्मनिर्भर होगा तो वह प्रत्येक परिस्थिति में बिना किसी दबाव के बाहरी खतरों का डट कर सामना कर सकता है. इसके विपरीत यदि उसका व्यापार में घाटा ज्यादा है और वह सामान्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिए अन्य देशों पर निर्भर है तो उसके मार्ग में अनेकों बाधाएँ आती रहेंगी.

आजादी के बाद भारत ने अनेकों पड़ावों को पार करते हुए विकास पथ पर अनगिनत कदम बढ़ाएं हैं. बैलगाड़ी से लेकर चंद्रयान तक का सफर अपने दम पर तय किया है. तकनीकी विकास के साथ आज भारत विश्व शक्ति बनने की कगार पर पहुँच गया है. परंतु, विश्व शक्ति बनने की अनिवार्य शर्त आत्मनिर्भरता होती है और आत्मनिर्भरता के पैमानों पर आज भी हम पूरी तरह से खरे नहीं उतरते.

आज जब पूरा विश्व कोरोना संकट से जूझ रहा है, ऐसे में भारत कोरोना के साथ-साथ बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, मजदूरों का पलायन, आतंकवाद व सीमा पर तनाव आदि अनेकों समस्याओं से जूझ रहा है. इसी बीच भारत व चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के उपरांत प्रत्येक भारतवासी आक्रोशित है. चीनी सामानों के बहिष्कार की मांग उठाने लगी है. पर, सच्चाई यह है कि आज सीमा पर चाहे कितना भी तनाव हो, लेकिन चीन के साथ व्यापारिक रिश्ता समाप्त नहीं किया जा सकता है. आज भारत में चीनी कंपनियों का मायाजाल कितना फैला हुआ है, यह किसी से छिपा नहीं है. एक सच्चाई यह भी है कि सरकार के स्तर पर किसी भी देश से सीधे तौर पर व्यापारिक संबध को तोड़ा या खत्म नहीं किया जा सकता है. आज भारत और चीन दोनों ही देश विश्व व्यापार संगठन की कानूनी पेचीदगी में फंसे हुए हैं. यानी सरकार इस अंतराष्ट्रीय कानून के तहत चीन से सीधे तौर पर व्यापार को नहीं रोक सकती है. ऐसे में एक सीधा विकल्प यही बचता है कि चीनी सामान का बहिष्कार निचले स्तर से शुरू हो. इसके लिए दुश्मन पर ऐसा वार हो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे कहावत का इस्तेमाल करना होगा.

अब, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या इन सामानों के विकल्प हमारे पास मौजूद हैं? और यदि नहीं, तो क्या हम उन सामानों का अपने देश में उत्पादन करने में सक्षम हैं या भविष्य में हो सकते हैं? निश्चित रूप से इसका उत्तर 'हाँ' है. यदि हम अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करते हुए वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करने लगे तो जल्दी ही आत्मनिर्भर बन सकते हैं. हमारे देश में वे सभी संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जो आत्मनिर्भर बनने के लिए आवश्यक है. भारत शायद विश्व का एक मात्र ऐसा देश है जिसे प्रकृति प्रदत्त सभी भौगोलिक परिस्थितियां वरदान स्वरूप प्राप्त हैं. यथा, भारत के कुछ इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ती है तो कहीं भरपूर गर्मी पड़ती है. कुछ राज्यों में बारहों महीने बारिश होती है तो कहीं न के बराबर बारिश होती है. यदि, इन परिस्थितियों का हम चतुराई से प्रयोग करें तो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना बहुत दूर की कौड़ी नहीं लगती.

आत्मनिर्भर भारत : संकल्पना का शुभारंभ

आत्मनिर्भरता ही वास्तविक स्वतंत्रता दिलाती है. वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए हाल ही में भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना प्रस्तुत की है. वर्तमान वैश्वीकरण के युग में आत्मनिर्भरता की परिभाषा में व्यापक बदलाव हुए हैं और विश्व समुदाय आत्मनिर्भरता को आत्मकेंद्रित के रूप में नहीं देखता है. भारत सदैव से 'वसुधैव कुटुंबकम' की संकल्पना में विश्वास करता है. चूँकि भारत दुनिया का एक महत्वपूर्ण देश है, अतः यदि आत्मनिर्भर अभियान से भारत प्रगति करता है तो वह दुनिया की प्रगति में भी भागीदार बनेगा. भारत सरकार ने इस योजना को दो चरणों में लागू करने का प्रस्ताव रखा है:

पहला चरण: इसमें चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक, खिलौने जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित करते हुए स्थानीय विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा.

दूसरा चरण: इस चरण में फर्नीचर, फूटवियर, एयर कंडीशनर, पूंजीगत सामान यथा मशीनरी, मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक, रत्न एवं आभूषण, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल आदि को शामिल करने का प्रस्ताव है.

आत्मनिर्भर भारत के पाँच स्तंभ:

अर्थव्यवस्था: जो वृद्धिशील परिवर्तन के स्थान पर बड़ी उछाल पर आधारित हो.

अवसंरचना: ऐसी अवसंरचना जो आधुनिक भारत की पहचान बने.

प्रौद्योगिकी: 21वीं सदी की प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था पर आधारित प्रणाली.

गतिशील जनसांख्यिकी: जो आत्मनिर्भर भारत के लिये ऊर्जा का स्रोत है.

मांग: भारत की मांग और आपूर्ति श्रृंखला की पूरी क्षमता का उपयोग हो.

आत्मनिर्भर भारत के लिये आर्थिक प्रोत्साहन: भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की गयी है. यह पैकेज भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10% के बराबर है. पैकेज में भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है.

तकनीकी हस्तक्षेप में वृद्धि: इस अभियान के माध्यम से भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की स्थापना के माध्यम से दो मुख्य लक्ष्यों यथा औद्योगिक विकास व रोज़गार को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा. वर्तमान वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्द्धा के दौर में राज्य सरकारों को अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा तथा महामारी के कारण बदली हुई परिस्थितियों में कंपनियों को घर से काम करने और अनुबंधित कामगारों को प्राथमिकता देना होगा. इसके लिए आधुनिक तकनीकी के अनुरूप कुशल श्रमिक की मांग को पूरा करने और अधिकतम रोज़गार उपलब्ध कराने हेतु कौशल विकास कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देना होगा.

उत्पादन श्रृंखला में भागीदारी: औद्योगिक विकास के साथ-साथ उत्पादन के स्वरूप और उद्योगों की कार्यशैली में बड़े बदलाव करने की भी योजना है. इससे कृषि और अन्य क्षेत्रों को इन परिवर्तनों के अनुरूप तैयार कर औद्योगिक विकास व ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान दिया जा सकेगा. उदाहरण के लिये विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादों की पैकेजिंग या उनसे बनने वाले अन्य उत्पादों के निर्माण हेतु स्थानीय स्तर पर छोटी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देकर औद्योगिक उत्पादन श्रृंखला में ग्रामीण क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी.

स्टार्टअप के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना: भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप व स्टैंडअप योजनाओं के द्वारा युवाओं को स्व-रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना व उनके नवीन अद्वितीय विचारों के जरिए नए-नए व्यवसायों को स्थापित करने की योजना है. इसके लिए युवाओं को विशेष आर्थिक सहायता भी दी जा रही है ताकि, युवा देश में ही रह कर उद्योग स्थापित कर रोजगार के अवसर पैदा करें.

तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता: हाल ही में 'मेक इन इंडिया' प्रोग्राम के तहत स्वदेशी तकनीक से निर्मित वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ने इतिहास रचा. इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनेकों नयी उपलब्धियां हासिल कर आत्मनिर्भर भारत अभियान को नया आयाम प्राप्त हुआ है.

कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता: कृषि के क्षेत्र में भारत बहुत पहले ही आत्मनिर्भर बन चुका है. आजादी के बाद कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति करते हुए भारत दाल, चीनी, कपास आदि के उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश बन चुका है. पशुधन के मामले में भी अग्रणी रहते हुए भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध और मक्खन उत्पादक राष्ट्र है.

सैन्य शक्ति का विस्तार: अपनी सैन्य शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि करते हुए भारत ने अत्याधुनिक हथियारों, उपकरणों, पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों तथा तेज क्रूज मिसाइलों से अपनी सेना को सुसज्जित कर लिया है. भविष्य में सेना के साज़ों सामान व आधुनिक हथियारों का निर्माण भी अब भारत में ही करने की योजना है.

निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर: औद्योगिक क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अनेकों महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. विश्व में दुपहिया वाहनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है. आज सड़कों का जाल व बंदरगाहों की क्षमता बढ़ाते हुए भारत आत्मनिर्भरता हासिल कर देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर रहा है.

निजी क्षेत्र को बढ़ावा: सरकार की घोषणा के अनुसार रणनीतिक क्षेत्रों के साथ औद्योगिक क्षेत्रों को भी निजी क्षेत्रों के लिये खोल दिया जाएगा. इसके लिए ऐसे रणनीतिक क्षेत्रों की सूची जारी की जाएगी, जहाँ निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ कम से कम एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी की उपस्थिति आवश्यक होगी. अन्य सभी क्षेत्रों में व्यवहारिकता के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निजीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा तथा रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अधिकतम संख्या सामान्यतः चार रखी जाएगी. बाकी अन्य कंपनियों के लिये निजीकरण, विलय आदि के विकल्प खुले रहेंगे. इसके अतिरिक्त गैर वित्तीय सार्वजनिक कंपनियों में सरकार अपनी हिस्सेदारी को 51% से कम करेगी.

भारत की स्वतंत्र उड़ान के समक्ष संभावित चुनौतियां

लागत और गुणवत्ता: वर्तमान समय में कई क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों को बहुत अधिक अनुभव नहीं है. ऐसे में लागत को कम रखते हुए वैश्विक बाज़ार की प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिये उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी.

आर्थिक समस्या: हाल के दिनों में भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में सक्रिय पूंजी और वित्तीय तरलता की चुनौती के मामलों में वृद्धि देखी गई. वैश्विक महामारी के कारण औद्योगिक गतिविधियों के रुकने और बाज़ार में मांग कम होने से औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं में वृद्धि हुई है. ऐसे में औद्योगिक अर्थव्यवस्था को पुनः गति प्रदान करने के लिये विभिन्न श्रेणियों में लक्षित योजनाओं को बढ़ावा देना चुनौतीपूर्ण होगा.

आधारिक संरचना: कोविड महामारी के कारण चीन से निकलने वाली अधिकांश कंपनियों के भारत में न आने का एक मुख्य कारण भारतीय औद्योगिक क्षेत्र (विशेष कर तकनीकी के संदर्भ में) में एक मज़बूत आधारिक संरचना का अभाव है. इसके अतिरिक्त भारतीय उत्पादक कच्चे माल की आपूर्ति के लिए आज भी आयात पर निर्भर है.

वैश्विक मानक: सरकार द्वारा स्थानीय उत्पादकों और व्यवसायियों को दी जाने वाली सहायता मुक्त व्यापार समझौतों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ (डबल्यू.टी.ओ.) के मानकों के अनुरूप ही जारी की जा सकती है. सरकार चाह कर भी इससे बाहर नहीं जा सकती है.

निष्कर्ष: भारत की विकास यात्रा अब तक शानदार रही है. औद्योगिक क्षेत्र में अनेकों चुनौतियाँ होने के बावजूद भारत अब उन उद्यमों में भी निवेश कर रहा है जिनमें भारत के वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने की संभावना है. भारत को महाशक्ति के रूप में उभारने के लिए सरकार द्वारा जारी विशेष आर्थिक पैकेज द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में दीर्घकालिक सुधारों को शामिल किया जा रहा है. आज भारत अपने पुरातन संस्कृति व समृद्ध परंपराओं को साथ लेकर शिक्षा, कृषि, अंतरिक्ष, संचार, रेलवे आदि समस्त क्षेत्रों में तेजी से विकास करते हुए आत्मनिर्भरता की राह पर उड़ान भरने हेतु अग्रसर है.

कृष्ण कुमार यादव
क्षे.म.प्र.का., बेंगलुरु

Steps of Aatma Nirbhar Bharat

Without food, man can survive for four weeks, without water for four days. And without air perhaps four minutes... But without expectation humans can't survive four seconds.'

To deal with the economic distress caused by the COVID-19 pandemic worldwide most of the governments have announced relief packages. Though big in numbers, these packages have very little to offer to those most affected by the crisis. All over the world, the best ways to respond to the COVID-19 pandemic has thrown up political, economic and ideological challenges before governments. Some countries have of course done better than others due to decades of neoliberal policies, governments and the political elite. The big economies like USA announced 13% of its GDP i.e., 2.7 trillion USD, Japan 21.1% of its GDP, Sweden 12% of its GDP, Australia 10.8% of its GDP, Germany 10.7% of its GDP, Brazil (10%) of its GDP etc. Across the world, countries relief packages vary from 1% of GDP to 12% of GDP as of now. Nationwide lockdowns have dealt a serious blow to our economy. Prime Minister Narendra Modi announced the big-bang systemic reforms under Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan or Self-reliant India Mission with the slogan 'Vocal for Local' and his government would reveal the details of an economic incentive package worth Rs 20 lakhs crore or 10% of India's GDP in 2019-20, aimed towards achieving this mission. He stressed on the importance of promoting 'local' products and called it Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan. The Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan is a chance for Indian start-ups to innovate for which we are usually dependent on global suppliers. They can innovate and bring in the market products and services that are world-class yet reasonable. They are quick to spot opportunities in adversities and innovate in limited time and budget to make competitive products. Start-ups in sectors like automation, fin-tech, supply chain, logistics, healthcare, etc. would lead the change in the mission. The steps of Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan stand on five pillars which needs five tranches of financial injection to boost the economy, to tackle the COVID-19 pandemic and become a self dependent country.

The five Pillars and Tranches :- The Prime Minister announced that an Aatma Nirbhar Bharat or a self-reliant India stands on the five pillars: (1) **Economy**, which brings in a quantum jump and not incremental change. This could be possible by focussing on MSMEs which is the second largest contributor to India's GDP. (2) **Infrastructure**, government has focused on infrastructure that represents modern India. Modern Infrastructure will make our engineers more innovative, which will enable India to become an innovative provider not seeker, (3) **System**, based on 21st-century technology-driven arrangements and system, (4) **Demand**, whereby the strength of our demand and supply chain should be utilized to full capacity, (5) **Vibrant Demography**, which is the source of energy for a self reliant India.

Following this, the Finance Minister had announced five phases for implementation of the programme. **Phase-I**:- Business including MSMEs, **Phase-II**:- Poor, including migrants and farmers, **Phase-III**:- Agriculture, **Phase-IV**:- New Horizons of growth and **Phase-V**:- Government Reforms and enablers.

The first tranche includes 16 specified notifications which spanned in the sector of MSME, NBFC, real estate, power sectors, etc. For taxpayers the deadline for income tax returns for the financial year 2019-20 was extended to 30 Nov 2020. The rates of Tax Deduction at Source (TDS) and Tax Collection at Source (TCS) have been cut by 25% for the next year. Employees Provident Fund support to low-income organized workers under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana(PMGKY), is being extended for

another 3 months. In MSMEs sector a total of Rs 3 lakhs crore emergency credit line has been declared to 45 lakh units to have access to working capital and to resume business activity and protect jobs. Provision of Rs 20,000 crores as subordinate debt for 2 lac MSMEs are stressed or deemed non-performing assets. Rs.50,000 crore equity infusion is planned, through an MSME fund with a corpus of Rs.10,000 crores. The definition of an MSME is being expanded to allow for higher investment limits and the introduction of turnover-based criteria. Foreign tenders will not be allowed for government procurement up to Rs.200 crores. Within 45 days, the government and central public sector enterprises will release all funds due to MSMEs. In the NBFCs category Rs.30,000 crore special liquidity schemes, under which investment will be made in investment-grade debt papers of NBFCs. Partial credit guarantee scheme are extended under which the government guarantees 20 % of the first loss to the lenders NBFCs, HFCs, and MFIs with low credit rating. Rs 90,000 crore liquidity injection plan is announced to provide loans for power distribution companies (discoms). In Real Estate sector the States and UTs have been advised to extend the registration and completion date of real estate projects by six months.

The second tranche is aimed to afford free food grains to migrant workers without ration cards. For the 2 months, the Centre spent Rs.3,500 crores to provide free food grains. This is an expansion of the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana i.e., PMGKY. Street vendors will be provided credit through a Rs.5,000 crore scheme, which will propose Rs.10,000 loans for initial working capital. Plans to register 2.5 crore farmers without Kisan Credit Cards scheme, along with fish workers and livestock farmers and offer them Rs. 2 lakh crore concessional credit. NABARD will provide additional refinance support of Rs 30,000 crores to rural banks for crop loans. Small businesses with loans under the MUDRA-Shishu scheme, will receive a 2% interest subvention relief for the next year. A scheme to build rental housing complexes through Public Private Partnership mode would be launched under the existing Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) scheme. Both public and private agencies will be incentivized to build rental housing on government and private land while existing government housing will be converted into rental units. By August 2020, the ration card portability scheme will allow 67 crore National Food Security Act beneficiaries in 23 connected States to use their cards at any ration shop anywhere in the country. All the States have been directed to enrol migrant workers returning to their native places in the MGNREGA scheme.

The third tranche of the economic assistance package focuses on agricultural marketing reforms. Inter-state trade plans to enact a central law to permit barrier-free inter-State trade of farm commodities and E-trading. This will allow farmers to sell produce at attractive prices beyond the current mandi system. For contract farming, there are plans to ensure a facilitative legal framework to oversee contract farming. This would provide farmers with assured sale prices and quantities even before the crop is sown and also allow private players to invest in inputs and technology in the agricultural sector. The Centre will deregulate the sale of six types of agricultural produce, including cereals, edible oils, oilseeds, pulses, onions, and potatoes by amending the Essential Commodities Act, 1955. For development of agriculture infrastructure an investment of 1.5 lakh crore rupees to build farm-gate infrastructure and support logistics needs for fish workers, livestock farmers, vegetable growers, beekeepers, and related activities.

The fourth tranche focuses on the sectors of defence, aviation, power, mineral, atomic and space. In defence sector there is a provision for banning import of some weapons and platforms to indigenise defence production. To reduce the defence import bill and encourage domestic production, there is a provision for a separate budget for domestic capital procurement. Under the automatic route, the FDI limit in defence manufacturing will be raised from 49% to 74%. To improve autonomy, efficiency and accountability the Ordinance Factory Boards (OFB) would be corporatized and listed on the stock market. In mining sector the government monopoly on coal would be removed with the introduction of commercial mining on a revenue-sharing basis. The private sector would be allowed to bid for 50 coal blocks and also undertake exploration activities. In space sector private involvement in space will be encouraged. A level playing field for private players will be created in the space sector, allowing them to use ISRO facilities and participate in future projects on space travel and planetary exploration. In aviation sector six more airports are up for auction on

private-public partnership mode, while additional private investment will be invited at 12 airports. In atomic sector research reactors in PPP mode would be set up for the production of medical isotopes.

The fifth tranche of measures covers seven areas such as MNREGA, health reforms and initiatives, businesses, decriminalisation of the Companies Act defaults, ease of doing business, Public Sector Enterprises (PSE), and support to state governments. Government declared a supplementary allocation of Rs 40,000 crore to increase employment under MNREGA. To reform the health sector, a plan has been taken to raise investment in public health to prepare India for future pandemics by creating infectious disease hospital blocks in all districts, encouraging research and implement digital health mission. To implement technology-driven education post-COVID-19, PM e-VIDYA, Manodarpan and other schemes will be launched.

To increase business through Insolvency Bankruptcy Code (IBC) process the threshold limit raised to Rs 1 crore from Rs 1 lakh. Seven compoundable offences were discarded, and five compoundable offences will be dealt with under the alternative framework. A list of strategic sectors will be notified for Public Sector Enterprises (PSE). In other non-strategic sectors, PSEs will be privatised. The figure of PSEs will be concentrated between one to four by merging, privatising or bringing under the holding companies. Revenue Deficit Grants Rs 12,390 crore in April and May, State Disaster Relief Fund Rs 11,092 crore in the first week of April and for anti-COVID activities, the Health Ministry allocated Rs 4,113 crore. The RBI increased Ways & Means Advance limit by 60%, the continuous overdraft days increased from 14 to 21 and also the number of days for an overdraft in the quarter increased from 32 to 50. The net borrowing ceiling limit for the FY 2020-21 for the states has been enlarged from 3% of GDP to 5% of GDP, and this will generate additional resources of Rs 4.28 lakh crore.

The salient point of the Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan is a framework for building a self-reliant India, which would be competitive globally. To fulfil this dream the mission targets to strengthen local manufacturing, building local supply chains and convert local products into global brands. The Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan is a chance for Indian start-ups to take charge of innovations. Start-ups in sectors like automation, fin-tech, supply chain, logistics, healthcare, etc. would lead the charge in the mission.

This Stimulus Package will stimulate the three sectors of the economy. In Primary Sector the packages declared for the agricultural and allied sectors are particularly transformative. These reforms are stepladder in the direction of 'One Nation One Market' objective and help India become the food factory of the world that will finally help in achieving the goal of a self-sustainable rural economy. Moreover, Rs 40,000 crore infusions in MGNREGA will help in alleviating the distress of migrants in their return to villages. In Secondary Sector Rs 3 lakh crore collateral free loans for MSMEs will help the finance-starved sector and will give a thrust to the miserable state of the economy. The MSME sector is the second largest employment generating sector in India. Subsequently, limiting imports of weapons and increasing the limit of FDI in defence from 49% to 74% will give a much-needed boost to the production in the Ordnance Factory Board and it will reduce India's huge defence import bill. In the Tertiary Sector the balance approach taken by the government across concerned sectors will improve the education and health sectors. The newly launched PM e-Vidya programme for online education provides a uniform learning platform for the whole nation, which shall enable schools, colleges and universities to stream courses online. The Public expenditure on health will be increased by investing in grass root health institutions and ramping up health and wellness centres in rural and urban areas.

Conclusion :- Finally, the five tranches of financial injection to the economy will rejuvenate the five strong pillars of the economy and decrease the COVID-19 pandemic. To remain globally competitive with a well assured future, we need to focus on, "Skills, scale and speed." The big-bang systemic reform Aatma Nirbhar Bharat plan encompasses the unfinished agenda of holistic reforms including reforms in Education, Skill and Labour, etc. We can prove to the world that the 21st century belongs to India through self-belief, dedication and discipline. The package will also focus on empowering the poor, labourers, and migrants etc., both from organized and unorganized sectors.

Biswajit Dhar
R.O., Guwahati

उच्च कार्यपालक वेतनमान VII में पदोन्नति पर हार्दिक बधाई !!

श्री अमरेन्द्र कुमार
महाप्रबंधक

श्री एम वेंकटेश्वर स्वामी
महाप्रबंधक

श्री बिनोद कुमार पट्टनायक
महाप्रबंधक

श्री ज्ञान रंजन सरंगी
महाप्रबंधक

उच्च कार्यपालक वेतनमान VI में पदोन्नति पर हार्दिक बधाई !!

श्री एम वी वी प्रसाद राव
उप महाप्रबंधक

श्री सोवन सेनगुप्ता
उप महाप्रबंधक

श्री आनंद कुमार
उप महाप्रबंधक

श्री के. अजय पॉल
उप महाप्रबंधक

श्री मनोज शर्मा
उप महाप्रबंधक

श्री राकेश विश्वनाथ मेश्राम
उप महाप्रबंधक

श्री पी. संन्यासी राजू
उप महाप्रबंधक

श्री बिशन दास
उप महाप्रबंधक

श्री आई. सत्यनारायण मूर्ति
उप महाप्रबंधक

श्री बिनोद कुमार गुप्ता
उप महाप्रबंधक

श्री उमापथिश्वर हलेमनी
उप महाप्रबंधक

श्री ए राधाकृष्णन
उप महाप्रबंधक

श्री प्रवीण कुमार खन्ना
उप महाप्रबंधक

श्री तत्ती श्रीनिवास
उप महाप्रबंधक

श्री अनुज एस. सिन्हा
उप महाप्रबंधक

श्री रणजीत कुमार
उप महाप्रबंधक

श्री राव एम. सीताराम
उप महाप्रबंधक

हम आपके नेतृत्व में बैंक के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं.

आत्मनिर्भर भारत में भारतीय भाषाओं का महत्व

आत्मनिर्भर भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है. यह उतना ही पुराना है जितना भारतीय भाषाओं का इतिहास. पूरी दुनिया की अर्थव्यस्थाओं का अध्ययन यह बताता है कि पहली शताब्दी से लेकर पन्द्रहवीं शताब्दी तक भारत का जीडीपी पूरे दुनिया के उत्पादों का लगभग 33% था. दुनिया भर के अलग-अलग देशों में भारतीय उत्पादों का निर्यात होता था. भारतीय मसाले, रत्न, कपड़े और यहाँ तक कि युद्ध सामग्रियों से भरे पानी के जहाज दुनिया भर का चक्कर लगाया करते थे. विदेशी व्यापारी भी भारत के विभिन्न हिस्सों से व्यापारिक रूप से जुड़े हुए थे. उन व्यापारिक व्यवहारों का वाहक और माध्यम निश्चित रूप से भारतीय भाषाएं ही थीं, क्योंकि तब इस देश में किसी भी विदेशी भाषा का आगमन नहीं हुआ था.

सारा उलट फेर पिछले पांच सौ सालों में हो गया जब इस देश पर राजनीतिक, धार्मिक, वैचारिक और मनोवैज्ञानिक हमलों के साथ-साथ भाषायी अतिक्रमण शुरू हो गए. पहले तो इस्लामी शासकों ने शासन और प्रशासन की भाषा बदल दी. फारसी, अरबी और तुर्की भाषा के शब्दों ने स्थानीय भारतीय शब्दों को पदच्युत और विस्थापित किया. फिर अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा पद्धति के विरुद्ध षड़यंत्रों को अंजाम देना शुरू किया. इन्होंने अंग्रेजी को शासन और प्रशासन का माध्यम बनाया. पुनः भारतीय भाषाओं के समृद्धि को दफन करने की प्रक्रिया शुरु हुई. किन्तु इन विकट परिस्थितियों में भी भारतीय समाज ने अपनी आंतरिक संरचना के सहारे अपने मूल्यों, अपनी भाषा और विलक्षण प्रतिभा का भरसक संरक्षण किया.

लेकिन समाज के एक बड़े वर्ग, खासकर पढ़े लिखे और संपन्न वर्ग ने अपनी लालसाओं के कारण सबसे पहले अपनी मातृभाषा का दामन छोड़ कर अपने नए नरेशों की भाषा को अपनाया, अपना रंग-ढ़ंग बदल लिया और अपनी ही मातृभाषा के मूल शब्दों को निगलने में जुट गए. आज परिदृश्य यह है कि भारतीय भाषाओं के लगभग एक तिहाई शब्द अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में समा चुके हैं या विलुप्ति के कगार पर हैं. ये समाज का वही वर्ग है जिसकी आवश्यकताएं भारत को आत्मनिर्भर देश की परिभाषा से बाहर कर देती है. अन्न, जल और प्राकृतिक संसाधनों से सम्पन्न यह भारतभूमि अपनी संतानों की सारी सांसारिक और सांस्कृतिक कामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम है. किंतु भारतीय समाज का वह वर्ग जो स्वयं-विस्मरण का शिकार है, अपनी अतृप्त आत्मा के कारण विक्षुब्ध है, उसे वह सुख-साधन चाहिए जो आम जन को उपलब्ध नहीं है. इनकी विलासिता के साधन इस देश के उत्पादों से पूरे नहीं होते और इस लिहाज से भारत एक आत्मनिर्भर राष्ट्र होते हुए भी एक बड़ा आयातक राष्ट्र है. समाज का यह तथाकथित अभिजात्य वर्ग विदेशी भाषा, विदेशी साहित्य और विदेशी सामग्रियों की ऐसी ललक पालता है जो भारत के आत्मनिर्भर होने के सपने को विफल कर देता है.

भारतीय संप्रभुता और संपन्नता को पिछली सहस्त्राब्दी में दो घातक आक्रमण और आधिपत्य का घाव लगा है. यह देश उन विध्वंसक आक्रांताओं से बच तो गया किन्तु यह अभी भी थका हुआ और घायल अवस्था में है. दोनों ही काल इस दृष्टि से विकट थे कि दोनों ने ही न सिर्फ इस देश के संसाधनों को लूटा बल्कि उसने भारतीय समाज को बदलने के लिए वो सब कुछ किया जो दुनिया के अन्य हिस्सों में विध्वंस और बदलाव करने में सफल रहे. इसका सबसे ज्यादा आघात भारतीय मानस और भारतीय भाषाओं पर पड़ा. स्वतंत्रता के उपरांत भी भारतीय समाज उन प्रभावों से अभी तक मुक्त नहीं हो पाया है. स्वतंत्रता के उपरांत भारतीय अस्मिता के उद्धार के सीमित प्रयास हुए भी. जबकि वो सारी ताकतें अभी भी प्रयासरत हैं कि भारतीय मूल्यों को कैसे ध्वस्त किया जाए. भारतीय भाषाएं उनके निशाने पर हैं जो भारतीय मूल्यों की जीवंत वाहक हैं.

स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अपने पहले उद्बोधन में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि इतिहास में कभी-कभी ये अवसर आता है जब हम पुरातन से निकलकर नवीन की ओर अग्रसर होते हैं, जब एक काल का अंत होता है और एक दमित राष्ट्र को मुखरता प्राप्त होती है. लेकिन क्या ऐसा हुआ? क्या भारतीय मानस अभी भी उन बंधनों से मुक्त हो पाया है? वस्तुतः भाषायी दृष्टि से ये पहले से और भी अधिक परावलम्बी हो गया है. मात्र 0.02 प्रतिशत अंग्रेजी बोलने वालों का दबदबा अब भी कायम है. लगभग 44%

भारतीयों ने अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में अपना लिया है. जबकि अरबी, फारसी और तुर्की भाषाओं के गर्भ से निकली हुई उर्दू ने भारतीय भाषाओं के मूल शब्दों को अपने प्रतिष्ठा पूर्ण स्थान से अलग कर दिया. सबसे दुखद बात तो यह है कि भारतीय भाषाओं को देशी, जातीय और स्थानीय (वर्नाक्यूलर) भाषा कह कर उनका उपहास किया जाता है. भारतीय भाषाओं के विलुप्त होते शब्दों के संरक्षण के लिए कोई भी प्रयास होता हुआ नहीं दिख रहा. सारी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं निर्लज्जता पूर्वक अंग्रेजी को बढ़ावा दे रही हैं. यह बहुसंख्यक समाज, जो देशज भाषाओं को ही बोलता और समझता है, उसके प्रति एक हिंसक व्यवहार है. आम जन को दी जाने वाली सेवाएं अनिवार्य रूप से उनकी ही भाषा में उपलब्ध होनी चाहिए. उच्च शिक्षा क्षेत्र में यह समस्या यथावत बनी हुई है और सुधारात्मक समाधान का कोई प्रयास होता हुआ नहीं दिख रहा है. सबसे बुरा हाल तो हमारे न्यायालयों और न्याय व्यवस्था का है जो अंग्रेजी से भी इतर ऐसी भाषा और ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है जो लैटिन और रोमन शब्दकोष से लिये गए हैं. इस क्षेत्र में भी कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाए जा रहे हैं. यह स्थिति बहुत ही निराश करने वाली है. नीति निर्धारकों के ढुलमुल रवैए और षड़यंत्रकारियों के धूर्त प्रयासों के कारण भारतीय भाषाओं का क्षरण हो रहा है. भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए स्पष्ट नीति और गंभीर प्रयास की आवश्यकता है.

1700 से ज्यादा भारतीय भाषाएं लगभग 780 भाषा समूहों का निर्माण करती हैं और राष्ट्रीय संपर्क सूत्र के लिये हिंदी सहित अनेक परिभाषित भाषाओं को चलायमान रखती है. इतने विस्तृत आधार के फलस्वरूप भारतीय भाषाओं के पास अपने शब्दों का एक विशाल भंडार है जो समस्त चिन्हित-अचिंहित, गोचर-अगोचर और धातु-अधातु संज्ञाओं और तत्वों को नाम देता है, परिभाषित करता हैं. इन भाषाओं की ये क्षमताएं इस राष्ट्र के समस्त आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और राजनीतिक इत्यादि व्यवहारों को सुगम मार्ग उपलब्ध कराने में सक्षम है. फिर भी हमारे देश के नीति निर्धारकों की कमजोर इच्छा शक्ति और हीन-भावना के कारण भारतीय भाषाओं का संरक्षण नहीं हो रहा है. फिर भी यह संतोष का विषय है कि भारत की भाषाओं का संरक्षक वह बहुसंख्यक वर्ग हैं. जिसे मूलतः अनपढ़ और गंवार समझा जाता है, जो भारत के ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं, जिनकी अभिलाषाएं और आकांक्षाएं सीमित हैं, उन्होंने अपनी मातृभाषा का दामन थाम रखा है. तमाम कुटिल षड़यंत्रों के बावजूद वह अपनी मातृभाषा की शुचिता को अक्षुण्ण रखने के लिए संघर्षरत है. उसकी ही भाषाएँ हमारी मुख्य संपर्क भाषाओं को संबल प्रदान करती हैं, नए शब्दों का सृजन करती हैं और संपर्क भाषाओं को समृद्ध करती हैं.

उस समाज की सारी आर्थिक, राजनीतिक और यहां तक कि भावनात्मक आवश्यकताएं यह राष्ट्र को पूर्ण करने में सक्षम है. भाषा संस्कारों का रक्षण करती है. यह जीवन के मंत्र का वाहक होती है. मातृभाषा हमारे चित्त को स्थिर रखती है और सामाजिक विकास के प्रवाह को संतुलित गति प्रदान करती है.

भारतीय भाषाओं का विकास इस भूभाग पर बिना किसी बड़े उथल-पुथल के अनादि काल से होता रहा है. इसलिए देश के समस्त सरोकारों को संचालित करने के लिए आवश्यक सामर्थ्य भारतीय भाषाओं में पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है. शब्दों का विशाल भंडार भारतीय भाषाओं, मुख्य रूप से अर्वाचीन (नवीन) भाषाओं जैसे हिंदी, बांग्ला इत्यादि को इतना सक्षम बनाता है कि दुनिया की अन्य भाषाएं इनसे शब्दों का उधार ले रही हैं. भारतीय भाषाओं में सामाजिक व्यवहार में प्रयुक्त होने वाले संवाद सूत्रों से लेकर ज्ञान विज्ञान और अभियांत्रिकी तक के जटिल शब्दों का विशाल भंडार है क्योंकि भारतीय भाषाओं की जननी है संस्कृत, जिसे अक्षर और स्वर की भी जननी मानी जाती है. आत्मनिर्भर होने के सभी लक्षण इस राष्ट्र में मौजूद है. इस आत्मनिर्भरता को परिभाषित करने के लिए हमारे पास भाषा भी है, पुरुषार्थ भी है और संकल्प भी है.

अतः भारतीय भाषाएं आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न का सूत्रधार है.

राजेश कुमार श्रीवास्तव
क्षे.का., सूरत

'नई तकनीक का उपयोग'

भारत के विकास के लिए नयी तकनीकी का व्यापक उपयोग अत्यावश्यक है. भारत में तकनीकी विकास और सुधारों के द्वारा देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है. तकनीक के उपयोग से देश का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सकता है. नयी तकनीक के द्वारा देश विकास के नए पैमानों को प्राप्त कर सकता है. सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग इस दिशा में एक प्रमुख कदम है. भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में भी सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से तकनीकी का व्यापक उपयोग हो रहा है. तकनीकी के नए आयामों के द्वारा देश के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त हो रहा है.

भारत का विकास संतुलित विकास के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें प्रकृति और तकनीकी का मिला जुला आयाम निर्धारित है. इस प्रकार तकनीकी विकास भारत के आत्मनिर्भर स्वरूप पर आधारित है. आज के समय में तकनीकी विकास एक सतत प्रक्रिया है. तकनीक का उपयोग भारत के व्यापक स्वरूप और नव आयाम पर आधारित है. इस प्रकार नयी तकनीक के प्रयोग के द्वारा भारत का बहुमुखी और बहुआयामी विकास उचित रूप से परिलक्षित होता है. सूचना प्रौद्योगिकी का बढ़ता प्रयोग जन मानस के पारदर्शी और बदलते स्वरूप को परिलक्षित करता है.

आज का युग हरित क्रांति के समान सूचना क्रांति का युग है. खेतों और उद्योगों का स्वरूप बदलता जा रहा है. आज के कृषक सूचना प्रौद्योगिकी और नयी तकनीक से युक्त है. ग्रामों में जनसंख्या का दबाव और रोजगार के घटते साधन नयी समस्याएँ उत्पन्न कर रहे हैं. परंतु नयी खेती की तकनीक और फसलों के चक्र में बदलाव जैसे औषधीय पौधों या व्यावसायिक उद्योग के कारण तकनीकी बदलाव उचित प्रकार से देखे जा सकते हैं. उद्योगों में भी नवीन तकनीकी का व्यापक उपयोग हो रहा है.

कोरोना काल ने ग्रामीण भारत के युवाओं को कृषि की ओर मोड़ दिया है. इस दौरान पढ़ी-लिखी युवा पीढ़ी उद्योग क्षेत्र में आने वाली समस्याओं द्वारा इसकी दक्षता में सुधार के तरीके ढूंढ रही है, इसके अलावा इस पर भी अधिक जोर दिया जा रहा है कि कैसे प्रौद्योगिकी को अपनाकर ग्रामीण भारत में उद्योग दक्षता को बढ़ावा मिले. भारत घरेलू और वैश्विक उद्योग उत्पादन मांग में अग्रणी योगदानकर्ताओं में से एक है. प्रौद्योगिकी अपनाने से दूध, सब्जी और अन्य उत्पादों को विभिन्न तरीकों से बेहतर बनाने में मदद मिली है. रिमोट सेंसिंग (उपग्रहों के माध्यम से), जीआईएस और मृदा स्वास्थ्य निगरानी, प्रौद्योगिकी परिवर्तन के उदाहरण हैं, जो उद्योग दक्षता में सुधार करने में मदद कर रहे हैं. सौर ऊर्जा के व्यापक उपयोग के द्वारा भी ऊर्जा संरक्षण और उसके व्यापक उपयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ है. लेकिन, खराब होने वाली और खराब हो रही उद्योगों के लिए कोल्ड स्टोरेज चेन तकनीक अपनाने से बर्बादी कम होने तथा किसानों और उपभोक्ताओं को होने वाले लाभ में काफी हद तक सुधार हुआ है.

पर्यटन उद्योग में तकनीक का बढ़ता प्रयोग देश की समृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है. कोरोना के कारण पर्यटन उद्योग से जुड़े राज्यों जैसे गोवा, उत्तराखंड के आर्थिक विकास में नकारात्मक प्रभाव पड़ा है. इस प्रकार इस क्षेत्र को उबरने में एक लंबा समय लगेगा परंतु हमारा देश तकनीकी के उपयोग के द्वारा इस स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है. इस प्रकार पर्यटन के क्षेत्र में व्यापक सुधार की आवश्यकता कोरोना काल में महसूस हुई है. इस प्रकार पर्यटन के क्षेत्र में सुधार और व्यापक विस्तार के द्वारा समस्त परिवर्तनों को सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक इस्तेमाल से उचित प्रकार से समझा जा सकता है. इस

प्रकार धार्मिक पर्यटन को नये विस्तारपूर्ण सुधारों के द्वारा उचित प्रकार से समझा जा सकता है. सामाजिक दूरी का उचित पालन तथा उचित व्यवस्था के द्वारा धार्मिक पर्यटन को उचित प्रकार से विस्तारित किया जा सकता है.

उद्योग आधारित छोटे उपक्रमों से उचित दर पर ट्रैक्टर और अन्य उद्योग उपकरण प्रदान करना, उत्पादन की लागत को कम करने में मदद करते हैं. भौगोलिक मैपिंग, जो किसान को जरूरत का सामान पहुंचाने में मदद करती है. जीपीएस सक्षम सेवाएं उपज, नमी आदि के बारे में प्रलेखन के क्षेत्र में भी मदद कर रही हैं. यद्यपि प्रौद्योगिकी अपनाने से भारतीय उद्योग क्षेत्र की दक्षता में सुधार हुआ है, प्रौद्योगिकी अपनाने से यह साबित हो गया है कि उद्योग उत्पादन में कई तरीकों से सुधार कर उद्योग दक्षता में सुधार करने की क्षमता है. इसलिए, प्रौद्योगिकी अपनाने से उद्योग उत्पाद को 'स्थानीय से वैश्विक' बाजार तक एक कुशल तरीके से पहुंचने में मदद मिल सकती है.

एक सफल भविष्य की विकास रणनीति उद्योग के लिए विचारों के साथ प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है. सफल व्यवसायीकरण के लिए मार्ग और इसका उपयोग बड़े पैमाने पर करने के लिए सही प्रोत्साहन और नीति समर्थन प्रौद्योगिकी लाने की जरूरत है. निजी क्षेत्र का निवेश तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. इन क्षेत्र में प्रयासों को और बढ़ाना होगा. क्योंकि तकनीकी ज्ञान, बुनियादी ढाँचा एक मजबूत वितरण तंत्र, अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र उद्योग में सीधे योगदान देता है. तकनीकी विकास ज्ञान और नए भौतिक बाजार की चुनौती पर आधारित है और भविष्य की तैयारी को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है.

कोरोना काल में तकनीकी के नए आयाम उत्पन्न हुए हैं. आज सभी जगह घर से कार्य करने को प्रोत्साहित किया जा रहा है. ताकि संक्रामण का फैलाव रोका जा सके और सूचना प्रौद्योगिकी का भी उचित प्रयोग हो सके. इस प्रकार प्रौद्योगिकी के उपयोग से विकास का मार्ग प्रशस्त होता है और भीड़ नियंत्रण भी उचित प्रकार से किया जा सकता है. भारत में सभी क्षेत्रों में तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है. उद्योग, सैन्य व अन्य सभी गतिविधियों में नवीन तकनीक को प्रोत्साहित किया जा रहा है. इस प्रकार तकनीकी का व्यापक उपयोग नए आयाम तथा नव विन्यास प्रदान कर रहा है.

आदित्य रमण सिंह
डीआईटी, पवई, मुंबई

बधाई

कुमारी सरीन, सुपुत्री सुश्री शमा शिकलगर, मुख्य प्रबन्धक (राभा), राभाकाप्र, कें. का., मुंबई ने सावित्रीबाई फुले, पुणे यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्चर की अप्रैल 2020 में आयोजित अंतिम वर्ष की परीक्षा डिस्टिंक्शन के साथ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की.

कुमार कृष्ण, सुपुत्र श्री नवनीत कुमार, उप महाप्रबंधक, ऋण अनुपालन एवं अनुश्रवण विभाग, कें. का., मुंबई ने सी बी एस ई बोर्ड, दिल्ली द्वारा मार्च 2020 में आयोजित 10वीं कक्षा की परीक्षा में 98% अंक अर्जित किये.

कुमार साईल, सुपुत्र श्री प्रवीण दादु सोनावले, एसडब्ल्यूओ 'बी' फ्रैकिंग विभाग, मुंबई समाचार मार्ग, मुंबई ने माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा में 92% अंक अर्जित किये.

स्वदेशी आंदोलन एवं आत्मनिर्भर भारत - कितना समान, कितना भिन्न

आत्मनिर्भर भारत शब्द जो कि अपने आप में सम्पूर्ण व्याख्या रखता है. यह एक नीति है-भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक बड़ा और अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने के लिए. इस शब्द को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत को आर्थिक रूप से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर प्रतिनिधित्व लिए प्रयोग किया गया था. लेकिन 'आत्मनिर्भर भारत' की यह परिकल्पना कोई नई अवधारणा नहीं है बल्कि इसकी एक विस्तृत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी रही है जो कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में काफी महत्त्वपूर्ण योगदान रखती है.

'स्वदेशी आंदोलन' भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का अहम हिस्सा था जिसका दूसरा पहलू 'बहिष्कार आंदोलन' था. स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन वर्ष 1905 के बंग-भंग के विरोध में जनजागरण के परिणाम के रूप में सामने आया.

स्वदेशी का अर्थ है-'अपने देश का'. इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना तथा भारत में बने माल का अधिकाधिक प्रयोग करके साम्राज्यवादी ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुँचाना व भारत के लोगों के लिये रोजगार सृजन करना था. यह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने और भारत की समग्र आर्थिक व्यवस्था के विकास के लिए अपनायी गयी रणनीति थी.

'स्वदेशी आन्दोलन' के मुख्य उद्घोषक श्री अरविन्द घोष, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय थे. यही 'स्वदेशी आन्दोलन' महात्मा गांधी के स्वतन्त्रता आन्दोलन का भी केन्द्र-बिन्दु बन गया. उन्होंने इसे 'स्वराज की आत्मा' कहा.

भारत में स्वदेशी का पहला नारा बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय ने 1872 ई. में बंगदर्शन के विज्ञान-सभा का प्रस्ताव रखते हुए दिया था.

इसके बाद भोलानाथ चन्द्र ने 1874 में शंभुचन्द्र मुखोपाध्याय द्वारा प्रवर्तित मुखर्जीज़ मैगज़ीन में स्वदेशी का नारा दिया था. उन्होंने लिखा था-किसी प्रकार का शारीरिक बल-प्रयोग न करके राजानुगत्य अस्वीकार न करते हुए तथा किसी नए कानून के लिए प्रार्थना न करते हुए भी हम अपनी पूर्वसम्पदा वापस ला सकते हैं.

जुलाई, सन 1903 की 'सरस्वती पत्रिका' में 'स्वदेशी वस्त्र का स्वीकार' शीर्षक से एक कविता छपी. रचनाकार का नाम नहीं था किन्तु वर्षभर के अंकों की सूची से ज्ञात होता है कि वह पत्रिका के सम्पादक महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना थी. कविता का कुछ अंश उद्घृत है-

विदेशी वस्त्र हम क्यों ले रहे हैं?
वृथा धन देश का क्यों दे रहे हैं?
न सूझै है अरे भारत भिखारी!
गई है हाय तेरी बुद्धि मारी!

'आत्मनिर्भर भारत' परियोजना की पृष्ठभूमि :

वर्ष 2020 में भारतवर्ष और सम्पूर्ण विश्व का इतिहास एक वैश्विक संकट का साक्षी बना जब दुनिया कोविड-19 महामारी के चपेट में आई. मार्च, 2020 में कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए भारत में लॉकडाउन का सहारा लिया गया. भारत की तर्ज पर अन्य देशों में भी लॉकडाउन के माध्यम से कोविड-19 को फैलने से रोकने के प्रयास किए गए. इस लॉकडाउन ने हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा आघात पहुंचाया. भारत की चरमराती अर्थव्यवस्था को राहत देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 अप्रैल 2020 को 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' की घोषणा की. इसके अंतर्गत सरकार द्वारा 29.87 लाख करोड़ (US 420 बिलियन) के कुल तीन आत्मनिर्भर भारत पैकेजों की घोषणा की गई. 12 मई 2020 को, प्रधान मंत्री ने 20 लाख करोड़ (US 280 बिलियन) के समग्र आर्थिक पैकेज की घोषणा की. इसके बाद, 12 अक्टूबर और 12 नवंबर 2020 को दो और आत्मनिर्भर भारत आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज घोषित किए गए.

आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत, कई सरकारी फैसले लिए गए हैं, जैसे कि एमएसएमई की परिभाषा बदलना, कई क्षेत्रों में निजी भागीदारी के लिए गुंजाइश बढ़ाना, रक्षा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाना और कई नवीन क्षेत्रों जैसे सौर ऊर्जा निर्माण आदि के क्षेत्र हेतु समर्थन का मिलना.

यह स्पष्ट है कि भारत को आर्थिक मजबूती प्रदान करने एवं कोविड-19 महामारी के चपेट द्वारा आर्थिक संकट से जूझ रहे सामान्य जनता को राहत देने, रोजगार के अवसरों को उत्पन्न करने, आयात के लागत को सीमित करने तथा भारत को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से इस परियोजना को लाया गया है. यह एक आर्थिक क्रांति है जो देश को विभिन्न क्षेत्रों में स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य का अनुसरण करता है.

स्वदेशी आंदोलन एवं आत्मनिर्भर भारत - कितना समान, कितना भिन्न

* स्वदेशी आंदोलन और आत्मनिर्भर भारत परियोजना लगभग एक जैसी अवधारणाएं हैं केवल समय में भिन्नता है. स्वदेशी आंदोलन ब्रिटिश पराधीनता से जूझने हेतु भारत का एक

जनजागरण आंदोलन था; वहीं आत्मनिर्भर भारत स्वाधीन भारत में आर्थिक पराधीनता से मुक्ति के लिए चलाया गया अभियान है.

* स्वदेशी आंदोलन ने कई ऐसी 'अवधारणाओं' को जन्म दिया जिसमें भारत की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक स्वतन्त्रता के मार्ग को प्रशस्त किया. वे सभी अवधारणाएँ वर्तमान में आर्थिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में एक नए वर्ज़न (2.0) के रूप में उपस्थित है.

* 'स्वदेशी' आंदोलन में भारत में बनी वस्तुओं को अपनाने पर ज़ोर दिया गया था. वर्तमान में आत्मनिर्भर भारत मिशन में भी 'वोकल फॉर लोकल' के स्लोगन को बुलंद किया गया है जो कि उसी क्रांति का ही रूप है. 'वोकल फॉर लोकल' में भारत की बनी वस्तुओं को अपनाने के सिद्धान्त पर ज़ोर दिया जा रहा है ताकि देश आर्थिक रूप से मजबूत हो सके.

स्वदेशी आंदोलन के दौरान शंभुचन्द्र मुखोपाध्याय की उद्घृत उक्ति एकबार पुनः वर्ष 2020 में भी चरितार्थ होती है कि, हमें हर समय यह स्मरण रखना चाहिए कि भारत की उन्नति भारतीयों द्वारा ही सम्भव है.

* जैसा कि इतिहास में वर्णित है कि सन 1905 में हुये स्वदेशी आंदोलन का एक दूसरा पक्ष बहिष्कार आंदोलन था. यह इत्तेफाक का विषय है कि वर्तमान संदर्भ में आत्मनिर्भर भारत अभियान में जहां 'वोकल फॉर लोकल' 'स्वदेशी आंदोलन' का संशोधित स्वरूप बन रही थी, वहीं 'बायकॉट चाइना' इस मिशन के साथ जुड़ गया और 'बहिष्कार आंदोलन' का पक्ष भी वर्तमान संदर्भ में सार्थक हो रहा है. भारत में चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने के लिए मांग भारत के लिए अल्पावधि में व्यावहारिक रूप से कठिन हैं परंतु देश के जनता द्वारा यदि चीनी उत्पादों और एप्लिकेशन्स का प्रयोग बंद किया जाए तो एक हद तक भारतीय उद्योग के हिस्से चीन पर निर्भरता कम हो सकती.

* **स्वराज की अवधारणा :** स्वराज शब्द का पहला प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था. तत्कालीन भारत में स्वराज का शाब्दिक अर्थ 'स्वशासन' या 'अपना राज्य' से लिया गया है.

वर्तमान में 'सेल्फ-सफ़िशियंट', 'सेल्फ-रेलियंट' जैसी अवधारणाओं को विकसित किया गया. इनका उद्देश्य भारत को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है.

स्वदेशी आंदोलन एवं आत्मनिर्भर भारत परियोजना के परिणाम/प्रभाव/उपलब्धियां:-

स्वदेशी आंदोलन : स्वदेशी आंदोलन ने भारत में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक सुधारों, अवसरों, नवोन्मेषी प्रयोगों और संरचनागत ढ़ांचे के निर्माण को मंच प्रदान किया.

* शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसरों को जन्म दिया- 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई.

* रोजगार के अवसरों के लिए कई औद्योगिक संस्थाओं की स्थापना हुई जिसमें पी सी राय केमिकल फैक्ट्री की स्थापना, टाटा आयरन व स्टील कंपनी सफलतम उदाहरण हैं.

* भारत में स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत भी इसी युग में हुई. आज भारत की अधिकांश राष्ट्रीयकृत बैंक उसी अवधि में (1905-1911 के बीच) स्थापित किए गए थे.

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में पहल/उपलब्धियां :

* जुलाई, 2020 से भारत में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई किट) क्षेत्र में उत्पादन की शुरुआत की गयी. भारत में पीपीई किट निर्माण उद्योग तीन महीनों में 10,000 करोड़ (US 1.4 बिलियन) का हो गया है, जो चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है यह आत्मनिर्भर भारत का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है.

* देश में 21,000 करोड़ (US 2.9 बिलियन) का सबसे बड़ा कोष आईआईटी पूर्व छात्र परिषद द्वारा स्व-निर्भरता के लिए मिशन का समर्थन करने के उद्देश्य से सेटअप किया गया था.

* भारत के अपने 'मेड इन इंडिया' 5G नेटवर्क की घोषणा जुलाई 2020 में रिलायंस जियो द्वारा की थी. मुकेश अंबानी ने जुलाई के मध्य में घोषणा की कि जियो ने स्क्रैच से पूर्ण 5G समाधान तैयार किया है, जो हमें 100 प्रतिशत होमग्रोन तकनीकों और समाधानों का उपयोग करते हुए भारत में एक विश्व स्तरीय 5G सेवा लॉन्च करने में सक्षम करेगा.

* सितंबर 2020 में, टेक महिंद्रा ने घोषणा की कि उनके पास भारत में एक पूरे 4 जी या 5 जी नेटवर्क बनाने और चलाने की क्षमता है. हमने पहले ही ऐसा कर लिया है.

* अगस्त 2020 में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की कि रक्षा मंत्रालय 5 वर्षों की अवधि में 101 मदों पर आयात प्रतिबंध लगाकर आत्मनिर्भर भारत पहल के लिए तैयार है.

* रसायन और उर्वरक मंत्री डी वी सदानंद गौड़ा ने सितंबर 2020 में कहा था कि भारत 2023 तक उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा.

* कॉयर उद्यमी योजना का उद्देश्य कॉयर से संबंधित उद्योग के सतत विकास को विकसित करना है.

* 23 सितंबर 2020 को इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख के अनुसार, आत्मनिर्भर भारत एजेंडे के अधूरे सुधारों में शामिल हैं:- सिविल सेवा सुधार (स्टील फ्रेम स्टील केज बन गया है), सरकारी सुधार (दिल्ली को 57 मंत्रालयों और सचिव रैंक वाले 250 लोगों की आवश्यकता नहीं है), वित्तीय सुधार (जीडीपी अनुपात को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करना), शहरी सुधार (52 के बजाय एक लाख से अधिक लोगों के साथ 100 शहरों में), शिक्षा सुधार (हमारे मौजूदा नियामक 'विश्वविद्यालयों के निर्माण' के बजाय 'विश्वविद्यालय भवनों के निर्माण' से भ्रमित है), कौशल सुधार (हमारे प्रशिक्षु विनियम नियोक्ताओं और विश्वविद्यालय को पीछे ढ़केल रहे हैं), और श्रम सुधार (हमारी पूंजी श्रम के बिना विकलांग है और श्रम पूंजी के बिना विकलांग है) आदि सुधारों को यथार्थ-भूमि पर लाने के लिए यह मिशन प्रयासरत है.

निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि 'आत्मनिर्भर भारत मिशन' भारत को आर्थिक रूप से स्वावलंबी और स्वतंत्र बनाने के लिए एक जनजागरण क्रांति है. स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम तथा स्वतंत्र भारत के आर्थिक निर्माण को आधार प्रदान किया है. इस पहल का उद्देश्य भी देश के आर्थिक विकास को मजबूत दिशा प्रदान करना है।

अजीत कुमार भारती
न्यू वीआईपी रोड शाखा, बड़ौदा

आत्मनिर्भर भारत - समस्याएं एवं व्यवधान

आइए, पहले आत्मनिर्भरता की बात करें.

एक इंसान की हैसियत देखकर कहा जाए, कि आत्मनिर्भरता क्या है? तो इसका उत्तर अंतर्मन से यही निकलेगा कि अपनी क्षमताओं पर पूरे मन से विश्वास रख कर, उनका समुचित दोहन करके अपना जीवन यापन कुछ इस तरह से किया जाए कि अपनी खुशियों की तलाश के लिए आंचल ना फैलाना पड़े.

हम सभी को यह गर्वसहित विदित है कि हम भारतवासी हैं. एक देश के आत्मनिर्भर होने का अर्थ है कि देश के सभी वर्ग के निवासियों, पशु पक्षियों और यहां तक कि देश की भौतिक आस्तियों की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं का उत्पादन देश में ही किया जाए. इसके लिए आवश्यक आधारभूत संरचना तैयार करने में हमारे देश के नेतृत्व ने कोरोना के इस विश्वव्यापी संकट के समय देश को विपदा से उबारने के लिए 20 लाख करोड़ की महती राशि की घोषणा की है.

भारत एवं निकटवर्ती देशों की गिरती अर्थव्यवस्थाएं–अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि साल 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था 4.5 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करेगी. इसका ऐलान आईएमएफ़ की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने वॉशिंगटन में विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट जारी करते हुए किया. इससे पहले अप्रैल के अपडेट में आईएमएफ़ ने भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर शून्य प्रतिशत होने का अनुमान लगाया था.

गीता गोपीनाथ ने भारतीय अर्थव्यवस्था की इस दशा की वजह बताते हुए कहा कि कोरोना वायरस के कारण लागू किए गए लॉकडाउन की अवधि लंबी है और दूसरा कारण है कि महामारी अब भी जारी है जिसका अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा.

आईएमएफ़ ने बुरी ख़बर दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को भी दी है. इसके अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था-4.9 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी.

विश्व बैंक की 8 जून की एक रिपोर्ट, जिसने चालू वर्ष में प्रति व्यक्ति आय में 3.6 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है. इसके मुताबिक़, इस साल लाखों लोग अत्यधिक ग़रीबी का शिकार होंगे.

विश्व बैंक समूह के उपाध्यक्ष सेला पेज़रबाशियालू ने कहा, ''यह एक चिंताजनक बात है, क्योंकि इस संकट (कोरोना महामारी) का असर लंबे समय तक रहेगा और हमें वैश्विक स्तर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा.''

इसी तरह, रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने भारत की रेटिंग को घटा दिया. उनका तर्क यह था कि भारत की विकास दर एक लंबे समय तक के लिए कम रहेगी, सरकार की राजकोषीय स्थिति बिगड़ेगी और इससे वित्तीय क्षेत्र में अनिश्चितता बनी रहेगी.

अप्रैल 2020 में, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, शक्तिकांत दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार किया था कि 2020-21 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि नकारात्मक रहने की उम्मीद है.

जैसा कि हम जानते हैं कि हम कोविड-19 के नियंत्रण के लिए लगाए गए लॉकडाउन से निकलने के प्रयासों में अनलॉक के द्वितीय एवं कुछ राज्यों में तृतीय चरण से गुजर रहे हैं. ऐसे में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी का यह उद्‌बोधन उल्लेखनीय है कि इस वित्त वर्ष के पहले दो महीनों के दौरान कोविड-19 के कारण पैदा हुए व्यवधान के बाद निर्यात में तेजी से सुधार हो रहा है क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आर्थिक गतिविधियों में सुधार हो रहा है. उन्होंने इतने कम समय में इस बड़ी उपलब्धि को हासिल करने के लिए निर्यातकों की सराहना की. उन्होंने कहा कि अधिकतर विदेशी बाजारों में इस तरह की शानदार वापसी नहीं हो पाई है.

आइए, अब आशंका के बादलों से झांकती समस्याओं एवं व्यवधानों और उनके संभावित निराकरण के बारे में बात करें.

1. **समानताओं को प्रोत्साहित करने वाले नियमों-कानूनों को बढ़ावा देना** – एक विचार से भारत वर्ष की जनता को मताधिकार की तो समानता प्रदान की गई है, मगर इसी का एक वर्ग, जिसे अभिजात्य वर्ग कहा जाता है, वह सत्ता द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों को सारी जनता में समान रूप से बांटने में रजामंद नहीं है.

उसने जिस जातीय, साम्प्रदायिक, वर्गवादी और नाना प्रकार के भेदभाव मूलक चिंतन को प्रश्रय दिया है, उससे जो सामाजिक व सियासी विसंगतियां पैदा हुई हैं और इनकी आड़ में रह कर जो सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक व सियासी गतिरोध पैदा किया गया, उससे शांतिपूर्ण और सहअस्तित्व वाले समाज का सपना एक दिवास्वप्न बन कर रह गया है. ऐसे में आत्मनिर्भर भारत की सोच कितनी कारगर साबित होगी, वक्त बताएगा.

कथित भारतीय अभिजात्य वर्ग सामाजिक न्याय और साम्प्रदायिक सद्‌भाव आदि की आड़ में जिन मनोनुकूल आर्थिक हितवर्द्धक नीतियों को तरजीह देता/दिलवाता आया है, उसी के वास्ते बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से अपनी कम्पनियों की सांठ-गांठ करता/करवाता आया है.

इसके निराकरण के लिए यह सुझाव दिया जा सकता है कि, हमारी संसद व विधानमंडल, समतामूलक समाज और अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु दलित, पिछड़े, गरीब सवर्ण जैसी तमाम भेदभावमूलक और निकृष्ट व्यवस्थाओं के खिलाफ निर्णायक कदम उठाएं ताकि आत्मनिर्भर भारत बनाने के पीएम मोदी के सपनों को निकट भविष्य में न्यूनतम चुनौतियों का सामना करना पड़े.

2. **पैकेज की राशि पर्याप्त नहीं है** – कुछ लोगों की राय में सरकार के द्वारा दिया गया आर्थिक पैकेज की राशि पर्याप्त नहीं है क्यूंकि

इसमें सरकार के 'राजकोषीय' पैकेज के हिस्से के रूप में भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा पूर्व में की गई घोषणाओं को भी शामिल किया गया है.

इसके विस्तार या यूं कहें कि सरकार के द्वारा दी गईं सारी सुविधाएं, सब्सिडी एवं घोषणाओं को समेकित रूप में देखना चाहिए न कि तत्कालीन लाभ के आंकलन के रूप में.

अतः लेखक की राय में आर्थिक पैकेज की राशि समुचित है और आवश्यकता है उसके योग्य मानसिक स्वास्थ्य वाले नेताओं के नेतृत्व में समुचित उपयोग करने की.

3. **लाभ का सीधे हितग्राही के खाते में जाना** – बहुत से लाभ जो अप्रत्यक्ष रूप से ऋण या सहायता के रूप में दिए जाते हैं, वे अक्सर मध्यस्थों के द्वारा हड़प लिए जाते हैं या फिर रिश्वत की मांग द्वारा काट लिए जाते हैं. वहीं सब्सिडी, पेंशन जैसे बहुत से लाभ सीधे हितग्राहियों के खाते में पहुंच जाते हैं.

रिश्वत की प्रथा से भारतीय जनता को बचाना एक अत्यंत ज्वलंत प्रश्न है, जिसे मिटाने के लिए न सिर्फ सरकार को कठोर एवं स्पष्ट कदम उठाने होंगे बल्कि आम जनता में भी यह जागरूकता आनी आवश्यक है कि रिश्वत के याचकों को त्वरित दंड देने की प्रथा लाने की पहल करनी होगी.

3. **बैंकों का पुनर्भुगतान की अनियमितताओं से डर**–भारतीय समाज में ऋण न चुकाने की और माफ़ी की बाट जोहने की बुरी आदत आम होती जा रही है. जिसके परिणामस्वरूप बैंकों में अवमानक आस्तियां तेजी से बढ़ती जा रही हैं.

उससे होने वाले दुष्परिणामों से बचने के लिए बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता को कम ब्याज पर रिजर्व बैंक के पास जमा कर अपना जोखिम कम कर लेते हैं. हाल ही में भारतीय बैंकों ने केंद्रीय बैंक में 8.5 लाख करोड़ रुपए जमा किये हैं.

इसके निराकरण के रूप में कहा जा सकता है कि सरकार को माफ़ी देने की मनलुभावन नीतियों से दूर रह कर दूरदर्शी नीतियों को अमल में लाना चाहिए. कम ब्याज दर पर ऋण देना एवं लंबी अवधि की चुकौती की सुविधा देना आदि इसके कुछ उपाय हो सकते हैं.

इससे बैंकों में व्याप्त भय धीरे-धीरे कम होता जाएगा जिससे वे निशंक होकर ऋण वितरित कर सकते हैं.

एमएसएमई इकाइयों से संबंधित आशंकाएं– जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी विकासशील देश की रीढ़ होती हैं, माइक्रो, लघु और मध्यम स्तर की उद्योग एवं सेवा की इकाइयां. इस प्रकार की इकाइयों के विकास के लिए भारत में अनेक उपाय किए गए हैं, जिनमें से कुछ उनके वर्गीकरण को और अधिक उदार बनाना है साथ ही क्रेडिट गारंटी योजना को एक करोड़ तक विस्तृत करना आदि.

परिभाषा के नवीन मापदंड : निवेश सीमा को संशोधित किया गया है.

कंपनी के टर्नओवर को मापदंड के रूप में जोड़ा गया है.

निर्माण और सेवा क्षेत्र के बीच अंतर को समाप्त किया गया है.

हालाँकि नवीन परिभाषा के लिये अभी आवश्यक कानूनों में संशोधन करना होगा.

पूर्व एम एस एम ई इकाइयों के वर्गीकरण

मानदंड : संयंत्र एवं मशीनरी या उपकरण में निवेश

वर्गीकरण – विनिर्माण उद्यम – सूक्ष्म – निवेश 25 लाख रुपए

लघु – निवेश 5 करोड़ रुपए

मध्यम – निवेश 10 करोड़ रुपए

सेवा उद्यम

सूक्ष्म – निवेश 10 लाख रुपए

लघु – निवेश 2 करोड़ रुपए

मध्यम – निवेश 5 करोड़ रुपए

संशोधित एम एस एम् ई इकाइयों के वर्गीकरण

समग्र मानदंड (Composite Criteria) : निवेश और वार्षिक कारोबार (टर्नओवर)

वर्गीकरण : सूक्ष्म – निवेश 1 करोड़ रुपए और टर्नओवर 5 करोड़ रुपए

लघु – निवेश 10 करोड़ रुपए और टर्नओवर 50 करोड़ रुपए

मध्यम – विनिर्माण और सेवा – निवेश 20 करोड़ रुपए और टर्नओवर 100 करोड़ रुपए

नवीन परिभाषा की आलोचना : एम एस एम ई इकाइयों की नवीन परिभाषा से उद्यमों को उनके आकार के कारण प्राप्त होने वाले लाभ संबंधी समस्या का समाधान संभव हो पाएगा.

हालाँकि इस बदलाव की आलोचना की जा रही है, क्योंकि नवीन एम एस एम ई इकाइयों की परिभाषा वैश्विक स्तर के अनुसार होनी चाहिये. नवीन परिभाषा में 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को लघु माना जाएगा परंतु वैश्विक स्तर पर 75 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले उद्यमों को लघु माना जाता है.

इसके संतोषजनक समाधान के विषय में कहा जा सकता है कि भारत में एम एस एम ई की इकाइयों की परिभाषा हालांकि अभी वैश्विक स्तर की नहीं है पर सुधार की प्रक्रिया जारी है और आगे भी सुधार की संभावना बनी हुई है.

मेरे व्यक्तिगत विचार और मेरे मत से अन्य लोग भी इससे सहमत होंगे कि अगर पूरे मन से और अपनी पूरी क्षमताओं से सरकार एवं वित्तीय संस्थाओं के द्वारा प्रदान की जा रही आर्थिक सहायता का लाभ उठाते हुए, ईमानदारी से सरल शर्तों पर मिली वित्तीय सहायता के नियमानुसार पुनर्भुगतान करते हुए कार्य संचालन किया जाए तो न केवल व्यक्तिक स्तर पर विकास होगा बल्कि सामाजिक विकास के साथ-साथ देश का भी तीव्र गति से आर्थिक विकास संभव है.

राहुल गुप्ता
क्षे.का., भोपाल

Aatm Nirbhar Bharat
Initiatives & incentives

The primary aim of Aatma Nirbhar Bharat is to make the country independent and combat the competition in the global market. It is also helpful in filling the gap between demand and supply of essential goods and services in the present debilitating situation. The five pillars of Atma Nirbhar Bharat are Economy, Infrastructure, Technology driven systems, Vibrant demography and Demand. Highlights of the Abhiyan are discussed in following paragraphs.

Collateral free business loans give financial cushion to several businesses and encourages entrepreneurs to produce maximum goods within the country. Government launched ECLGS 2.00 to be utilized for 100% guaranteed collateral free additional credit at capped interest rates to;

i) Entities in 26 sectors identified by Kamath Committee in addition to the Healthcare Sector with Credit outstanding of above Rs.50 Crore upto Rs.500/- Crore as on 29.2.2020. ii) No upper ceiling of annual turnover. iii) Additional credit upto 20% of outstanding as on 29 Feb. 2020. The ECLGS 1.0 (Emergency Credit line Guarantee Scheme) is fully guaranteed and collateral free. The eligible entities under this scheme are MSME Units, business enterprise, Individual loans for Business purposes and MUDRA borrowers.

The Government of India has approved production linked incentive schemes for the following three sectors and 10 champion sectors which will be covered under the scheme:-

Mobile manufacturing and specified electronics components, critical key starting materials (KSM), Drug intermediaries and Active Pharmaceutical ingredients/Manufacturing of Medical devices.

Street vendors will get easy access to credit under a special scheme that will provide them initial working capital upto Rs.10,000/- for each enterprise. Around 50 lakh rural and urban street vendors doing business in adjoining urban areas will be benefitted and credit of Rs.5000/- crore would flow to them.

In order to provide boost to the housing sector and increase demand for steel, cement, transport and other construction material, government has extended credit linked subsidy scheme for middle income group (annual income between Rs.6 Lakh and 18 Lakh upto March 2021).

NABARD will provide additional refinance support of Rs. 30,000/- crore for meeting crop loan requirement of Rural Co-operative Banks and Regional Rurals Bank (RRBS). Limit of collateral free lending to be increased from Rs. 10 Lakhs to 20 Lakh for women self help groups supporting 6.85 Crore households.

MNREGA wage increased to Rs.202 a day from Rs.182/- to benefit 13.62 crore families.

The new Scheme Atma Nirbhar Bharat Rojgar Yojna has been launched to create new employment opportunities during Covid 19 recovery phase. The establishments which are registered with EPFO if new employees added they will be benefitted proportionately. The establishments which will be registering with EPFO after the

commencement of the Scheme will get subsidy for all new employees.

To create job opportunities for tribals in urban, semi urban and rural areas for aforestation and plantation works, Compensatory AFFORESTATION Management and planning Authority (CAMPA) funds of Rs.6,000/- Crore has been granted. One Nation One Ration Card. This Scheme has been implemented for universalization of Ration Cards to emable migrant workers and their families to access public distribution benefits from any Fair Price Shop in the country. They can get food grains at subsidized rates.

Government wants to reduce the dependence on imported items in defence, hence to boost the domestic defence manufacturing industry, government has announced a list of 101 items that they will stop importing. Thus India will only provide all the 101 items from domestic manufacturers.

The slogan Make in India should now be upgraded to Make for World with the variation Make in India for the World.

Anjali M. Yawalkar
FGMO Mumbai

डिजिटल आत्मनिर्भरता, टेक्नोलॉजी और बाजार का खेल

भारत इन दिनों डिजिटल क्रांति के दौर में है. कई दशकों तक अमेरिकन कंपनियों पर पेमेंट सिस्टम और सेटेलमेंट के लिए हमारी सम्पूर्ण निर्भरता रही. 2014 तक अमेरिकी कार्ड कंपनी वीज़ा और मास्टरकार्ड ने रूस में 90% बाजार पर नियंत्रण कर लिया था. उस दौर में रूस पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण दोनों कंपनियों ने मिलकर संपूर्ण रूसी भुगतान पारिस्थितिक तंत्र को ठप्प कर दिया. रूसी बैंकों और उनके ग्राहकों को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा. सम्पूर्ण विश्व में बड़ा हंगामा हुआ और इस घटना ने हर जागरूक देश को खुद के पेमेंट और सेटेलमेंट सिस्टम बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया.

भारत ने विगत दिनों इस दिशा में जबरदस्त सफलता हासिल की है. जेएएम (JAM²A Jandhan, Aadhaar Mobile) की आधारभूत परिकल्पना से जन्मी एक फ़िनटेक अवधारणा 'इंडिया स्टैक' ने भारत की तस्वीर बदल दी. भारत स्टैक को चरणों में लागू किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 2009 में आधार नंबरों की शुरुआत से हुई थी. साथ में 'सेवाओं का पैक' (pack of services) की शुरुआत की गई, जिसमे e-KYC, UPI, आदि सम्मिलित है. सेवाओं का यह गुलदस्ता भारत में पेमेंट और सेटेलमेंट सिस्टम की रीढ़ बन गया है.

आज 98% आबादी को आधार से पंजीकृत किया जा चुका है जिसमें 40 करोड़ बैंक खाते आधार से जुड़े हैं. यूपीआई पूरी तरह से इंटरऑपरेबल पेमेंट सिस्टम है जो आपको वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल प्लेटफॉर्म के जरिए विभिन्न बैंक खातों के बीच पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देता है. अब भारत में भुगतान के लिए एक सुरक्षित और तेज पेमेंट हाईवे उपलब्ध है.

यूपीआई अब भारत में डिजिटल भुगतान के हर दूसरे तरीके से आगे बढ़ गया है, जिसमें मासिक लेनदेन की संख्या अब एक अरब को पार कर गई है.

UPI **का** scale Amja speed अकल्पनीय है. यूपीआई प्लेटफॉर्म पर अब तक 143 भारतीय बैंक उपलब्ध हैं. दुनिया में कहीं भी न तो ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध है और न ही इतने सारे लेन-देन कभी एक ही मंच पर हुए हैं. गूगल ने अमरीकी Federal Reserve System को UPI जैसी व्यवस्था जल्द से जल्द लागू करने का सुझाव दिया है. NPCI सीईओ दिलीप असबे ने हाल में ही कहा कि यू पी आई जल्द ही देश में कैश की जगह ले लेगा.

UPI ने भारत को दुनिया में पेमेंट और सेटेलमेंट के क्षेत्र में बहुत आगे कर दिया है. भारतीय क्यूआर स्कैन कोड और विभिन्न तरीकों से धन हस्तांतरित कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश देश अभी भी पारंपरिक तरीकों का उपयोग कर रहे हैं. विकसित देशों में कार्ड से भुगतान अभी भी प्रमुख है. यूरोपीय देशों के कई हिस्सों में, चेक भुगतान अभी भी भुगतान की प्रमुख व्यवस्था है. चीन में अली पे और वीचैट हैं, जो सहज हैं लेकिन वे यूपीआई के समान सरल नहीं हैं.

भारत का विविध बाजार, भीड़-भाड़ वाले शहर और अलग-अलग जनसांख्यिकी के लिए सबसे उपयुक्त साबित हुआ. Google ने 2017 में भारत में UPI आधारित ऐप Tez (तेज) लॉन्च किया और बाद में इसका नाम बदलकर गूगल पे कर दिया. एक वर्ष के भीतर, गूगल पे में 3 गुणा से अधिक की वृद्धि और 67 मिलियन मासिक उपयोगकर्ता देखे गए. कोई सोच भी नहीं सकता, इतनी विविधता वाला देश मोबाइल फोन पर पैसा ट्रांसफर करने की तकनीक को इतनी तेज गति से स्वीकार करेगा.

पूरी दुनिया में, वित्तीय संस्थानों को FinTech द्वारा चुनौती दी जा रही है. भुगतान हस्तांतरण में हर दिन क्रांति हो रही है. ओटीपी भुगतान से लेकर क्यूआर स्कैन आधार भुगतान तक, भारत बहुत प्रगतिशील रहा है. Google पे को भारत में लॉन्च करते समय, Google ने NPCI के साथ पर्याप्त समय बिताया और UPI की शानदार वास्तुकला का पूरा लाभ लिया. phonepe, paytm, Rozarpay आदि कुछ और नाम हैं जिन्होंने काफी सफलता हासिल की है.

लेकिन हाल के दिनों में विदेशी प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है. भारतीय बैंक UPI का लाभ लेने में बुरी तरह विफल रहे हैं और हम पूरी तरह से अमेरिकी प्रभुत्व-जाल में लगभग फंस चुके हैं. आज यूपीआई जैसे घरेलू वित्तीय उत्पाद होने के बावजूद, भारतीय फिनटेक बाजार में विदेशी खिलाड़ियों का कब्जा है. शुरुआती दिनों में स्टार्टअप्स द्वारा चैंपियन बनने के बावजूद, अंततः Google और वॉलमार्ट जैसे यूएस के बिग टेक PhonePe ने UPI innovation पर प्रभावी नियंत्रण प्राप्त कर लिया है. भारत के कुल यूपीआई बाजार के लगभग 75% हिस्से पर इन दो का आधिपत्य है.

यहां तक कि शून्य एमडीआर को डिजिटल भुगतान को आगे बढ़ाने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है.

राजस्व पर इसके प्रभाव का मतलब है कि इसने भुगतान स्थान में तकनीकी दिग्गजों के प्रभुत्व को मजबूत करने में और मदद मिलेगी.

इन बड़ी टेक कंपनियों के लिए शून्य एमडीआर के बिल का भुगतान करना आसान है. जबकि आने वाले समय में छोटे भारतीय फिनटेक स्टार्टअप को बाजार में बने रहने के लिए जबरदस्त संघर्ष करना होगा. व्हाट्स ऐप द्वारा इस मैदान में उतरने से मामला और रोचक होगा. भारतीय बैंक तो इस खेल से बहुत पहले ही बाहर हो चुके हैं.

यूपीआई के साथ, भारत को अपना एक पेमेंट हाइवे तो मिला है लेकिन हमें फ़रारी भी खुद बनानी होगी. अन्यथा रूस को याद रखें.

विश्वास कुमार आनंद
क्षे.का., सूरत

Quiz on 'Aatma Nirbhar Bharat' Package

1. What is the name of the economic package launched by the central government to counter the effect of lockdown in view of COVID-19?

A) COVID-19 B) Aatma Nirbhar Bharat C) Aarthik Nirbharta D) Aarthik

2. What is the total outlay of economic package launched by central government to counter the effect of lockdown in view of COVID-19?

A) Rs 20,97,053 Cr B) Rs 20,87,153 Cr C) Rs 20,97,153 Cr D) Rs 20,87,053 Cr

3. What is the turnover requirement for classification as Medium industry in MSME?

A) < Rs 5 crore B) < Rs 10 crore C) < Rs 50 crore D) < Rs 100 crore

4. What is the definition of Small industry under MSME?

A) Investment < Rs 5 crore and Turnover < Rs 50 crore

B) Investment < Rs 10 crore and Turnover < Rs 50 crore

C) Investment < Rs 10 crore and Turnover < Rs 100 crore

D) Investment < Rs 1 crore and Turnover < Rs 5 crore

5. What is the definition of Micro industry under MSME?

A) Investment < Rs 1 crore and Turnover < Rs 10 crore

B) Investment < Rs 5 crore and Turnover < Rs 15 crore

C) Investment < Rs 1 crore and Turnover < Rs 5 crore

D) Investment < Rs 5 crore and Turnover < Rs 10 crore

6. The Aatma Nirbhar Bharat Package is approximately equal to what percent of India's GDP?

A) 5% B) 2% C) 10% D) 8%

7. What percent of entire outstanding credit will the Businesses/MSME get from banks/NBFCs as Emergency Credit Line under the Aatma Nirbhar Bharat Package?

A) 10% B) 20% C) 30% D) 40%

8. What is the corpus of Funds to be setup for MSME?

A) Rs 10,000 crore B) Rs 20,000 crore C) Rs 50,000 crore D) Rs 75,000 crore

9. What is the extended date for filing of Income Tax return for Assessment Year 2020-21?

A) 31 December 2020 B) 31 July 2020 C) 30 November 2020 D) 31 October 2020

10. Global tenders will be disallowed in Government procurement tenders upto Rs _____ crores.

A) 10 B) 100 C) 150 D) 200

11. The TDS rates for all non-salaried payments to residents, and tax collected at source rate will be reduced by what percent?

A) 20% B) 25% C) 30% D) 35%

12. The period of 'Vivad se Vishwas' Scheme for making payment without additional amount has been extended upto?

A) 31 December 2020 B) 30 November 2020 C) 31 October 2020 D) 30 September '20

13. The government aims to implement "One Nation One Ration Card" by?

A) December 31, 2020 B) January 31, 2020 C) March 31, 2021 D) April 30, 2021

14. What percent of interest subvention is being provided to Shishu MUDRA loanees?

A) 1% B) 2% C) 3% D) 2.5%

15. What is the outlay of CAMPA funds announced in the Aatma Nirbhar Bharat Package?

A) Rs 4000 crore B) Rs 8000 crore C) Rs 5000 crore D) Rs 6000 crore

16. What is the outlay of the scheme to be launched for the Formalisation of Micro Food Enterprises (MFE)?

A) Rs 1,000 crore B) Rs 10,000 crore C) Rs 1,00,000 crore D) Rs 50,000 crore

17. The Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) has been launched for?

A) Farmers B) Fisherman C) MSME D) Banking sector

18. What is the outlay of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)?

A) Rs 9,000 crore B) Rs 11,000 crore C) Rs 20,000 crore D) Rs 25,000 crore

19. What is the outlay of National Animal Disease Control Programme for Foot and Mouth Disease (FMD) and Brucellosis?

A) Rs. 14,434 crore B) Rs. 13,434 crore C) Rs. 14,343 crore D) Rs. 13,343 crore

20. What is the size of Animal Husbandry Infrastructure Development Fund?

A) Rs. 15,000 crore B) Rs. 20,000 crore C) Rs. 25,000 crore D) Rs. 30,000 crore

21. What amount has been set aside for the Beekeeping initiatives under the Aatma Nirbhar Bharat Package?

A) Rs 100 crore B) Rs 250 crore C) Rs 500 crore D) Rs 750 crore

22. What is the outlay of the "From 'TOP' to TOTAL" scheme?

A) Rs 100 crore B) Rs 500 crore C) Rs 1,000 crore D) Rs 5,000 crore

23. What is the FDI limit in the defence manufacturing under automatic route has been raised to?

A) 49% B) 51% C) 25% D) 74%

24. What additional amount will the government allocate to MGNREGS?

A) Rs 50,000 crore B) Rs 10,000 crore C) Rs 40,000 crore D) Rs 25,000 crore

25. What is the name of programme launched by government for multi-mode access to digital/online education?

A) PM eVIDYA B) Manodarpan C) PM Vidya D) eManidarpan

26. The Minimum threshold to initiate insolvency proceedings (related to IBC) has been raised to?

A) Rs 50 lakh B) Rs 1 crore C) Rs 25 lakh D) Rs 2 crore

27. What is the borrowing limit of States for 2020-21?

A) 3% B) 4% C) 5% D) 6%

28. What is the insurance cover per health worker under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Package?

A) Rs 10 lakh B) Rs 5 lakh C) Rs 50 lakh D) Rs 25 lakh

29. What amount will women Jan Dhan account holders get per month for 3 months under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Package?

A) Rs 500 B) Rs 1000 C) Rs 100 D) Rs 750

30. What amount of Ex-gratia will be given to 3 crore poor senior citizen, poor widows and poor Divyang.

A) Rs 500 B) Rs 1000 C) Rs 750 D) Rs 1500

Please find the answers of this Quiz in this issue only. - Editor

U Sethupitchai
R.O., Madurai

प्रकृति का वरदान लद्दाख

लद्दाख, जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व में स्थित एक ऊंचा पठार है जिसे हाल ही में 31 अक्टूबर, 2019 को भारत के एक संघ शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया. सिंधु नदी के किनारे स्थित लद्दाख अपने गगनचुंबी पहाड़ों, सुदंर झीलों, आकर्षक मठों के माध्यम से हमें प्रकृति की सुदंरता को करीब से देखने का अवसर प्रदान करता है. उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत से घिरे लद्दाख के उबड़-खाबड़ रास्तों पर बाइक चलाना, सिंधु नदीं में रिवर राफ्टिंग करना, पर्वतों पर चढ़ाई करना, कड़कती ठंड में गर्म खाद्य पदार्थ विशेषत: टिगमों, तिब्बती थुक्सा सूप का आनंद लेना, हेमिस गोम्पा त्योहार में भाग लेना, बर्फ के चादर पर चलना अर्थात जंस्कार नदी के ऊपर चादर ट्रैक जैसी गतिविधियां अद्वितीय आनंद की अनुभूति कराने में कोई कमी नहीं रहने देती. यदि कम शब्द में कहें तो अपनी चिंताओं को दरकिनार कर सुंदरता की गोद में घूमने का मौका हमें लद्दाख में मिलता है.

- धीरज रजक
कें.का., मुंबई

SELF - RELIANT INDIA INDEPENDENT INDIA

Self-reliance is not only about being self dependant or self made but it is more about creating a sense of self-esteem. A sub-continent like India, full of diversity and a huge population of 133 crores has no option than being a self-reliant nation. Being Atmanirbhar can serve the diverse needs of its population and provide them with choices. A content nation can also contribute to the welfare of other counties with a sense of self-pride. Globally there has been a geo-political, geo-economic and geo-strategic shift due to the pandemic. The COVID-related pressures and the unfortunate border tensions with its largest import partner, China, present a rare opportunity for India to reinvent itself, economically.

'Vocal for Local' was the call given by our Prime Minister in May 2020. His aim was to convert India, Asia's third largest economy into a global nerve centre of supply chains. This essentially means, not only to buy and use local products, but also to take pride in promoting them. Centre has already announced a well-considered programme, the Atmanirbhar Bharat Abhiyan (ANBA), as part of the post-pandemic economic revival package. Rs 20.00 lakh crore (10 per cent of India's GDP) was earmarked for this purpose.

The global pandemic, Covid-19 took very little time to spread and show it's devastating effect all across the world economy. International trade has been constricted and global supply chains have, by and large, been disrupted. Each nation has been left to fend for itself. India's dependence on other countries has been exposed in several areas. The country should now refocus on manufacturing, and be self reliant.

Most of our imports of essential items - raw materials, components and intermediates required producing finished goods by a large number of enterprises across several sectors, including MSMEs which are imported from China. For example, the pharmaceuticals sector imports nearly 70 per cent of its raw material and drug intermediates. So there is bound to be serious apprehensions on this issue

The thought of reviving the local born out may seem unrealistic enthusiasm at the very outset. Of course, it may not be feasible to replace all foreign imports in the near future. It may also be debatable if the end goal is to replace the entire chain of imports from a country (China). Moreover, as some economists apprehend, a populist demand for dumping all that is of Chinese origin, may be forgotten soon. However experts and industrialists do assert that the ANBA is an excellent initiative and gives India the opportunity to embark on its self-reliance drive.

Immediate fallout of Vocal for Local

One immediate fallout of these measures will be creation of large scale employment opportunities for both the skilled and unskilled workforce. A stronger manufacturing base will also lead to positive spinoffs related to the supply-purchase of local raw material and capacity building of allied manufacturing units.

There are many other things going for the ANBA. It has a well-defined charter. The scheme has met with little criticism. Indeed, a number of Opposition leaders including Chief Ministers of a few states have supported it. There seems to be no shortage of political will to execute the mission. Even, then implementing

the reforms would require innovative ways to overcome day to day obstacles and challenges.

Few bottlenecks in ANBA

Over 90 percent of the Indian workforce operates in the informal sector. It means irregular and uncertain earnings, lack of job and social security, and lack of appropriate working conditions. The reality of an Atmanirbhar Bharat cannot coincide with such a large informal sector. The recent Covid-19 crisis has exposed the vulnerabilities of the informal workers. The Covid-19 pandemic has left them in the lurch - without food, income and in several cases, even shelter. The picture that is painted contradicts the tenet of self-reliance. Nevertheless, the Atmanirbhar Bharat Abhiyan falls short of announcing a consolidated, comprehensive set of measures for social protection apart from some isolated initiatives like affordable social rental housing which appear to be too little too late.

So ANBA should not be 'inward looking' but aimed at 'making us the global nerve centre of the supply chains'

Some key suggestions for successful implementation of ANBA

Strong action plan is required to be drawn by the Niti Aayog listing all possible categories of targets under the ANBA and the Vocal for Local Mission. A monitoring agency to review and suggest course correction to ensure that no delay is allowed to build up.

Each State/UT along with each District (or a group of districts) is to develop an action plan in consonance with the above mentioned action plan - with a similar agenda and a robust mechanism. A separate organisation created by each state will be responsible for the implementation of the action plan, as well as running all related operations on a day-to-day basis. It will also conduct regular studies to identify local and global market trends and invite competitive solutions to meet market demands.

Role of MSME in successful implementation of ANBA

MSME (micro, small and medium enterprise) sector in India can play a significant role in achieving the vision of self-reliant India supported by a three-pronged strategy that includes financial stability, availability of skilled labour in MSME clusters, and market competitiveness of their products to achieve import substitution as well as exports.

These enterprises have, by and large, been seen as struggling for survival. but the reforms announced as part of the ANBA - collateral free credit, expanding the scope of the sector, an online market place exclusively for it, the proposal that governments will pick up equity stakes in enterprises that show growth potential - should put them on a stronger footing.

This is a big challenge in terms of availability of skilled labour to the MSMEs in and around these urban centres. Ensuring the availability of skilled labour by either skilling local workforce or making the conditions lucrative for the migrant labour to come back is essential for the growth of MSMEs. Carefully planned interventions with a robust implementation plan can ensure the revival and strengthening of the sector, and will also in the process restart the economic engine in a big way.

First and foremost, making an economy self-reliant must at best refer to a medium-term horizon if not the longer term. It surely is not something that can be achieved in the short run. Hence, endeavours to make the country a manufacturing hub and the generation of employment opportunities must go hand in hand.

Importance of Farmers and Farm sector in successful implementation of ANBA

Farmers are one of the pillars of an economy. They are considered as the Anadatta or food provider. The economic health of a farmer matters significantly to whether an economy can be regarded as self-reliant. The greater ambition for a self-reliant economy is to transform the farmer into an AGRIPRENEUR. India's farmers are bound by the shackles of low productivity, low incomes, lack of access to institutional credit, indebtedness etc. They are reeling under the burden of a fragmented agricultural marketing ecosystem and climatic uncertainties and vagaries of nature. A self-reliant farmer is fundamental to the vision of a self-reliant India.

Every crisis brings to the fore an opportunity; the current one too has created an urgent need to focus on the ANBA. While all of the plans under the overarching theme of the Atmanirbhar Bharat Abhiyan paint an ambitious picture of a self-reliant India, the catch lies in implementation. Will corruption, red-tapism, competitive federalism, failure of co-ordination between various authorities, overlapping jurisdictions and bureaucratic hurdles in general allow the dream of Atmanirbhar Bharat to become a reality? The concept of maximum governance minimum government is the key to this ambition. If India succeeds in crossing this bridge, then a new ray of hope awaits on the other side.

Subrat Kumar Dhal
R.O., Raipur

आत्मनिर्भर महिलाएँ - जागरूक महिलाएँ

समय बदल रहा है, परंपराएं बदल रही हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य भी बदल रहे हैं. भूमंडलीकरण के प्रभाव से नए दृष्टिकोण और नए मूल्य स्थापित हो रहे हैं. इन्हीं नए मूल्यों में जगह बना पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता. जैसाकि सभी जानते है कि भारतीय समाज में आजादी से पहले और आज़ादी के बाद भी महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, किन्तु फिर भी महिलाओं ने अपने दम पर परिस्थियों को बदलते हुए, अपने आप को, अपने समाज को और अपने भविष्य को बदला है. अपने आपको आत्मनिर्भर बनाया है. इस बात को स्वीकारना ही होगा कि आज की नारी ने जिस प्रकार से हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी प्रस्तुत की है, वह वाकई काबिल-ए-तारीफ है. पहले के समय में महिलाओं को केवल घर के दायरे तक सीमित रखा जाता था. घर के किसी भी फैसले से लेकर किसी भी मामले में उसकी कोई उपस्थिति नहीं होती थी. किन्तु यह महिला है जनाब, हार मानना कहां जानती है.

पहले के समय में एक कहावत होती थी लड़कियां पेड़ पर नहीं चढ़ सकतीं, क्योंकि समाज में यह मान्यता है कि ऐसा होने पर हरे वृक्ष सूख जाते हैं. महिलाओं को डराने के लिए ऐसी बातें कही जाती थीं. असल में हिम्मत वाली लड़की ही पेड़ पर चढ़ सकती है. इस तरह डराकर और विरोध करके उसकी हिम्मत को तोड़ा जाता है. क्योंकि पेड़ पर चढ़ने वाली स्त्री के डर से पुरुष की हिम्मत सिहर जाती है. पुरुष प्रधान समाज ने नारी को रोकने के लिए ऐसी ही युक्तियों को समय समय पर समाज में लागू किया है.

देश बदल रहा है. महिलाओं की दशा में सुधार हो रहा है, समय के साथ-साथ नारी शक्ति और सशक्त होती जा रही है. परिवर्तन प्रकृति का नियम है यह बात तो सत्य है, किन्तु परिवर्तन का क्या परिणाम हुआ है और क्या होगा और उस परिवर्तन को आने वाली पीढ़ी किस प्रकार स्वीकार करती है और इससे क्या सीख लेती है, ये बात अधिक महत्त्व रखती है. देखा जाए तो हर युग में प्रतिभाशाली महिलाएँ रही हैं और हर युग में उन्होंने अपनी प्रतिभा से समाज में उदाहरण प्रस्तुत किया है. जैसे सीता, सावित्री, द्रौपदी, गार्गी आदि पौराणिक देवियों से लेकर रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्या बाईहोल्कर, रानी चेनम्मा, रानी पद्मिनी, हाड़ी रानी आदि महान रानियों से लेकर इंदिरा गाँधी और किरण बेदी से लेकर सानिया मिर्ज़ा आदि आधुनिक भारत की महिलाओं ने भारत को विश्व भर में गौरवान्वित किया है और महिलाओं ने धरती पर ही नहीं अपितु अन्तरिक्ष में भी अपना परचम लहराया है. इनमें सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला प्रमुख हैं. कल्पना चावला ऐसी पहली भारतीय महिला थीं जो स्पेस में गई थीं. कल्पना बतौर मिशन स्पेशलिस्ट और प्राइमरी रोबॉटिक आर्म ऑपरेटर के तौर पर स्पेस गई थीं. भारत जैसे देश में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि हमारे देश की नारी ऐसे स्पेस में भारत का झण्डा लहराएगी. देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी 'जिन्हें 2003 में यूनाइटेड नेशन्स सिविल पुलिस एडवाइजर के तौर पर चुना गया.

इस बात में कोई दो राय नहीं है कि किसी इंसान में जब जागरूकता आती है तो वह स्वतः आगे बढ़ता है. परिस्थियाँ चाहें कितनी भी कठिन हो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा ही महिलाओं के साथ हुआ. सदियों की गुलामी, पीड़ा, त्रासदी ने महिलाओं को ऐसा खड़ा किया कि पूरी दुनिया उनका लोहा मान गई. ऐसी ही महिलाओं ने अपने साथ-साथ देश का भविष्य भी बदल डाला है. आज हर क्षेत्र में चाहे वह शिक्षा का हो या व्यवसाय का हो या राजनीति या खेल, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जहां महिलाएं

कामयाब न हुई हों, आत्मनिर्भर न बनी हों. ऐसी महिलाएं खुद तो आत्मनिर्भर हुई हीं, साथ-साथ अपने परिवार को भी आगे बढ़ाया है. महिलाएँ बेहद भावुक स्वभाव की होती हैं और इन्हीं भावुकता के चलते कई बार उन्हें पुरुषों से कमतर समझा जाता है. उनके हौसलों को तोड़ने के प्रयास किये जाते हैं. कई बार समाज और दुनिया उनके पंखो को काटने में सफल होती है तो कई बार दुनिया उनके हौसलों और बुलंद खयालों के सामने अपना सर झुकाती हैं.

कुछ ऐसी ही महिलाओं ने अपने देश को आगे बढ़ाने में भरपूर योगदान दिया. कुछ ऐसी ही महिलाओं में एक नाम है-इंदिरा गांधी का. भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1966 से 1977 तक देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला. इंदिरा को 'वुमेन ऑफ द मिलेनियम' का खिताब दिया गया था. इंदिरा गांधी को सम्पूर्ण देश एक 'आइरन वुमेन' के नाम से जानता है, जिसने राजनीति जैसे क्षेत्र, जिसमें पुरुषों का वर्चस्व होता है, को तोड़ कर देश सेवा की और लोगों के दिलों पर राज किया.

आत्मनिर्भरता की यह कहानी केवल शहरों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि गाँव में भी नारी जाति ने अपने नाम का डंका बजवाया है. किसी भी गाँव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना कोई आसान काम नहीं होता किन्तु इसे झूठ साबित कर पूर्णिया गाँव की गरीब महिलाओं को संगठित कर आत्मनिर्भर बनाया गया और इसी का नतीजा है कि जिले में अब तक तीन लाख महिलाएं आत्मनिर्भर हो चुकी हैं. अब ये महिलाएं अपना परिवार तो चला रही हैं, साथ ही दूसरी जगहों पर जाकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग भी दे रही हैं. कमाल यह है कि कोई महिला जागरूक किसान है, तो किसी महिला को मुर्गी पालने में महारथ है. इन्हीं महिलाओं ने मक्के का व्यापार किया और पहले ही सीजन में बिज़नस को एक करोड़ बीस लाख तक पहुंचा दिया. इन महिलाओं की असल ज़िन्दगी कई पेचीदा मोड़ों से भरी

हुई हैं और ये महिलाएँ आपको किसी नॉबेल की हिरोइन की ही तरह जिंदगी से जूझते हुए, कभी ज़िंदगी को ज़िंदादिली से जीते हुए, तो कभी हताश होकर गिरके फिर उठते हुए नज़र आएँगी.

यह सही है कि हर युग में महिलाओं ने अपना परचम लहराया है, फिर भी उन्हें हर युग में भेदभाव और उपेक्षा का सामना करना पड़ा है. महिलाओं के प्रति भेदभाव और उपेक्षा को केवल साक्षरता और जागरूकता पैदा कर ही खत्म किया जा सकता है. आज भारत में हर 8वां पायलेट एक औरत है और तो और यूएन ने 21वीं सदी को महिलाओं की सदी घोषित किया है. महिलाओं की साक्षरता, उनकी जागरूकता और उनकी उन्नति न केवल उनकी गृहस्थी के विकास में सहायक साबित होती है बल्कि उनकी जागरूकता एवं साक्षरता देश के विकास में भी अहम् भूमिका निभाती है. इसीलिए सरकार द्वारा आज के युग में महिलाओं की शिक्षा और उनके विकास पर बल दिया जा रहा है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद की जा रही है. सरकार ने इनको बल देने के लिए कई योजनाओं भी शुरुआत की हैं. महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और अन्याय के प्रति आवाज उठाने की हिम्मत प्रदान करना ही असल में नारी सशक्तिकरण है. तभी असल में उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा.

एक सुखी जीवनयापन के लिए किताबी ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान भी अति आवश्यक है जोकि हमारे कौशल में निखार लाता है और हमारे व्यावहारिक ज्ञान और अनुभव में वृद्धि करता है. व्यवहारिकता, अनुभव और कौशल विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी जीवनयापन में सहायता करता है. ऐसा नहीं है कि अशिक्षित महिलाओं में कौशल एवं हुनर कम है. कृषि, कुटीर उद्योग, पारम्परिक व्यवसाय, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय जैसे कार्यों से महिलाओं को अपने इस हुनर को बाहर लाना है और देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाना है.

पुरूषों की भाँति महिलाएँ भी देश की समान नागरिक हैं और उन्हें भी स्वावलम्बी होना चाहिये ताकि समय आने पर वह भी काम कर सकें और अपने परिवार को चलाने में मदद कर सकें. यही जागरूकता ही तो उनके, उनके परिवार के व देश के विकास को गति देगी एवं एक नई दिशा देगी. एक खुशहाल भविष्य की कामना करते हुए सभी नारी जाति इस बात का संकल्प कीजिये-**मैं अपने हुनर को पहचानूँगी और स्वावलम्बी बनकर दूसरों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनूँगी, मैं खुद एक आत्मनिर्भर लड़की हूँ जो कि घर और ऑफिस दोनों को मैनेज करती हूँ. ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं वकील और ना ही अध्यापिका. पर हाँ मैं शिक्षित हूँ और काम करती हूँ और इस बात से खुश हूं कि मैं आत्मनिर्भर हूँ.**

ऊषा
डीआईटी., पवई, मुंबई

आत्मनिर्भर महिलाएं/जागरूक महिलाएं

नारी तुम केवल श्रद्धा हो,
विश्वास रजत नग पगतल में।
पीयूष स्रोत सी बहा करो,
जीवन के सुंदर समतल में ।।

जयशंकर प्रसाद जी ने इन सुंदर पंक्तियों में महिलाओं की सौम्यता का वर्णन किया है. महिला, इस शब्द को सुनते ही हमारे मन में उसके विभिन्न रूपों की छवि उभरने लगती है. महिला अर्थात एक मां, एक बहन, एक पत्नी व एक बेटी इत्यादि रूप में अपनी भूमिका निभाती है. स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों के पश्चात भी हम महिलाओं को केवल इन्हीं रूपों में देखते हैं.

पहले महिलाएं केवल घरों में रहती थीं. उन्हें घर से बाहर जाना, पढ़ना-लिखना, खेलना-कूदना, पुरुषों की तरह बाहर काम करने जाना, इन सबकी आजादी नहीं थी. परंतु परिवर्तन प्रकृति का नियम है. आज हमारा देश बदल रहा है और इस बदलते परिपेक्ष्य में महिलाओं की स्थिति में भी सुधार आ रहा है तथा समाज के विभिन्न वर्गों का दृष्टिकोण, महिलाओं के प्रति अपनी रुढ़िवादी सोच भी समय के साथ बदल रही है. इतना ही नहीं, समय के साथ आज की नारी शक्ति और अधिक सशक्त हो रही है.

महिलाओं का विकास देश का विकास है क्योंकि स्त्री की उन्नति पर ही राष्ट्र की उन्नति निर्भर है. आज दुनिया का कोई भी क्षेत्र स्त्रियों की पहुंच से अछूता नहीं रहा है. महिलाओं ने अपनी मेहनत के बल पर अपनी प्रतिभा का लोहा हर क्षेत्र में मनवाया है और स्वयं को समाज में एक महान शक्ति के रूप में स्थापित किया है.

सशक्त नारी समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकता :

हमारे ग्रंथों में नारी के महत्व को बताते हुए कहा गया है **'यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता:' अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं.** महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहले हमें उनके अधिकारों और उनके मूल्यों को हनन करने वाली उस दानवी सोच जैसे भ्रूण हत्या, अशिक्षा, दहेज प्रथा, यौन हिंसा, असमानता, वेश्यावृत्ति, मानव तस्करी, स्त्री के प्रति घरेलू हिंसा आदि को खत्म करना होगा. विश्वभर में प्रतिभाशाली महिलाओं के योगदान के लिए उनको सम्मानित करने के साथ एवं महिलाओं के प्रति समाज में जागरूकता लाने के लिए सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (आठ मार्च), मातृ दिवस जैसे अन्य कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं. ताकि विश्व भर में महिलाओं के प्रति जन चेतना का प्रसार किया जा सके. इसके साथ ही लड़कियों की शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है ताकि महिलाएं पढ़-लिख कर अपनी जिम्मेदारी स्वयं के प्रति, समाज व राष्ट्र के प्रति अच्छे से निभा सके. महिला एक मां, बहन, पत्नी, बेटी, बहू के रूप में अपने कर्तव्य का यथोचित पालन करने के साथ सशक्त समाज के निर्माण में अपनी विशेष भूमिका निभाती है. उन्हें आर्थिक दृष्टि से और भी अधिक मजबूत बनाने के लिए विशेष वित्तीय सहायता तथा छोटे-छोटे घरेलू कारोबार के द्वारा उनको अधिक मजबूती दी जा रही है.

सशक्त नारी बनने के लिए आत्मनिर्भर होना अत्यंत आवश्यक है. आत्मनिर्भरता अर्थात स्वयं पर निर्भर होना, क्योंकि जब आत्मनिर्भरता हमारे जीवन में आती है तो यह हमें भीड़ से हटकर सोचने की प्रेरणा देती है. एक ऐसी प्रेरणा है जिसके द्वारा हम कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं. महिलाओं को चाहते या ना चाहते हुए भी कहीं न कहीं अपने माता-पिता व पति पर निर्भर रहना पड़ता है. एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता सभी को है इसलिए अपने जीवन को सम्मान पूर्वक जीने और आत्मनिर्भर बनने के लिए महिलाएं प्रयासरत हैं. उदाहरण के तौर पर- ग्रामीण विकास, बिहार विभाग की सोसायटी जीविका, गांव की महिलाओं के लिए अग्रसर कार्य कर रही है. इसी क्षेत्र के पूर्णिया गांव की तीन लाख महिलाएं संगठित होकर आत्मनिर्भर बन चुकी हैं. यह सब महिलाएं अपने घर के कामकाज के साथ बाहर जाकर महिलाओं को आत्मनिर्भर होने की ट्रेनिंग भी दे रही हैं. उन्होंने महिलाओं के जीवन में बदलाव की एक नई बुनियाद रख दी है. ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इन महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के जरिए कम दरों पर ऋण उपलब्ध हो रहे हैं जिससे महिलाएं अपना खुद का रोजगार विकसित कर रही हैं. **मनरेगा योजना-महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना** भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफी कारगर साबित हो रही है. इस

योजना का उद्देश्य जिले के अंतर्गत दो हजार महिलाओं को पूरे वर्ष काम देना है.

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना–इस योजना के अंतर्गत शहर में करीब साढ़े सात हजार महिलाएं आत्मनिर्भरता के साथ कार्य कर रही हैं. नए उद्यमों के क्षेत्र में भी महिलाओं ने अपनी भागीदारी दी है. छोटे-छोटे ग्रामीण स्तर से लेकर बड़े-बड़े शहरों में महिलाएं कुछ नया करके अपनी अलग ही पहचान बना रही है. इसके लिए कुछ सरकारी योजनाएं जैसे अन्नपूर्णा स्कीम, महिला उद्यमियों के लिए स्त्री शक्ति पैकेज, सेंट कल्याणी स्कीम एवं मुद्रा योजना आदि इन महिलाओं के लिए काफी मददगार सिद्ध हो रही हैं, जिसके अंतर्गत भारत सरकार व बैंक के जरिए उन्हें ऋण की राशि दी जा रही है. कोरोना काल में महिलाएं घर पर रहकर ही रंग बिरंगी डिजाइनर मास्क बनाकर आत्मनिर्भर बनने के साथ देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं.

महिला सशक्तिकरण एवं जागरूकता – महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य है कि महिलाएं अपने लिए निर्णय लेने में सक्षम हो, उनके अंदर अन्याय के प्रति आवाज उठाने की हिम्मत हो, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता हो, अपने अंदर छुपी हुई शक्ति से स्वयं का साक्षात्कार कराना तथा स्वयं के अंदर एक ऐसी शक्ति का प्रवाह करना है जिससे वह अपने फैसले स्वयं ले सकने में सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण है.

भले ही आज के समाज में कई भारतीय महिलाएं उच्च पदों पर आसीन हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर इत्यादि लेकिन आज भी उसकी कार्यक्षमता एवं योग्यता पर संदेह किया जाता है. इसलिए महिला जागरूकता के साथ समाज में विशेषत: पुरुष वर्ग को महिलाओं की क्षमताओं एवं कार्य कुशलताओं के प्रति जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है. विश्व में जिस देश ने भी महिलाओं की शक्ति एवं कार्यकुशलता का सम्मान किया है वह देश आज विकसित होकर उन्नति की राह पर सबसे आगे है. जैसे-जैसे समय बदला, विकसित हुआ, महिलाओं को अपने अंदर छुपी हुई शक्ति का एहसास हुआ. तभी महिला सशक्तिकरण की धारणा समाज के सामने उभर कर आने लगी थी. महिला सशक्तिकरण के कारण महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रही हैं. वे समाज में अपनी पहचान बना रही हैं. वे लिंग (स्त्री/पुरुष) अनुपात से ऊपर उठकर सोचने लगी हैं. विश्व भर की महिलाओं की बात करें तो आज वे जिस मुकाम पर हैं वहां पर पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत व संघर्ष किया है.

भारत की महिला सशक्तिकरण के मामले में आज पीछे नहीं है. लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर महिलाएं आज भी घर से बाहर निकलकर महफूज नहीं है. इसके लिए सरकार भी महिला सशक्तिकरण पर जोर देने के लिए कई योजनाओं के साथ महिला सुरक्षा के लिए- आत्मरक्षा शिविर, कानूनी शिक्षा, सेमिनार, विचार गोष्ठी आदि प्रयासों से महिलाओं को संगठित तथा आत्मनिर्भर करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. पिछले कई सालों में महिलाओं के साथ लैंगिक असमानता और बुरी प्रथाओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा संवैधानिक और कानूनी अधिकार बनाकर उनकी सामाजिक स्तर को और अधिक मजबूत किया गया है और आज का समाज महिलाओं के बारे में अधिक जागरूक है इसलिए स्वयंसेवी समूह और एनजीओ आदि संस्थाएं इनके लिए सफलतापूर्वक कार्य कर रही है. सरकार महिलाओं के लिए- 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना', महिला हेल्पलाइन योजना, उज्जवला योजना, महिला शक्ति केंद्र आदि योजनाएं बनाकर महिलाओं के हित में बढ़-चढ़कर जिम्मेदारी का निर्वाह कर रही है और महिलाएं चार दीवारों से बाहर निकलकर देश के प्रति महत्वपूर्ण कार्यों में सफल भागीदारी कर रही है. महिलाओं को सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाने के लिए 'आर्ट ऑफ लिविंग' में भी महिला सशक्तिकरण पर विशेष छह कार्यक्रम आरंभ किए हैं जैसे-आर्थिक स्वतंत्रता, कन्या शिक्षा, एचआईवी/ऐड्स, जल कार्यक्रम, नेतृत्व संवर्धन और सामाजिक सशक्तिकरण. ये सभी कार्यक्रम महिलाओं के आत्मसम्मान, आंतरिक सजगता और रचनात्मकता की दृष्टि से ठोस आधार प्रदान करते हैं. किसी ने ठीक ही कहा है कि महिलाएं जब अपने आपको पारंपरिक सोच की जंजीरों को स्वयं तोड़ने लगेंगी, तो विश्व की कोई भी शक्ति उन्हें रोक नहीं सकेगी.

जागरूक महिलाएं ही संपूर्ण समाज को एक नई दिशा दे सकती हैं.

महिलाओं के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है. हमें यह बात समझनी होगी कि महिलाएं अनपढ़ होते हुए भी घर को इतने अच्छे से संभाल सकती हैं. अगर वही महिलाए पढ़ी-लिखी होगी तो वह समाज व देश को कितने अच्छे से संभाल पाएगी.

आज हमारे भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार तो आया है लेकिन जिस प्रकार से पुरुषों की तरह महिलाएं भी देश की समान रूप से नागरिक हैं. उन्हें भी पुरुषों के समान स्वाबलंबी होना चाहिए ताकि समय आने पर वह अपने परिवार की ज़िम्मेदारी के साथ-साथ अपनी कार्यकुशलता से आर्थिक रूप में भी सहयोग बन सकें. उनकी जागरूकता एवं स्वावलंबन ही उनके परिवार व देश के विकास को नई दिशा देगी. जरूरत है अपनी नई सोच के बंद दरवाजों को खोलकर नई रोशनी को अंदर आने देने की और उस नई रोशनी में अपना प्रतिबिंब देखने की! फिर उस प्रतिबिंब को निहारकर अपने आपको निखारने की! अपने अस्तित्व को पहचानने की, उसे बनाए रखने की और जागरूकता के साथ आत्मनिर्भरता की तरफ एक सफल कदम बढ़ाने की...

जिम्मेदारी संग नारी, भर रही उड़ान ।
ना कोई शिकायत, ना कोई थकान ।।

प्रवीण कुमार
स्टा.म.वि., बेंगलुरु

आत्मनिर्भर भारत - लोकल के लिए वोकल

आत्मनिर्भर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, आत्म और निर्भर. आत्म का अर्थ होता है स्वयं एवं निर्भर अर्थात आश्रित. अत: जो व्यक्ति स्वयं के पुरुषार्थ पर आश्रित है वही आत्मनिर्भर कहलता है. इतिहास के पन्नों को पलटे तो हम पाएंगे कि, भारतवर्ष सदा ही आत्मनिर्भर रहा है. हमारी कला, संस्कृति, हमारे कुटीर उद्योग, खेती, पशुपालन इत्यादि ने हमें हमेशा से आत्मनिर्भर बनाए रखा है. ऐसा कहा जाता है कि समय का चक्र वहीं पलट कर वापस आता है जहाँ से शुरू हुआ था. वर्तमान समय हमें यही दिन दिखा रहा है. कोरोना महामारी ने हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में बहुत कुछ सिखाया है. लॉकडाउन के दौरान आयात और निर्यात लगभग बंद हो गए थे. अचानक आए संकट ने खाने-पीने की वस्तुओं की उपलब्धता को कम कर दिया एवं उसकी कीमतों को बढ़ा दिया. आवश्यक वस्तुएं जैसे-खाद्य सामग्री, औषधियाँ, पीने का पानी, आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता जन-जन तक पहुँचाना एक चुनौती बन गयी. इन परिस्थितियों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान आत्मनिर्भरता के महत्व की ओर आकृष्ट किया है.

हालांकि आत्मनिर्भरता शब्द नया नहीं है. ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग द्वारा बनाए गए सामानों और उसकी आमदनी से आए पैसों से परिवार का खर्च चलाने को ही आत्मनिर्भरता कहा जा सकता है. कुटीर उद्योग या घर में बनाए गए सामान को अपने आस-पास के बाजारों में ही बेचा जाता है. यदि किसी की सामग्री अच्छी गुणवत्ता की हो तो, अन्य जगहों पर भी इसकी मांग होती है. एक आम भाषा में कहा जाए तो कच्चे माल से जो सामान घरों में हमारे जीवन के उपयोग के लिए बनाया जाता है, उसे हम लोकल सामग्री कहते है पर सत्य यही है कि यही आत्मनिर्भता का एक रुप है. हम सहजता से मिल जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों और कच्चे माल द्वारा वस्तुओं का निर्माण कर, उसे अपने आसपास के बाजारों में बेच सकते हैं. इससे हम स्वयं के साथ-साथ, आत्मनिर्भर भारत की राह में अपना योगदान दे सकते हैं और हम सब मिलकर एक आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण के सपने को साकार करने में सहयोग कर सकते हैं.

हममें से प्रत्येक व्यक्ति चाहता है आत्मनिर्भर बनना, क्योंकि आत्मनिर्भरता, आत्म सम्मान से जुड़ा हुआ भाव है. जो व्यक्ति आत्मनिर्भर है, वास्तव में वही स्वाभिमानी एवं आत्मसम्मानी व्यक्ति है. देश का प्रत्येक नागरिक यदि आत्मनिर्भरता को अपना लक्ष्य बनाता है तभी हम देश की आत्मनिर्भरता के बारे में सोच सकते हैं. आत्मनिर्भरता का पाठ हमें स्वयं महात्मा गांधी जी ने पढ़ाया था. गांधी जी का दर्शन हमें बताता है कि, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करके ही हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं. स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, भारतीयों ने ऊंच-नीच, बड़े-छोटे, जाति-धर्म का भेद भुलाकर, स्वदेशी आंदोलन चलाया और उसमें पूरी-पूरी सफलता प्राप्त की.

कोरोना महामारी के कारण, लगभग पूरे विश्व की अर्थ व्यवस्था पर जैसे विराम लग गया और न केवल गरीब, मध्यम वर्ग बल्कि बड़े-बड़े पूंजीपतियों को भारी आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा. रोजदारी पर काम करने वाले मजदूरों के लिए यह समय अत्यंत मुश्किल भरा रहा है. उन्हें खाने-पीने तक की परेशानी आ गयी. न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाने के कारण उन्होंने पैदल ही अपने राज्य की ओर पलायन करना शुरू कर दिया.

इसी दौरान हमने देखा कि चीन ने भारत के डोकलाम सीमा क्षेत्र पर कब्ज़ा करने की कोशिश की. जिसमें भारत के लगभग बीस जवान शहीद हो गए. सीमा के इस विवाद में भारत के सैनिकों को पहुंची क्षति के कारण देश के हर कोने से चीनी सामान को बैन करने की माँग के साथ ही चीनी सामान को बंद कर दिया गया और प्रधानमंत्री ने सारे देश को आत्मनिर्भर बनने का मंत्र दिया. चूंकि हमारा देश चीन में बनी वस्तुओं पर एक बड़े स्तर पर निर्भर था अत:, उन्होंने सभी भारतवासियों को संबोधन किया कि वे घरेलू उत्पाद का इस्तमाल करें ताकि हमारा राष्ट्र मज़बूती के साथ खड़ा हो सके.

हमारे देश को चहुं ओर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है. एक तरफ महामारी से मरते देशवासी, दूसरी तरफ भूख से मरते जन-मानस, तीसरी ओर सीमा पर घुसपैठ तो चौथी तरफ गिरती अर्थव्यवस्था. देश चारों ओर से संकट से जूझ रहा था. इसी दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने '**वोकल फॉर लोकल**' का नारा दिया. जिसका अर्थ है स्थानीय या लोकल वस्तुओं का उपयोग करना एवं उसके लिए प्रचार-प्रसार करना. उन्होंने संकट की इस घड़ी में सभी को आत्मनिर्भर बन राष्ट्र की सेवा और तरक्की में योगदान देने की अपील की. देश को आत्मनिर्भर बनाकर ही हम उसे तरक्की के लिए आगे खड़ा कर सकते है. महात्मा गांधी के दिखाये आत्मनिर्भरता के सपने को पूरा करने का बीड़ा उठाया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने! आत्मनिर्भरता न केवल हमारे स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देगी बल्कि बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार भी देगी. भारत के आत्मनिर्भर होने से देश को कई फायदें होंगे. आत्मनिर्भर भारत के चलते हमारे देश में उद्योगों में वृद्धि होगी. हमारे देश को अन्य देशों से कम सहायता लेनी होगी, नौजवानों के लिए रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, गरीबी कम होगी, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, देश में वस्तुओं का भंडारण बेहतर तरीके से किया जा सकता है. हम आयात कम करके निर्यात को बढ़ा सकते हैं और विकास के ऐसे ही कई अवसर आयेंगे.

आत्मनिर्भरता की इस यात्रा में प्रधानमंत्री जी ने पाँच मूल मंत्र दिये है-इंटेंट अर्थात इरादा करना, इंक्लूसिव या समावेश करना, निवेश या इनवेस्टमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर या

सार्वजनिक ढाँचे को मज़बूत करना और नई चीज़ों की ख़ोज करना. कोरोना महामारी ने एक तरफ जहाँ देश की अर्थव्यवस्था को झंझोड़ कर रख दिया है वहीं, देश को आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी दिया. **कोरोना काल ने हमें लोकल उत्पादन, लोकल बाज़ार और लोकल सप्लाई चेन का महत्व भली भांति समझा दिया है. संकट के समय लोकल ने ही हमारी मांगों को पूरा किया है. इस लोकल ने ही हमें बचाया है. इस प्रकार लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा.** अन्य देशों की मदद लिए बगैर हमने महामारी से लड़ने की दवा बनाने का काम सम्पन्न किया. पीपीई किट, वेंटीलेटर, सेनीटाइजर, एन-95 मास्क का निर्माण भारत में ही शुरू हो गया.पहले ये सभी चीज़े विदेशों से मंगाई जाती थी क्योंकि इनका नाम मात्र भी उत्पादन भारत में नहीं होता था. इस प्रकार आत्मनिर्भरता की ओर इसे पहला कदम बोल सकते हैं. इस बदलाव में प्रधानमंत्री जी का लोकल के लिए वोकल का नारा बहुत काम आ रहा है. वास्तव में चुनौतियाँ कितनी ही बड़ी क्यों न हो मानव का थकना, हारना, टूटना, बिखरना मंजूर नहीं है. हमें निरंतर प्रयास करते रहना होगा. सतर्क रहते हुए, नियमों का पालन करते हुए हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है. इस संकट की घड़ी में हमें अपने संकल्पों और मज़बूत करने की आवश्यकता है. हमारा संकल्प संकट से विराट होना चाहिए. हम सभी निरंतर 21वीं सदी को भारत की सदी के रूप में देखने की बात सुनते रहे हैं. अब समय आ गया है, जब वास्तव में इसे भारत की ही सदी बना दिया जाये. आज यह हमारी ज़िम्मेदारी भी है. इसका मार्ग केवल आत्मनिर्भर भारत ही है. हम एक राष्ट्र के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े है जहाँ यह आपदा एक संदेश एक संकल्प और एक महत्वपूर्ण अवसर लेकर आई है.

आत्मनिर्भर होना आत्म केन्द्रित व्यवस्था होना नहीं है, इस बात को हमें याद रखना होगा. हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि आत्मनिर्भरता में संसार के सुख, सहयोग और शांति की चिंता निहित है. हमारी संस्कृति संसार के प्रत्येक जीव मात्र का कल्याण चाहने वाली संस्कृति है. जो संस्कृति पृथ्वी को माँ मानती है, जब ऐसी भूमि आत्मनिर्भर बनेगी तो इससे एक सुख-समृद्ध विश्व की संभावना सुनिश्चित होती है. भारत की प्रगति में विश्व की प्रगति समाहित है. जब दुनिया जीवन और मृत्यु से लड़ रही है तब भारत में बनी दवाइयाँ विश्व के अन्य देशों के लिए जीवन का उपहार, जीवन की आशा स्वरूप है. भारत की चारों ओर प्रशंसा हो रही है तो निश्चित ही हर भारतीय इस पर गर्व कर रहा है. हम मानव जीवन के कल्याण के लिए कटिबद्ध है.

प्रत्येक देशवासी को लोकल के लिए वोकल रहना होगा :- आत्मनिर्भर भारत का सपना लोकल के लिए वोकल रहे बगैर संभव नहीं है. न सिर्फ **लोकल** प्रॉडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना भी आवश्यक है. हम ऐसा कर सकते है. **लोकल से ग्लोबल** बनने का यह बड़ा अवसर है, इसलिए **लोकल के लिए वोकल** रहना होगा.

कोरोना काल ने हमें सिखाया है कैसे विपत्ति के समय केवल लोकल उत्पात ही हमारे काम आए हैं और उन्होंने ही हमारा साथ दिया है. यह बात समझने की है कि, कैसे जिन ब्रांड को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना हुआ देखते है वाकई में, वे भी कभी लोकल ही थे. लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका उपयोग करना शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व महसूस किया तब वे ब्रांड लोकल से ग्लोबल बन गए. अतः हमें लोकल का मूल्य पहचानना ही होगा. इसलिए हर भारतवासी को लोकल के लिए वोकल बनना ही होगा. साथ ही इसका हमें गर्व से प्रचार भी करना है. आने वाले समय में देश की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय विकास संबन्धित गतिविधियों में, पूरा-पूरा एहतियात बरतते हुए, निरंतर तेजी लायी जा रही है. प्रधानमंत्री जी द्वारा अपने भाषणों में कई बार देशवासियों के सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया कि, कैसे सिर्फ उन्होंने लोकल हतकरघा और खादी के प्रयोग को बढ़ावा देने की एक अपील मात्र की ओर लोगों ने अपना प्रेम दर्शाते हुए, न केवल लोकल हथकरघा और खादी के उपयोग को बढ़ाया बल्कि खादी की लोकप्रियता ने इसे एक ब्रांड बना दिया. भविष्य में, इस प्रकार का प्रेम हमें भारत के प्रत्येक ब्रांड और उत्पादों के लिए दिखाना होगा.

लेकिन यह सिलसिला केवल लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने से ही नहीं बल्कि लोकल मार्केट्स, लोकल सप्लाइ चैन को मज़बूत और आधुनिक बनाने पर भी निर्भर करता है. अत: इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि सप्लाई चैन का प्रत्येक स्टेक होल्डर मज़बूत हो. लोकल को मज़बूत करने में वर्तमान सरकार द्वारा एक आर्थिक पेकेज की घोषणा की गई है, जो 20 लाख करोड़ रुपये का पेकेज है. जोकि भारतीय जी डी पी का लगभग 10% है. इससे विभिन्न स्तरों पर लोकल को बल मिलेगा. इसमें लैंड (भूमि), लेबर (मजदूर), लिक्विडिटी (तरलता) और लॉ (कानून) पर बल दिया गया है. इससे कुटीर, लघु मध्यम उद्यम को बल मिल रहा है.

आवश्यकता इस बात की है कि हम अर्थव्यवस्था के हर स्तर पर इन व्यवस्थाओं के लिए वोकल बने. यह केवल सरकार की नहीं बल्कि प्रत्येक भारतवासी की ज़िम्मेदारी है चाहे वे सरकारी सेवाओं में हैं, बैंकों में कार्यरत हैं, वित्तीय संस्थाओं में हैं, किसी कुटीर उद्योग को चलाते हों, सप्लाई चेन का हिस्सा हों, चाहे आम जनता ही क्यों न हो, उन्हें सरकार की इस मुहिम में अपनी ज़िम्मेदारी लोकल के लिए वोकल होकर निभानी ही होगी. तभी हम वास्तव में इसे सशक्त बना सकते हैं और अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण में अपनी ज़िम्मेदारी निभा सकते हैं और शायद इसलिए **देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कथन है कि आत्मनिर्भरता हमें सुख और संतोष देने के साथ-साथ सशक्त करती है. 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने का हमारा दायित्व है, जो आत्मनिर्भरता के प्रण से ही पूरा होगा. लेकिन इसके लिए 130 करोड़ भारतवासियों की ऊर्जा लगेगी.**

निधि सोनी
क्षे.का., इंदौर

AATM-NIRBHAR BHARAT

PROBLEMS & INTERVENTIONS

Today is the era of globalization where every country is dependent on each other in some way or the other. Making our country Bharat Atmanirbhar is the need of the hour and during this pandemic it is even more important to be self sufficient.

Bharat or India became independent in 1947 which was the starting point to become Atmanirbhar but it was not an easy journey. Initially after independence India was so short of food grains that it was not able to feed its own population. Bharat started a revolution to become aatmanirbhar in food grains by starting a successful movement called Green revolution.

Just like Green revolution Bharat has started various revolutions, initiatives or movements to become Aatmnirbhar. In 70s White revolution was started Which led to tremendous growth in dairy & dairy products.

The need of the country changes with time. We have to be flexible in finding solutions for the same. At present to make Bharat Aatmnirbhar we have to be independent in many fields not just one or two. Government of India in the recent past has launched "Make in India" initiative to become Atmanirbhar in various area of manufacturing, whether it is electronics, defence, food processing units etc., some of which has started to show good results as well especially in the field of mobile handsets manufacturing. Many foreign companies such as Apple, Samsung, Xiaomi etc. are producing mobile handsets in our country today not just for domestic use but for export as well.

The path of manufacturing mobile handsets was not easy & had many hurdles. Government of India launched many schemes to incentivise global as well as domestic manufacturers to come & 'Make in India'. Some companies came ahead & launched their plants in India starting with assembly unit which means parts were made in other countries; they just assembled those parts here to make the mobile handset. However with time & various initiatives by Government of India most of the parts of these mobile handsets are now manufactured in India which shares the meaning of "Make in India" or to say Bharat. Similar developments are happening in the field of other electronic equipments such as LCD & LED TVs where in the past these TVs were imported from other countries such as China or other east Asian countries but now they are being largely produced in our country.

Another great example of Atmanirbhar Bharat was during the pandemic period , when Covid-19 was at its peak in March-April 2020. To fight against Covid-19, India required various things such as N-95 masks which was a world standard mask for protection against these types of viruses, PPE kits for health workers fighting against this deadly virus, ventilators for saving lives of people seriously affected by this Covid-19 virus & drugs like Hydro x chloroquine which initially showed good results in fight against Covid-19 virus. However at that time India had neither produced N-95 masks nor PPE kits in the past & importing from the other countries was a very costly affair & also the demand could not be met with the imports. India moved ahead & started producing N-95 equivalent masks, PPE kits as well as ventilators in a very short time & thus met all domestic requirements. All these things were produced in such a large quantity that we were able to export as well. This shows that whenever there is a big problem in our way we come ahead stronger & make ourselves aatmanirbhar. For the Hydrox chloroquine drug, used for Covid-19 which was used for malaria before, India become a saviour when most countries even the biggest economy i.e. United States of America (USA) asked for our help to provide this drug & India has delivered not only to USA but most of the other countries in the world which made India a global supplier of this drug to fight against the pandemic.

Above are some examples of the challenges & their interventions for becoming atmanirbhar. So, whenever challenges have come in the way of Bharat we have come face to face up against the challenges for making ourselves atmanirbhar. Now, the future for atmanirbhar depends on the fact that first we realize what can be the problems or challenges we are facing or will be facing for making ourselves atmanirbhar. Once we find out what are the actual problems we can easily find solutions to the same which we have done in the past too. Bharat has lot of potential as it has a large population & lots of resources, whether it is in the field of service or manufacturing or natural resources mining. If Bharat utilizes its maximum potential, then nobody can stop Bharat becoming fully atmanirbhar.

Ankit Gupta
R.O., Indore

AATMNIRBHAR BHARAT HOW HELPFUL ARE THE NRIs

Prime Minister of India, Shri Narendra Modi has first used the term 'Atmanirbhar Bharat Abhiyan'.

"Atmanirbhar Bharat", which means 'Self-Sufficient India', is a policy formulated by Shri Narendra Modi for making India "a bigger and more important part of the global economy", pursuing policies that are efficient, competitive and resilient, and being self-sustaining and self-generating. To achieve the goal of "Atmanirbhar Bharat" various stake holders have to take active role in making this dream come true. One of the important stake holders are NRIs.

It is a dream of Indian youth of early 2000's to do a Software course in India and get a job in America and earn dollars and have a luxurious life. This phenomenon is termed as "DOLLAR DREAMS", thanks to the software boom in 2000's many Indians realized their DOLLAR DREAMS and further down the line other countries like UK, Canada, Germany, UAE, etc. have also became favored destinations thereby leading to steady increase in strength in number of NRIs.

Govt. of India encourages active participation of the NRIs in the Indian growth story. Since 2003, the Pravasi Bharatiya Divas (Overseas Indians' Day) is celebrated in India on 9 January each year, to "mark the contributions of the Overseas Indian community in the development of India". The day commemorates the arrival of Mahatma Gandhi in India from South Africa, and during a three-day convention held around the day, a forum for issues concerning the Indian diaspora is held and the annual Pravasi Bharatiya Samman Awards are bestowed.As of December 2005, the Indian government has introduced the "Overseas Citizenship of India (OCI)" scheme to allow a limited form of dual citizenship to Indians, NRIs, and PIOs for the first time since independence in 1947.

Remittances by NRIs : Since 1991, India has experienced sharp remittance growth. In 1991 Indian remittances were valued at 2.1 billion USD; in 2006, they were estimated at between $22 billion and $25.7 billion which grew to $67.6 billion in 2012-13, up from $66.1 billion the fiscal year, 2011-2012, when the remittances exceeded the foreign direct investment(FDI) inflow of $46.84 billion into India.

Money is sent to India either electronically (for example, by SWIFT) or by demand draft. In recent years many banks are offering money transfers and this has grown into a huge business. Around 40% of remittances of india flow to the states of Kerala, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Punjab and Uttar Pradesh which are among the top international remittance receiving states. States like Andhra Pradesh and Tamil Nadu get most of their remittance from the USA, Kerala from UAE, Punjab from Canada as most of the people migrate from their states to these countries. Even some Indian banks have recently offered such services.

A 2012 study, by Reserve Bank of India revealed 30.8% of total foreign remittances was from West Asia, compared to 29.4% from North America and 19.5% from Europe.

Reasons to Invest in India : Strong economic growth and Demographics – India's economy is the third-largest in the world based on purchasing-power-parity (PPP), and it ranks 5th as per nominal GDP. The country has shown considerable growth in the IT and business process outsourcing industries which continue to be among the largest sectors of the global economy. It ranks 12th in the world in terms of nominal factory output, and with one of the fastest-growing workforces in the world, India shows great potential for further progress.

High-interest rates-The interest rates offered on bank deposits in India varies between 5-7.5% and is higher than those offered by most other countries of the world. In the year 2019, NRIs sent home $1.95 billion in their NRI deposit accounts which is the highest in 26 months.

Quality of Investment Markets – The Bombay Stock Exchange (BSE) is the second oldest in the world and offers you a low-cost and well-governed

environment to invest and grow. The Indian stock market has generated high investment returns in the past years, and according to experts, the rate is likely to increase further.

Demographics – India is one of the youngest countries in the world with a population of around 1.2 billion that possesses strong work ethics and a high level of education. Further, the working-age population of India is likely to increase in the coming years creating a higher possibility for India to dominate the global economy in future years.

Capital Investment – The capital investment gets calculated as the purchase of new plant and equipment by firms as a percent of GDP, and India's latest value of 30.21 percent is an indicator of good long-term economic growth, as compared to the world average of 24.56 percent.

Financial Assets – The Indian market offers a variety of investment options for all types of investors and choosing the right one based on your risk appetite, return expectations and financial needs can help you utilize your earnings and grow them effectively.

Retirement Plan – Creating a retirement plan well in advance is something many NRI's are doing these days. Moreover, given the uncertainty in the global economy, it is a wise decision to invest and diversify portfolio so that a secure retirement plan is ensured.

Investment opportunities in India

For an NRI who wishes to repatriate funds that are generated overseas or maintain income earned in India, must open an NRE or NRO account depending on their requirements. (The operational aspects of these accounts is a separate subject).Various popular, safe and best investment options available in India for NRIs (non-residents of India) are as follows:–

Bank Fixed Deposits – Investing in bank fixed deposits is one of the safest and most popular investment option. It helps to diversify portfolio and increase savings. For a risk-averse NRI, this is an ideal option as bank fixed deposits ensure guaranteed returns that are not affected by market fluctuations. NRIs can invest in bank fixed deposits with NRE or NRO account and earn a high fixed rate of return. There are three types of fixed deposit accounts –NRE Fixed Deposit Account, NRO Fixed Deposit Account and Foreign Currency Non-Resident (FCNR) Fixed Deposit Account.

Direct Equity – NRIs who want to take advantage of the growth and economic prospects of their home country, can do so with the help of direct equity investment that is, investing in the Indian stock markets. Direct equity in India can be a great way to diversify portfolio, and can do easily under the portfolio investment scheme (PIS) of the Reserve Bank of India (RBI). Under this scheme, open an NRE/NRO account with an Indian bank that is authorized by the RBI because aggregate investment cannot exceed 10% of the paid-up capital in an Indian company and the PIS account helps RBI ensure that this limit is maintained.Moreover, to open a trading account with a registered broker and a DEMAT account that holds shares in an electronic form to trade in stocks on the National Stock Exchange (NSE) of India/ BSE.

Real Estate – Real estate in India is an ever-growing industry and holds significant prospects in sectors like hospitality, commercial, housing, manufacturing, and retail. They are also moderately-liquid investments and are quite popular because the risk involved is low while the return received is very high as real estate property prices keep increasing.

There are several ways one can opt for a real estate investment, some of which are - commercial properties, residential properties, and Real Estate Mutual Funds. Investments in commercial spaces such as offices or shops can help you generate considerably high returns subject to due diligence.

Bonds and Non-Convertible Debentures (NCD) – If one wants to diversify their portfolio beyond bank deposits and explore opportunities in the financial market, they can do that through bonds and debentures.

A bond is a unit of corporate debt issued by a company and is referred to as a fixed-income instrument as it pays a fixed interest rate to debt-holders. Bond prices are inversely correlated with interest rates and have specific maturity dates for repayment of the principal amount.

There are three main categories of bonds that one can invest in –

Non-Convertible Debentures (NCD) - An NCD is a fixed deposit used by public companies in India to raise funds without diluting their equity. They give a fixed rate of interest for a specific period, and the debentures offered by these companies cannot get converted into shares. Also, the NCD market is well regulated, the investment process is exclusively online and the allotted NCDs get credited to your DEMAT account.

PSU Bonds – Public Sector Undertaking Bonds (PSUs) are medium or long term debt instruments issued by Public sector undertakings. PSU's require funds for their regular working capital or capital expenditure and to meet these requirements they

issue PSU bonds. All PSU bonds have a specific maturity date and have a built-in redemption. If one is having an average risk appetite and is looking for double-digit returns, this is a good investment option.

Perpetual Bonds – These are bonds that do not have a maturity date and are not redeemable. However, they pay a steady stream of interest and have a perpetual bond cash flow. One can trade these bonds in the open market and to make a profit using these bonds, market conditions and your willingness to sell them play an important role.

Government Securities – The Reserve Bank of India has recently allowed non-residents to invest in specified Government of India dated securities without any quantitative limit. This option came into effect from 1st April 2020 and got introduced under a separate channel called 'Fully Accessible Route' (FAR).

In some types of dated government securities one can opt for long-term investment strategies which include:-

Fixed-rate government bonds – The interest rate on these bonds are fixed.

Floating rate government bonds – The interest rate here changes according to market fluctuations.

Capital Index Bonds (CPI bonds) – These bonds have coupon payment rates that are adjusted based on the current inflation rates in the Indian market.

Certificate of Deposits (CDs) –

A Certificate of Deposit is a type of money market instrument issued against the funds deposited with a bank in a DEMAT form for a specific tenure. Even as an NRI, one can subscribe to Indian CDs, however, only on a non-repatriation basis. That means one cannot endorse it to another NRI in the secondary market. CDs get regulated by the Reserve Bank of India and are usually used as short-term investment.

National Pension Scheme (NPS)– NRIs planning for retirement and are looking for a long-term investment with equity exposure in their portfolio as well as pension benefits, then NPS is a good option. In NPS, one gets various choices like equity investment, government securities, and other fixed-income instruments. but one can invest in NPS only if an Indian citizen. Also, when investing in NPS, the savings get locked in, and one gets a lump sum amount only after retiring while the rest gets used for a pension. Therefore, one should opt for NPS after careful consideration based on long-term retirement plans and financial goals. There are two types of NPS accounts - Tier 1 Account (All payments and funds are locked in this account until retirement) and Tier 2 Account - (These accounts offer more flexibility concerning deposit and withdrawal of funds).

ULIP – Unit Linked Insurance Plans (ULIPs) are offered by insurance companies and give both insurance and investment options under a single integrated plan. When investing in this option, one has to pay a premium either on a monthly or annual basis. A part of it gets used for providing insurance cover and the rest of the amount gets invested in the fund chosen by you like equity, debt, or hybrid.

ETFs – ETFs or Exchange Traded Funds are marketable securities that track stock elements and mirror an underlying index. As an NRI, one can invest in ETFs with minimum portfolio management and a low transaction fee structure to gain exposure to a myriad of Indian equities or debt. ETFs are a cost-effective way to quickly invest in the Indian stock market as one can get access to a portfolio of Indian stocks that mirror indexes such as the NIFTY 50. ETFs are highly liquid investments, they have become one of the most popular ways of investment in India for NRIs.

There are three types of mutual funds - Debt Funds - (Invest only in fixed income instruments), Equity Funds (Invest only primarily in equity instruments) and Hybrid Funds (Divide investments between equity and debt to create a balance).

Conclusion - The growth of an economy primarily depends on savings and consumption made by the people of the Country and Capital Expenditure and Reforms made by the Governments. India is a country where the market is consumption driven and has a higher percentage of youth in the total population which translates to more demand for products and more income at disposal for savings. Government of India has introduced major reforms in Labour Markets, Agricultural Sector, Capital Markets, etc., which have its own advantage of improving GDP. Even though Indian Rupee has underperformed against USD when compared to other major developing economy currencies, there is a lot of potential for Indian Rupee to appreciate against USD in the near future due to various structural reforms introduced by the Government of India.

It may be concluded that, it is the best time for NRIs to make India as their investment destination and be part of India's mission of 'Aatmanirbhar Bharat'.

K. Ramesh
R.O., Secunderabad

महाराष्ट्र के प्रमुख देव
'श्री गणेश' और इन देवता का उत्सव 'गणेशोत्सव' हर वर्ष बड़े धूमधाम से महाराष्ट्र में
व्यक्तिगत, घरेलु तौर पर तथा सार्वजनिक स्तर पर मनाया जाता है लेकिन कोविड 19 के मद्देनजर इस वर्ष गणे
बहुत छोटे पैमाने पर और शांति से मनाया गया. सार्वजनिक गणेशोत्सव में वह तामझाम, शोरगुल नहीं था. हमारे यूनिव
गणेशोत्सव की इस परंपरा को कायम रखते हुए, कोविड –19 के माहौल में भी गणेशोत्सव पूरी एहतियात के साथ म
अध्यक्षा, सत्यवति रै. द्वारा गणेशोत्सव मनाने के पीछे यही भावना रही कि कोविड–19 की वजह से लोगों
मानसिकता या धैर्य में जो गिरावट आयी है, उसे संबल दिया जाएं.

Our spirit should not get dampen....

Today the whole world is reeling under the impact of the covid-19 pandemic. It has redefined the life style and economic activities with devastating effect. Social distancing, wearing off masks, staggered attendance in offices and work from home are some of the concepts introduced in our life style and thought process. This has been a testing time for the students, children and senior citizens who were forced to get confined to their homes.

However, there is always a silver lining to any crisis. When people had to spend time together in the family, the ties grew stronger with better understanding and lending emotional support to each other. We developed healthy habits to combate the emotional scars.

This pandemic should not be allowed to dampen our spirits. We can still find ways to meet and greet. Let us all pray that it does not leave an unhealed scar on our psyche. There is always a ray of hope at the end of the dark tunnel.

Mrs. Sangita Sharma
Secretary, UniOne

What's New

भारतीय बैंकों में केंद्रीय के.वाई.सी. रजिस्ट्री (CKYCR) का कार्यान्वयन

भारत सरकार ने ग्राहकों द्वारा विभिन्न वित्तीय संस्थानों में बार-बार केवाईसी की आवश्यकताओं/औपचारिकताओं को पूरा करने की परेशानी को देखते हुये, सरसाई (सीकेवाईसीआर) के अंतर्गत केंद्रीय पंजीकरण की स्थापना करने का निर्णय लिया है जिसे नियमित रूप से सभी बैंकों में लागू किया गया है.

इसी संदर्भ में भारत सरकार ने दिनांक 07 जुलाई 2015 को एक गज़ट अधिसूचना जारी करते हुये सी.के.वाई.सी को सक्रिय रूप से लागू करते हुये पीएमएल (रिकार्ड का रखरखाव) नियम 2005 में संशोधन किया गया है.

जिसके तहत सीकेवाईसीआर (CKYCR) के अंतर्गत फोटो सहित केवाईसी दस्तावेज सरसाई के सर्वर में अपलोड किया जाता है.

उक्त दिशानिर्देशों को सही तरीके से अनुपालन हेतु केवाईसी/एएमएल विभाग ने सीकेवाईसीआर के लिए नोडल विभाग बनाया गया है जिसके द्वारा समय-समय पर सरसाई सर्वर में केवाईसी डाटा अपलोड करने के लिए शाखाओं को दिशानिर्देश जारी किया जाता रहेगा.

भारत सरकार के उपर्युक्त नीति को अक्षरशः लागू करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक पत्रांक संख्या आरबीआई/2016-17/डीबीआर एएमएल.बीसी. 47/14-01-01/2016-17 दिनांक 08 दिसंबर 2016 के माध्यम से सभी बैंको को निर्देश दिये गए हैं कि दिनांक 01 जनवरी 2019 को या उसके बाद खुलने वाले सभी नए व्यक्तिगत खातों से संबन्धित केवाईसी आंकड़ों को केंद्रीय केवाईसी रिकार्ड रजिस्ट्री में अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए.

अब एक नजर भारत सरकार एवं आरबीआई द्वारा जारी सीकेवाईसीआर के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी ग्राहक हित का अनुपालन हमारे बैंकों में कैसे हो रहा है उसका वर्णन संक्षेप में निम्नवत है :-

हमारे बैंक का अनुदेश परिपत्र क्रमांक 621-2016 दिनांक 26 अक्तूबर 2016 के द्वारा सभी शाखाओं/कार्यालयों को सूचित किया गया है कि व्यक्तिगत खाते खोलने के लिए वर्तमान में परिचालित फॉर्म/फार्मेट का आशोधन करते हुये निम्नलिखित फॉर्म को लागू किया जा रहा है :-

AOF-1 :- खाता खोलने का फॉर्म;

CIF-1:-आवेदक/हस्ताक्षरकर्ता की जानकारी;

DDL - 1 :- ग्राहक एवं ग्राहक से सम्यक जांच फार्म (Due Diligence Form)

नामिती:- Nomination :- नामांकन फॉर्म

उपरोक्त फार्म में किसी भी ग्राहक का पूर्ण जानकारी प्राप्त किया जा सकता है.

संकलन : अनुदेश परिपत्र क्रमांक : 621-2016 दिनांक 26-10-2016

इसके अलावा वित्तीय समावेशन के अंतर्गत खोले जाने वाले खाते (बीएसबीडीए/बीएसबीडीएस) के लिए फॉर्म-I तथा फॉर्म V बेसिक बचत बैंक जमा सह ओवर ड्राफ्ट खाता खोलने का फॉर्म जारी किया गया है जो 01.01.2019 से खोले जानेवाले खातों में लेना आवश्यक है. इस फॉर्म के साथ नामांकन हेतु अलग से नामांकन फॉर्म लेना आवश्यक है.

(संकलन : अनुदेश परिपत्र क्रमांक : 713 - 2016, दिनांक 28.12.2016)

उपरोक्त दोनों आशोधन (Modification) सीकेवाईसीआर (CKYCR) को देखते हुये किया गया है.

बैंकों में डाटा क्लीनिंग : एक नजर

डीआईटी (DIT) मुंबई द्वारा स्कैनिंग यूटिलिटी (Scanning Utility) पैकेज बनाया गया है जिसमें शाखाओं द्वारा 01.01.2019 से किसी भी चैनल द्वारा बनाए गए आईडी का डाटा अपलोड किया जाना है.

यह पैकेज आर सी सी द्वारा शाखा में कंप्यूटर (PC) पर इंस्टॉल किया गया है जिसमें स्कैनर जुड़ा हुआ (Attatch) है. आर.सी.सी. द्वारा उक्त पैकेज का शॉर्टकट शाखा के कंप्यूटर पर बनाया गया है जिसे क्लिक करके खोला जा सकता है.

यूजर आई डी : सोल आई डी (SOL ID) + एम(M^2)

एवं पासवर्ड : ubi1234 है.

शाखाएँ पैकेज से संबन्धित स्कैनिंग यूटिलिटी पोर्टल (scanning Utility Portal) - (Home page)-Help Optimum में जाकर भी View / Print कर सकते हैं.

जिस खाते का POI/ POA/ Photographs अपलोड (Upload) होना है उसका ब्यौरा (डिटेल्स) इस पैकेज के ड्रॉप लिस्ट (Drop List) में आपको मिल जाएगा. जो खाते ड्रॉप लिस्ट (Drop List) में है उसी खाते का ब्यौरा (Details) अपलोड होना है. अपलोड करते समय यह सावधानी बरतनी है कि ग्राहक का उक्त तीनों ब्यौरों (Details) का इमेज क्लियर हो. इसलिए यह

आवश्यक है कि अनुमोदन प्राधिकारी (Approval Authority) द्वारा अपलोड किया डाटा को अस्वीकृत न (रिजेक्ट न किया) जाय तथा साफ इमेज (Clear Image) ही अपलोड हो.

(संकलन : सूचना परिपत्र संख्या – 01718–2019 दिनांक 30.09.2019)

शाखाओं में अपलोड पेंडेंसी (Uploading Pendency) को देखते हुये डीआईटी (DIT) ने मोबाइल ऐप यूटिलिटी की शुरुआत की है, जिसे हमारे प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में लॉन्च किया गया है. मोबाइल ऐप यूटिलिटी को आप/शाखाएँ http://59.163.35.50:8090/UBI/appdownload यूआरएल (URL) से डाउनलोड कर सकते हैं.

इस ऐप को यूनियन परिवार में उपलब्ध स्टाफ के मोबाइल नंबर पर इंस्टाल किया जा सकता है. केवल फिनेकल आईडी वाले शाखा के सदस्य ही इस ऐप को इंस्टाल और उपयोग कर सकते हैं.

यह ऐप केवल एंड्रोएड डिवाइस पर ही काम करेगा. स्कैनिंग और क्रॉपिंग के लिए स्कैनर और डेस्कटॉप की आवश्यकता नहीं है. एक से अधिक स्टाफ सदस्यों द्वारा एक ही समय में अपने मोबाइल का उपयोग कर अधिक से अधिक लंबित पेंडेंसी को निपटाया जा सकता है.

ऐप लॉगिन हेतु यूजर आईडी – स्टाफ आईडी और पासवर्ड के रूप में – डिफ़ाल्ट पासवर्ड – ubi@1234 रखा गया है जिसके द्वारा स्टाफ सिर्फ अपने शाखा के डाटा को ही प्रोसेस कर सकते हैं. ओटीपी (OTP) सत्यापन के माध्यम से पासवर्ड बदलने की सुविधा प्रदान की गई है.

संकलन : अनुदेश परिपत्र : 01810–2019 दिनक 23–12–2019

अभी तक हमने देखा कि उपरोक्त दो माध्यमों (पीसी/मोबाइल ऐप) के द्वारा ग्राहक का POI/PO–और फोटोग्राफ को पैकेज में अपलोड कर सकते हैं.

मेकर (Maker) – अनुमोदनकर्ता (Approver) – एडमिन (Admin)

मेकर (Maker) :– शाखाएँ मेकर (Maker) के रूप में CKYCR सर्वर में उपलब्ध ग्राहक आईडी का उपरोक्त तीन डॉक्युमेंट अपलोड करेंगे क्योंकि ग्राहक का दस्तावेज़ (Documents) शाखा में ही उपलब्ध रहता है.

अनुमोदनकर्ता (Approver) : शाखा द्वारा अपलोड दस्तावेजों को केंद्रीय कार्यालय द्वारा ही अनुमोदित किया जाता रहा था लेकिन केंद्रीय कार्यालय में अनुमोदन (Approval) के लिए पैकिंग स्थिति को देखते हुये उच्च प्रबंधन ने इसे विकेन्द्रीकरण (Decentralised) किया है जिसके अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर अपने क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाली शाखाओं के डाटा को वेरीफाई एवं अनुमोदित (Approve) करेंगे जिससे कि आरबीआई द्वारा दिये गए समय के अनुरूप सभी ग्राहकों का डाटा अपलोड किया जा सके. इसके लिए पीसी (PC) पर निम्नवत पैकेज इंस्टाल किया गया है.

लॉगिन आईडी – क्षेत्र कोड C जैसे कि रांची क्षेत्र के लिए कोड 547271 है तो यूजर आईडी 547271C होगा और पासवर्ड के लिए डिफाल्ट पासवर्ड Unionbank1234 रखा है जिसे प्रथम लॉगइन के बाद बदलना आवश्यक है.

शाखा द्वारा अपलोड किए गए डाटा को वेरीफ़ाई करते समय क्षेत्रीय कार्यालय के वेरीफ़ाईकर्ता द्वारा निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है :– चूंकि डाटा सरसाई में अपलोड होता है इसलिए आवश्यक है कि अपलोड किया गया डाटा सही हो.

ग्राहक का डाटा, जो पैकेज में दिया गया है उसमें ग्राहक का नाम, लिंग (Gender) जन्म तिथि (DOB), पता (Adress) तथा पिन कोड (PIN Code) इत्यादि सही मिलते हों.

यदि कोई सुधार की आवश्यकता है तो रिजेक्सन/रिस्कैनिंग के बारे में तुरंत सूचित करते हुये इसे सही कराना है.

पैकेज में इमेज अपलोडिंग से reload कारण/reason के लिए कुछ 5 से 6 स्कैनिंग problem डिफाल्ट दिये गए हैं जिसे स्टार्ट कर रि–स्कैन के लिए वापस किया जा सकता है.

यदि फिनेकल में कोई सुधार की आवश्यकता है तो उचित कारण देते हुये आशोधन (Modification) के लिए रिजेक्ट किया जा सकता है.

एडमिन (Admin) : एडमिन अपलोड का कार्य केंद्रीय कार्यालय स्तर पर किया जा रहा है. वेरीफाइड दस्तावेज़ (Document) को सरसाई सर्वर में अपलोड करेंगे और उक्त सर्वर से प्राप्त Response को फिनेकल में अपडेट किया जाएगा.

संदर्भ : पत्रांक : GBOD/0115/2020 दिनांक 11.02.2020

हमने CKYCR पैकेज में ग्राहक डाटा, इमेज अपलोडिंग, अनुमोदन (Approval) एडमिन (Admin Role) कार्य को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करने की कोशिश की है. हमने जिसे भी परिपत्र/पत्रांक का संदर्भ दिया है उसे स्टेप वाइज़ मेकर, चेकर के लिए मैन्युअल स्क्रीन के साथ उपलब्ध कराया गया है जिससे कि दोनों यूजर को तीव्र गति से काम निपटाने में परेशानी महसूस न हो.

यहाँ यह बताना आवश्यक है कि यह एक नियामक (Regulatory) अपेक्षा है जिसका गैर अनुपालन दंडात्मक कार्रवाई को आकर्षित कर सकता है.

अतः हम अपेक्षा करते हैं कि उपरोक्त सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये सभी स्टाफ सदस्य मिलकर सीकेवाईसीआर (CKYCR) तथा इमेज अपलोडिंग का कार्य पूरा करेंगे तथा अपनी संस्था (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) का नाम अग्रणी पंक्ति में रखने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे.

महेश राम
क्षे.का., धनबाद

औषधीय गुणों का खजाना - भृंगराज

भृंगराज कई औषधीय गुणों का खजाना है. इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटीहिस्टामिनिक (एलर्जी को दूर करने वाला), हेपेटोप्रोटेक्टिव (लीवर को स्वस्थ रखना) और एक्सपेक्टोरेंट (कफ जैसी श्वांस की बीमारी को दूर करना) जैसे कई औषधीय गुण होते हैं. इसे केसराज के नाम से भी जाना जाता है. भृंगराज की सफ़ेद, पीली और काली ये तीन जातियाँ पाई जाती हैं. सफ़ेद जाति को भृंगराज, पीली को पीत भृंगराज और काली जाति को नील भृंगराज कहा जाता है. आयुर्वेद के अनुसार भृंगराज का पौधा कड़वा, गरम, धातु परिवर्तक, कृमिनाशक और विषनाशक होता है. इसमें पित्त को शुद्ध करने, बालों को बढ़ाने और दीर्घायु करने के गुण होते हैं. इसकी जड़ों से लेकर तने, पत्तियां और फूलों को औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है. भृंगराज को फाल्स डेज़ी भी कहा जाता है. इसका उपयोग यकृत की बीमारी और तिल्ली की वृद्धि तथा विभिन्न प्रकार के पुराने चर्म रोगों को दूर करने के लिये किया जाता है. तो आइए, जानते हैं भृंगराज के बारे में !

* पीलिया में भृंगराज की पत्तियों और जड़ से निकले अर्क का इस्तेमाल किया जाता है. इसमें मौजूद औषधीय गुण हेपटोप्रोटेक्टिव (लीवर विकार को ठीक करने की क्षमता) के रूप में काम करते हैं. मुंह से लिया गया इसका अर्क एक टॉनिक के रूप में काम करता है.

* भृंगराज के अर्क में पाये जानेवाले एंटीऑक्सीडेंट और एंटीमाइक्रोबियल गुण खांसी का कारण बनने वाले कीटाणुओं को खत्म करने में और हानिकारक कीटाणुओं को पैदा होने से रोकने में मददगार साबित होते हैं. अतः खांसी से राहत मिलती है.

* भृंगराज का एंटीस्पास्मोडिक गुण दस्त को रोकने में कारगर होता है, जो मल को चिकना होने से रोकता है और दस्त से राहत देता है. साथ ही यह मांसपेशियों की सिकुड़न को भी कम करता है.

* भृंगराज में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट और एंटीमाइक्रोबियल गुण पेट में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करके पेट के संक्रमण, अल्सर, जलन और बैक्टीरिया से होने वाली आंतों की समस्या को दूर करने में मदद करता है.

* भृंगराज का एंटीबैक्टीरियल गुण आंखों को संक्रमण से बचाता है तथा इसका एंटीडायबिटिक गुण आंखों को मधुमेह से होने वाले खतरे से बचा सकता है. इसका एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण आंखों की सूजन को दूर कर आंखों को स्वस्थ करने में मदद करता है.

* भृंगराज में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण अस्थमा के दौरान होने वाली फेफड़ों की सूजन को दूर कर फेफड़ों को कई प्रकार से फायदा पहुंचाता है, इससे आपको सांस लेने में होने वाली तकलीफ से राहत मिलती है.

* भृंगराज के एंटीबैक्टीरियल, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण बुखार को दूर करने में कारगर होते हैं. इसकी मदद से मलेरिया, डेंगू व चिकनगुनिया को ठीक किया जा सकता है. यह मच्छरों को पनपने से रोकने में भी कारगर होता है.

* भृंगराज के तेल में मौजूद मेथनॉल नामक पोषक तत्व बालों को मजबूत करने के साथ ही गंजेपन, बालों के झड़ने, असमय बालों की सफेदी होने को रोककर बालों के विकास में मदद करता है.

* इसको थोड़े तेल में मिलाकर सिर पर लेप करने से सिर दर्द दूर हो जाता है.

* इसके पत्तों का रस एक चाय के चम्मच की मात्रा में देने से पीलिया और ज्वर में लाभ होता है.

* इसकी जड़ को पेशाब की जलन दूर करने हेतु उपयोग में लाया जाता है.

* मसूड़ों को मजबूत करने और दंतशूल को मिटाने के लिये इसे मसूड़ों पर रगड़ते हैं.

* इसके सेवन से यकृत की विनिमय क्रिया सुधरती है, पित्त का संचालन व्यवस्थित रूप से होता है और आमाशय तथा पित्ताशय की पाचन क्रिया सुधरने से सारे शरीर में ओज और कान्ति की वृद्धि होती है.

* अग्नि से जले हुए व्रण पर भृंगराज, मरवा और मेहंदी के पत्तों को पीसकर लगाने से जलन शांत हो जाती है और नई आनेवाली त्वचा सामान्य शरीर के रंग की हो जाती है.

* भृंगराज के रस में हीराकसी को मिलकर लेप करने से बाल काले हो जाते हैं.

* बिच्छू के डंख पर इसके पत्तों को पिसकर लेप करने से तथा इसके रस को नाक में टपकाने से बिच्छू का विष उतर जाता है.

* भृंगराज का रस और बकरी का दूध समान अनुपात में लेकर उसको गर्म करके नाक में टपकाने से और इसके रस में काली मिर्च मिलाकर सिर पर लेप करने से आधासिर दुखने की व्यथा मिट जाती है.

* यह शरीर में होनेवाले सूजन रोकने में असरदायक होता है. प्रतिदिन रात को सोते समय भृंगराज का रस शरीर पर मसल कर लगा लेना चाहिये. इस प्रकार 6 महीने तक लगातार करते रहने से शरीर की बढ़ी हुई चर्बी और उस चर्बी की वजह से जगह-जगह होनेवाली गाठें दूर हो जाती हैं.

* यह शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति को मजबूत बनाने वाली और हमारे शरीर को संक्रमण से बचाने वाली सफेद रक्त कोशिकाएं (डब्लूबीसी) के उत्पादन में सहायता कर इसको बढ़ाने का काम करता है.

* यह लीवर के साथ-साथ किडनी के लिए भी फायदेमंद होता है. इसकी जड़ का प्रयोग शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को बाहर निकालने और शारीरिक कार्यप्रणाली को गतिशील रखने के लिए किया जाता है. इसके अंदर एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लैमटेरी गुण होते हैं, जो फैटी लीवर, पीलिया जैसी बीमारी में फायदा पहुंचाता है.

भृंगराज से नुकसान - अधिक मात्रा में सेवन करने से आपको पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है. इसी तरह गर्भावस्था और स्तनपान की अवस्था में डॉक्टर के परामर्श के बाद ही भृंगराज का सेवन करना चाहिए. इसके तेल की तासीर ठंडी होती है. अतः अगर आपको सर्दी या जुकाम है, तो इससे सिर की मालिश न करें. इसमें मौजूद गुण रक्त में मौजूद ग्लूकोज के स्तर को कम कर देता है, इसलिये जिन्हें लो शुगर की समस्या है, उन्हें इसके सेवन से परहेज करना चाहिए. कब्ज की समस्या वालों को इससे दूर रहना चाहिए.

अनिता भोबे
यूनियन धारा, के.का., मुंबई

गांवों का विकास / आत्मनिर्भर कृषक

यह एक निर्विवाद सत्य है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है. 2011 की जनगणना रिकॉर्ड के अनुसार भारत में लगभग 6 लाख गांव है. भारत की कुल जनसंख्या का 73% भाग गांव में निवास करता है. इस तथ्य से हम यह कह सकते हैं कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता.

आजादी के बाद देश की सभी सरकारों ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. पंचायती राज व्यवस्था आने के बाद ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने में और समस्याओं के त्वरित निराकरण में सहायता मिली है.

देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में हरित क्रांति का आह्वान किया था जिसके कारण परंपरागत तकनीकों को छोड़कर देश के किसान खेती के लिए नवोन्मेषी तकनीक की ओर अग्रसर हुए. जिससे फसल उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली. यह किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की ओर पहला कदम माना जा सकता है. हरित क्रांति के परिणाम स्वरुप देश के किसान बहु फसलीय व्यवस्था, अधिक उत्पादन देने वाले बीज, उपयुक्त संचार व्यवस्था, आधुनिक कृषि यंत्र, पेस्टिसाइड्स एवं फर्टिलाइजर का उपयोग करने लगे जिसके कारण किसानों की आय कुछ हद तक बढ़ने लगी. किसानों की आय बढ़ने से दो महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले.

1. **ग्रामीण क्षेत्रों में :** रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए जिससे शहरों की ओर होने वाला पलायन कुछ हद तक रुक गया.

2. ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई और अंतत: ग्रामीण क्षेत्र देश के विकास में प्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका निभाने लगे.

5 जून 2020 को देश की वर्तमान सरकार द्वारा कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तीन महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए.

कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) कानून 2020–इस विधेयक के जरिए किसानों को उनके द्वारा उत्पादित फसलों को कहीं भी बेचने की छूट दी गई है. अब किसान अपना माल देश के किसी भी बाजार में बेच सकता है. खरीदारों के बीच प्रतियोगी वातावरण होगा तो किसानों को अच्छा भाव मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी.

किसान (संरक्षण एवं सशक्तिकरण) समझौता और कृषि सेवा कानून 2020–इस विधेयक के जरिए किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ अग्रसर होंगे. किसान अपनी फसल की बिक्री दर बुवाई के समय ही तय कर सकते हैं और खरीदार के साथ अनुबंध कर सकते हैं इस विधेयक के पीछे सरकार का उद्देश्य किसानों की उपज का सही मूल्य दिलाने में सहायक होगा.

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 **(संशोधन) कानून** 2020–कुछ महत्वपूर्ण खाद्यान्नों को अब आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया गया है जिसके कारण किसानों को इन खाद्यान्नों का उचित मूल्य मिल सकेगा और निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा.

इन तीनों विधायकों के पक्ष में सरकार का तर्क है कि अब **किसान अपनी फसल को देश के किसी भी बाजार में बेच सकेंगे** इसका सीधा प्रभाव यह होगा कि अब बाजार भी बिचौलियों से मुक्त होगा और वर्तमान में कार्यरत मंडी व्यवस्था को भी प्रभावपूर्ण तरीके से किसानों के हित में कार्य करना होगा.

ई–नाम (नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट) नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लांच किया गया है जहां क्रेता और विक्रेता एक ही प्लैटफ़ार्म पर खाद्यान्नों की खरीदी और बिक्री कर पाएंगे. इससे किसानों को पारदर्शी तरीके से अपनी फसल बेचने का अधिकार प्राप्त होगा.

सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं इसमें सीधे–सीधे परंपरागत खेती करनेवाले किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि संबंधित अन्य गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है.

सभी सरकारों के एकीकृत प्रयासों से हम देश की साक्षरता दर को बढ़ाने में सफल हुए हैं इसी का परिणाम है कि आज देश के कृषक परंपरागत खेती के साथ ही मत्स्य उत्पादन, बहुफसलीय व्यवस्था के अंतर्गत फलों का उत्पादन, पोली हाउस, हायड्रोपोनिक्स एवं सोलर ऊर्जा का उपयोग करने की तरफ अग्रसर हुए हैं. देश के ग्रामीण क्षेत्र लगातार उन्नति के पथ पर अग्रसर हैं. किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को लगातार सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है. इसके अतिरिक्त अधिक उत्पादन देने वाले बीज एवं खाद्य भी क्रेडिट सोसाइटी के माध्यम से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं. सरकार नवोन्मेषी तकनीक भी किसानों को अपनाने की सलाह देती है साथ ही इन तकनीकों को अपनाने में आने वाले खर्च को ऋण के रूप में देती है और सब्सिडी के जरिए इन योजनाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है.

ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाएं भी ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है.

संक्षिप्त रूप से आत्मनिर्भर कृषक की संकल्पना और गांव का विकास एक दूसरे के पूरक हैं. कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए परंपरागत आहार शैली का व्यापक प्रसार करना आवश्यक है. विगत कुछ वर्षों में हम फल, औषधियों के बजाए फास्ट फूड की तरफ आकर्षित हुए हैं. किसानों से सीधे उनकी उपज खरीद कर हम भी उनकी आय बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. सरकार को भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एवं कोल्ड स्टोरेज सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए अधिक प्रयास करने चाहिए. देश की सरकार द्वारा कई सराहनीय कदम किसानों की आय बढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाये जा रहे हैं. देश आत्मनिर्भर कृषक की संकल्पना के साथ हम सही दिशा में अग्रसर हैं, समेकित प्रयासों के जरिए ही हम गांवों का पूर्ण विकास कर पाएंगे. यह हमारे लिए अति आवश्यक हैं क्योंकि गांवों के विकास से ही देश का विकास संभव है.

सतीश कुमार मेहता
क्षे.का., राजकोट

Face in UBI crowd

The Gazal Nawaj in Making

Friends, you all will agree that mankind has myriad talents, the variety changes from person to person. It is hard to believe that a person who has trained in classical music can equally give justice to its semi-classical forms like 'ghazal' and 'thumri' and can also write stories. Friends, meet one such Unionite - Shri Rajeev Yadav, Assistant Manager of our Regional Office, Lucknow. Hailing from a middle class family, Shri Yadav strongly believes that singers and writers are born. His father has retired from Education Dept. (U.P. Govt.) while his mother is a home maker. Though he himself doesn't have family trend for these arts, this creative artiste had taken pains to mould his inborn talents into professional ones. This down to earth fellow attributes all the credit of his success to his parents and guru. Here in this short dialogue with Smt. Supriya Nadkarni, he has discussed his journey in both the musical and literary world.

❑ For the very first time who introduced you to music?

When I was in the second standard, my class teacher introduced me to music for the very first time.

❑ How did you get deeply involved in this hobby?

I was always fond of singing. This started in childhood from school days itself and then went onwards to college and university level and today it has reached the 'Gharana Singing' which is constantly moving forward.

❑ Music is a wonderful, exciting & engrossing hobby that requires immense patience and concentration - Please elaborate.

Yes I agree, it is possible to produce any tone that touches your soul in words only when you keep practicing continuously with patience only and meditation. After all, the only sound that touches the heart inside is called 'Music'.

❑ Should music be commercialised?

Yes, Music should be commercialized. as it is a serious subject. Earlier people in our country used to spend their entire life for music with dedication because they used to get protection from the King and his entire livelihood was preserved, but at present it is not so. Today, the challenges in the field of music have become tough. If music is not commercialized, then people working in this field will face the question of running their livelihood.

❑ Do you follow 'Gharana' tradition? Do you support the traditional 'Gharana Style' in music? Why?

Yes I follow the tradition of Banaras Gharana. I support Traditional Gharana style because Indian music has flourished in its Gharana roots.

❑ Who are your idols in the field? And your inspiration?

My guru Pandit Rameshwar Prasad Mishra. My inspiration, of course my mother always.

❑ Your favourite classical 'ragas'? Your favourite Ghazal/Thumri?

My favorite classical ragas are 'Shivranjani', 'Jog', 'Jai-jaivanti', 'Pahadi', 'Bhairavi', 'sohni', 'Darbaari' and 'Megh-Malhaar'. My favorite ghazal is 'Apni tasveer ko aankhon se lagaata kya hai' of Ghulam Ali and my favorite Thumri is 'Na aaye piya' from the Film 'Hazaaron Khwahishen Aisi' sung by Shobha Joshi.

❑ What is the difference between a Ghazal and a Thumri?

Thumri is a vocal genre or style of Indian music. The term 'thumri' is derived from the Hindi verb 'thumakna' (means 'to walk with dancing steps so as to make the ankle-bells tinkle.') Thus, it is connected with dance, dramatic gestures, mild eroticism, evocative love poetry and folk songs especially from Uttar Pradesh. Thumri is characterized by its sensuality, and by a greater flexibility with the raga and restricts itself to expressing the countless hues of shringar by combining melody and

words. A thumri singer goes straight to the emotional core of a composition and evokes each yearn of amorous feelings, each strand of sensuous sentiment, with great discretion.

The ghazal is a form of amatory poem or ode, originating in Arabic poetry. It is a poetic expression of both the pain of loss or separation and the beauty of love in spite of that pain. Historically it has been one of the most popular poetic forms across the Middle East and South Asia. Even into the modern era the ghazal has retained its extreme popularity among South Asian royalty and nobility. Most of the ghazals are now sung in styles that are not limited to khayāl, thumri, rāga, tāla and other classical and light classical genres.

Both Ghazals and Thumris are semi-classical. Ghazal is a composition of many 'shers' normally in odd numbers like 3, 5 or 7 while Thumri is a short poem. The first poem of ghazal is called 'Matla' and the last one as 'Makhta'.

❑ According to you, what is difficult – classical or Ghazal/Thumri singing? Why?

According to me, Classical singing is difficult because we cannot go beyond the limitation of a classical raga along with taal and matra but we can go in Ghazal or Thumri sometimes which are expressions - dominant not like the mathematical rhyme of classical raga.

❑ What is your definition of music?

It's a difficult question, but in short I can say that the group of notes that you hear with a controlled voice and the one which reaches your soul and makes you relaxed is Music! It is a great and divine voice.

❑ How have your family members & colleagues helped you in honing your skills?

I come from a family that has no connection with music but when I told them that I want to learn music, they honored my decision gladly, arranged for my music classes and supported me. My friends and colleagues always supported me and helped me in every possible way to sail smoothly and go ahead in the field of music.

❑ What is your daily schedule pertaining to music? How much time do you devote towards 'riyaz'?

To be honest, after joining the banking services, it is difficult for me to follow the regular schedule. I do steal 3 to 4 hours from this hectic schedule for my daily Riyaz, either in the morning or in the evening.

❑ Any special practice/preparation before giving a performance?

Yes, I practice properly before every performance. Practice boosts your confidence. Sometimes it leads to creation of a master piece though not always!

❑ What is the process of bringing out an album?

To bring out a Ghazal Album is a tedious job - one has to incorporate the right 'shayri' and the same should be blessed with right music and a good composition. Besides this, a good Music company that brings out this album plays an important role. Thus it's a perfect combo of all necessary ingredients just like a good cup of tea!

❑ How have you started your writing endeavours?

After witnessing some events happening in the society, the desire arose in my mind that these incidents should be compiled and brought to the notice of general public. Thus this endeavor kick started.

❑ Who is your inspiration?

My own Inner instinct!

❑ How do you choose your theme?

I don't have to choose any theme, just pen down the subject that appeals to me and is good and different.

❑ When have you decided to go in for 'professional writing'?

I was confident of my skill and with the completion of my very first story, I decided to go in for professional writing.

❑ What prompted you to publish your work?

It seems to me that if I only keep on writing stories, then the very purpose of writing will not be fulfilled nor will the message reach people. So to reach to the masses through stories, I thought of publishing my work.

❑ Are writers born?

Yes writers are born. Writing should be in your genes first of all and with training & experience, one can sharpen this skill.

❑ Have you undergone any formal training to polish your latent skills?

In the field of music, yes I have taken help of an instructor before and I am taking it even today, but I have not taken any training to become a writer.

❑ What's new in hand now? Any future plans?

I am working on a Ghazal album which will be completed by mid-2021, as well as a book of stories which will be in out very soon.

❑ Any message for budding stars?

By the way, I am a budding artist too! I just want to say to those who are coming into this field that keep doing your work with all efforts and success is always achieved with patience and honesty.

'Union Dhara' wishes him 'All The Best' in his future endeavours.

Supriya Nadkarni
Union Dhara, C.O.

Contest No. 155

नयी प्रतियोगिता / New Contest

फोटो–श्री अक्षय आंगवलकर
(सतर्कता विभाग, के.का.मुंबई)

शीर्षक दें / Coin a Caption

क्या ये तस्वीर भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित कर रही है? तो फिर इंतजार कैसा? फौरन अपने की–बोर्ड पर उंगलियाँ चलाना शुरू करें और हमें 'sulabhakore@unionbankofindia.com' पर इस तस्वीर से संबंधित सिर्फ एक या दो पंक्तियों में बढ़िया–सा शीर्षक लिखकर ई–मेल करें. आप अपनी प्रविष्टि 'संपादक, यूनियन धारा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक भवन, तल मंज़िल, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई–400 021' इस पते पर भी प्रेषित कर सकते हैं. शीर्षक अंग्रेजी या हिन्दी में भेजा जा सकता है. दोनों ही श्रेणियों के लिए अलग–अलग पुरस्कार रखे गए हैं. कृपया नोट करें कि यह प्रतियोगिता सिर्फ बैंक के सेवारत कार्मिकों के लिए ही है.

यदि आपका शीर्षक हमारे स्तर पर चुना जाता है, तब आपको पुरस्कार के साथ–साथ यूनियन धारा में प्रकाशित होने का मौका भी मिलेगा.

जल्दी करें, प्रविष्टियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि है, **20 मार्च, 2021**.

संपादक

Does this photograph fire your imagination or spontaneously inspire you to express your feelings? Then what are you waiting for? Start keying in and e-mail us your superb, classy caption, relating to this photograph only in one or two lines at 'sulabhakore@unionbankofindia.com'. You can also send your entries to 'Editor, Union Dhara, Union Bank of India, Central Office, Union Bank Bhavan, Ground floor, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400 021'. The Caption can be sent in English or Hindi. Both the categories have different prizes. Please note that this contest is open only for the present staff members of the Bank.

If your caption is chosen, you will be awarded a prize and your name will be published in 'Union Dhara'.

Hurry up, the last date to receive entries is **20th March, 2021**.

Editor

यूनियन धारा प्रतियोगिता क्र. 153 'शीर्षक दे'
पुरस्कार प्राप्त योगदानकर्ता

पुरस्कार	हिन्दी खंड	अंग्रेजी खंड
प्रथम	**श्री सचिन बंसल,** स्टा. महाविद्यालय, बेंगलुरु	**श्री सनी महेंद्र,** क्षे.का.प्रयागराज
द्वितीय	**सुश्री नूपुर तिवारी,** क्षे.का., भोपाल सेंट्रल	**श्री राकेश कुमार रथ,** एस.एस.आई., विशाखापट्टनम
तृतीय	**श्री अमित महतो,** रा.का.प्र., कें.का., मुंबई	**श्री ए. पानी कुमार,** क्षे.म.प्र.का., विशाखापट्टनम
प्रोत्साहन	**श्री जीतेन्द्र शर्मा,** पंडरी शाखा, रायपुर	**श्री सुभाष चन्द्र,** क्षे.का., उदयपुर

Aatmnirbhar Bharat Where are the Possibilities

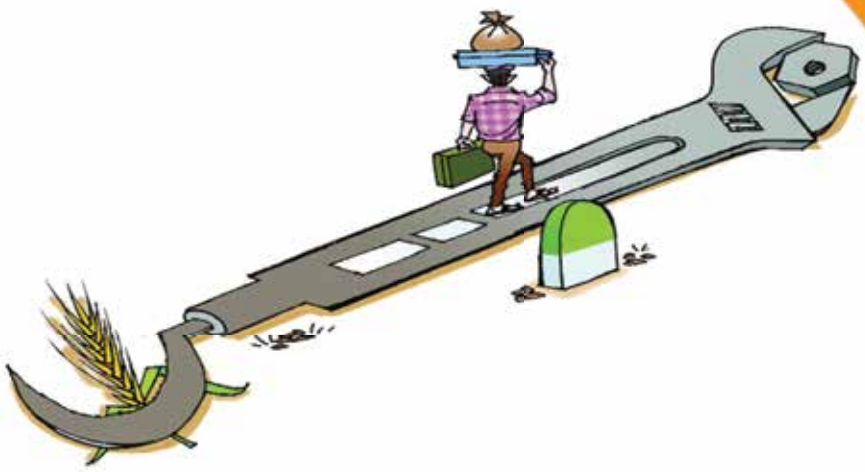

Aatmnirbhar Bharat is a policy formulated by Prime Minister of India to make India Self Reliant & a Key member in the Global Economy, with the slogan'' Vocal For Local. Covid Pandemic has raised the need for Aatmnirbhar Bharat in order to promote Entrepreneurship. The definition of MSME has been changed. Entrepreneurship development cell at district cell assisting young entrepreneurs, financial institutes providing collateral free credit under MUDRA, is a known fact that in 70s & 80's as a nation we were under food crises. The Green Revolution has changed the entire scenario. We have shown the world we can become self reliant in agriculture to feed our huge population, & even export surplus in the global market. Similarly there is tremendous scope in other sectors where we can become self reliant, we need not depend on other countries such as China, South Korea & Japan from where our share of import is high. We have Top class IT companies in software with global presence such as Infosys, Wipro, & TCS, likewise we can do better in hardware also, Currently Indian hardware market specially smart phones & laptops are captured by foreign companies, with up gradation in Research & Technology, Indian companies have the ability to produce competitive products.

No doubt liquidization, privatization, globalization plays a vital role in economic upliftment of India, by way of increasing our foreign reserve, employment generation but it is somewhere restricted. The expansion of local companies, however being a member of WTO we can't deny the entry of MNC's in India but we can choose the products to buy. Other countries are looking at India as a huge market to downgrade the Importance & market share of China. In our Electronic & Toy Market, we have ample scope. Prime Minister has given emphasis on the same, while addressing the nation in Man Ki Bath about us having skilled manpower, industry friendly policies of Government which will surely make a huge difference.

We have good scope in Healthcare Industries, our pharma companies are at par with other global companies, We have Top Class Hospitals and India could become the desired Destination for South Asian countries for major treatments. Currently Indian Defence Sector is heavily dependant on foreign countries, and this could be a sector where we can become self reliant.

Indian Companies in Agri Sector are as good as their foreign competitors.Indian Seed Companies such As Mahyco is as Good as Monsanto. Indian Pesticide Companies such as Indofill & Godrej Agrovet are as good as Bayers Crop Science, only the need is to promote & purchase Indian Products. in FMCG sector Patanjali is acquring a market share from P& G, Hindustan Uniliver & Nestle, People prefer fresh products instead of processed food, organic instead of chemical food, and this is a good sign for Indian FMCG companies, There is scope in automobile sector, in the energy sector we could reduce import of Uranium by way of promoting & manufacturing solar products like solar light, solar pump. It will take sometime to become self reliant but gradually we can achieve the desired results.

Ganesh Mante
USK, Faizpur

शुभमस्तु

श्री दीपक बी. कांबले
महाप्रबंधक

श्री संकरैया एम.
महाप्रबंधक

श्री जी. गुरुहरिनाथ राव
महाप्रबंधक

श्री आई. श्रीकरा राव
महाप्रबंधक

श्री आर. वी. रमना राव
महाप्रबंधक

श्री गुरतेज सिंह
उप महाप्रबंधक

श्री अशोक कुमार
उप महाप्रबंधक

श्री एम जे अशोक
उप महाप्रबंधक

श्री एन लक्ष्मीनारायण भट
उप महाप्रबंधक

श्री अदाबला शेषगिरी राव
उप महाप्रबंधक

श्री विजयकुमार ए.
उप महाप्रबंधक

हमें गर्व हैं

क्षे.का., उदयपुर के अंतर्गत आने वाली सविनाखेड़ा शाखा द्वारा 48 करोड़ का डिपॉजिट लाने पर क्षेत्र प्रमुख, श्री जितेंद्र सिंह तोमर द्वारा शाखा प्रमुख, श्री रोहन चौहान व उप शाखा प्रमुख, श्री दीनदयाल केडिया का क्षेत्रीय कार्यालय में सम्मान किया गया

रामपुरा शाखा, सूरत के सुरक्षा प्रहरी श्री प्रेम प्रकाश सिंह को शाखा के गेट पर राशि रु. 9000/- गिरे हुए मिलें. उन्होंने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए ग्राहक को राशि लौटाई. ग्राहक श्री प्रवीण भाई मोहन भाई पारीक द्वारा सुरक्षा प्रहरी को प्रशंसा पत्र भी दिया गया.

Answers for Quiz - (From Page No. 39)														
1. B	2. A	3. D	4. B	5. C	6. C	7. B	8. A	9. C	10. D	11. B	12. A	13. C	14. B	15. D
16. B	17. B	18. C	19. D	20. A	21. C	22. B	23. D	24. C	25. A	26. B	27. C	28. C	29. A	30. B

पुरस्कार और सम्मान

हमारे बैंक को फिर एक बार प्रतिष्ठित 'गोल्डन पीकॉक नेशनल ट्रेनिंग अवार्ड –2020' से सम्मानित किया गया है. यह पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स (आईओडी), नई दिल्ली द्वारा 15.07.2020 को आयोजित वर्चुअल पुरस्कार समारोह में प्रदान किया गया. उल्लेखनीय है कि हमारा बैंक 'नेशनल ट्रेनिंग अवार्ड श्रेणी' के अंतर्गत 9वीं बार इस पुरस्कार का विजेता बना है. यह पुरस्कार श्री विनायक वी. टेंभूर्णे, महाप्रबंधक (एचआर–एल एण्ड डी) ने प्राप्त किया.

Our Bank bagged the Internet Entrepreneur Awards (For Building Enterprises for a Tech Future - LEARN TECH Awards). This Award was conferred by The Future of Tech Congress & Awards and World Education Congress at a virtual award ceremony held on 15.10.2020. Our Bank has won this award in the category of 'The Best Digital Transformation of a Training Program in response to COVID 19'. The Award was received by our Executive Director Shri Manas Ranjan Biswal.

दि. 04.07.20 को अंचल प्रमुख की अध्यक्षता में क्षे.का., दुर्गापुर में आयोजित शाखा समीक्षा बैठक का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ करते हुए श्री अमरेन्द्र कुमार, अंचल प्रमुख, कोलकाता.

दि. 15.09.20 को क्षे.का.सिलीगुड़ी द्वारा 'स्वच्छ भारत अभियान' के तहत स्थानीय पार्क की सफाई क्षेत्रीय कार्यालय के स्टाफ सदस्यों द्वारा क्षेत्र प्रमुख, श्री संजीव कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई.

दि.10.09.20 को अंचल प्रमुख, श्री अमरेन्द्र कुमार की उपस्थिति में दुर्गापुर सिटी (यूनियन बैंक) एवं सिटी सेंटर (पूर्व आंध्रा बैंक) को समामेलित किया गया.

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्टा.प्र.कें., भुबनेश्वर में श्री पुष्कर कुमार सिन्हा, केंद्र प्रभारी द्वारा ध्वजारोहण किया गया. इस अवसर पर सभी स्टाफ सदस्य एवं उनके परिवार सदस्य भी उपस्थित थे.

दि. 15 अगस्त 20 को क्षे.का., हावड़ा के परिसर में कार्यालय एवं शाखा के कुछ स्टाफ सदस्यों द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए.

स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान दि. 12.09.20 को स्टा.प्र.कें., भुबनेश्वर में सभी स्टाफ सदस्यों द्वारा केंद्र के आस पास के इलाकों की साफ-सफाई की गई.

दि.17.08.20 को क्षे.का., सिलीगुड़ी द्वारा क्षेत्र महाप्रबंधक कोलकाता, श्री अमरेन्द्र कुमार की उपस्थिति एवं क्षेत्र प्रमुख, श्री संजीव कुमार की अध्यक्षता में आनंद लोक मेडिकल प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कैशलेस कैंपस का शुभारंभ किया गया.

दि.06.07.20 को क्षेत्र महाप्रबंधक-कोलकाता श्री अमरेन्द्र कुमार, क्षेत्र प्रमुख-बृहद कोलकाता, श्री कुन्दन लाल एवं क्षेत्र प्रमुख-हावड़ा, श्री मयंक भारद्वाज द्वारा हावड़ा क्षेत्राधीन नवाबपुर शाखा एवं एटीएम के नए परिसर का उद्घाटन किया गया.

दि. 09.09.20 को क्षे.का., हावड़ा के सम्मेलन कक्ष में हावड़ा क्षेत्राधीन कुछ शाखाओं के लिए ऋण मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया. साथ ही दि. 10.09.20 को खड़गपुर शाखा, मिदनापुर जिलों की सभी शाखाओं के लिए ऋण मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया.

'स्वच्छता ही सेवा' को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान दि. 25-09-20 को क्षे.का., हावड़ा के स्टाफ सदस्यों द्वारा कार्यालय परिसर को स्वच्छ रखते हुए स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया.

समाचार (पश्चिम)

क्षे.का., नासिक के क्षेत्र प्रमुख द्वारा नासिक क्षेत्र के देवगिरि परिसर में वृक्षारोपण किया गया.

क्षे.का., महेसाणा में दिनांक 1 से 15 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया. इसी संदर्भ में स्वच्छता अभियान के चलते बस अड्डा परिसर की सफाई की गई. इस मौके पर महेसाणा क्षेत्र के क्षेत्र प्रमुख, श्री सुभाष शर्मा, उप क्षेत्र प्रमुख, श्री पी. सी. जैन, एवं अन्य स्टाफ सदस्य. इसी उपलक्ष्य में यूनियन बैंक द्वारा झाड़ू एवं कूड़ेदान भेंट किए गए.

क्षे.का., नागपुर द्वारा सिविल लाइन्स शाखा परिसर में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. ध्वजारोहण क्षेत्र प्रमुख, श्री सुमेर सिंह सरोया ने किया. कार्यक्रम में मुख्य रूप से सिविल लाइन्स शाखा के सहायक महाप्रबंधक, श्री नीरज सिंह, धंतोली शाखा के सहायक महाप्रबंधक, श्री राजेश कुमार यादव, मुख्य प्रबन्धक, श्री नरेंद्र सम्यक व साथ ही एसोसिएशन के प्रमुख श्री जगन्नाथ मौंदेकर, उपस्थित रहे.

दि. 15.08.2020 को क्षे.का., नासिक परिसर में स्वतन्त्रता दिवस मनाया गया. इस उपलक्ष्य में क्षेत्र प्रमुख, डॉ. अजित मराठे ने झंडा फहराया एवं सभी सुरक्षा गार्डस् को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया.

दि. 15.08.20 को क्षे.का.,अहमदाबाद द्वारा आयोजित स्वतन्त्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि, श्री प्रमोद कुमार सोनी, क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय, अहमदाबाद उपस्थित रहे. साथ में उपस्थित श्री मनोज कुमार, क्षेत्र प्रमुख एवं श्री रामानन्द राम, उप क्षेत्र प्रमुख, क्षे.का., अहमदाबाद. ध्वजारोहण के पश्चात गार्डस् द्वारा मार्च पास्ट किया गया. साथ ही क्षेत्र महाप्रबंधक द्वारा गार्डस् को सम्मानित भी किया गया.

क्षे.का., नागपुर में स्पोर्टस् क्लब के सदस्यों द्वारा दि. 22 से 28 अगस्त 20 को श्री गणेश स्थापना का कार्यक्रम आयोजित किया गया. स्थापना के उपलक्ष्य में क्षेत्र प्रमुख, श्री सुमेर सिंह सरोया व क्षे.का. के सभी स्टाफ सदस्य कार्यक्रम में उपस्थित रहे.

दि. 25.06.20 को क्षे.म.प्र.का., अहमदाबाद के अधीन क्षे.का., आणंद ने पूर्व-कॉर्पोरेशन बैंक, आंचलिक कार्यालय, बड़ौदा के वर्तमान परिसर में अपनी कार्यप्रणाली का शुभारंभ किया. क्षेत्र प्रमुख श्री राजेश कुमार झा जी ने स्टाफ सदस्यों को संबोधित किया. इस अवसर पर क्षे.का.,बड़ौदा क्षेत्र प्रमुख श्री सत्यजीत मोहंती, उप क्षेत्र प्रमुख श्री आशीष सुवालका, मुख्य प्रबंधक मो. जावेद हुसैन उपस्थित रहे.

दि. 19.07.20 को क्षे.का., नासिक में ई-आंध्रा और ई-कार्पोरेशन शाखाओं के शाखा प्रबंधकों के साथ रोल आउट समारोह आयोजित किया गया, जिसमें ई-आंध्रा और ई-कॉर्पोरेशन बैंक की स्थानीय शाखाओं के शाखा प्रबंधक एवं क्षेत्रीय कार्यालय के सभी स्टाफ सदस्य और यूनियन बैंक की स्थानीय शाखाओं के शाखा प्रबंधक उपस्थित रहे, इस समय केक काट कर इस खुशी को सभी के साथ मनाया गया.

दि.15.08.20 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्षे.का., सूरत के प्रांगण में श्री प्रांजल बाजपेयी, क्षेत्र प्रमुख, सूरत, द्वारा ध्वज फहराया गया. इस अवसर पर श्री सुनील सिंह नेगी, उप क्षेत्र प्रमुख, सूरत; श्री राम सुंदर पांडेय, प्रबन्धक (सुरक्षा) तथा श्री भोला कुमार सिंह, न्यू सिटि लाइट शाखा उपस्थित थे.

दि. 15.08.20 को क्षे.का.,बड़ौदा के परिसर में स्वतन्त्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया. इस अवसर पर क्षेत्र प्रमुख, श्री सत्यजीत मोहंती द्वारा ध्वजारोहण किया गया. इस अवसर पर कार्यालय के अन्य कार्यपालकगण उपस्थित रहे और माइक्रोसॉफ़्ट टीम्स ऐप के माध्यम से शाखाओं एवं सेवानिवृत्त स्टाफ-सदस्यों को भी जोड़ा गया.

दि. 08.07.20 को सरल, सूरत का रोल आउट किया गया. इस अवसर पर केक काटते हुए श्री प्रांजल बाजपेयी, क्षेत्र प्रमुख सूरत; श्री सुनील सिंह नेगी, सरल प्रमुख, सूरत; श्री अमित कुमार, सहायक महा प्रबंधक, पूर्व कॉर्पोरेशन बैंक; श्री दुर्गानन्द मिश्रा, मुख्य प्रबंधक, सरल साथ में उपस्थित हैं सरल, सूरत एवं क्षे.का., सूरत के स्टाफ सदस्य.

दि. 08.07.20 को यूनियन लोन पॉइंट, सूरत का रोल आउट किया गया. इस अवसर पर केक काटते हुए श्री प्रांजल बाजपेयी, क्षेत्र प्रमुख सूरत; श्री अमित कुमार, सहायक महा प्रबंधक, पूर्व कार्पोरेशन बैंक; श्री सुनील सिंह नेगी, सरल प्रमुख, सूरत; श्री भौतिक सावलिया, यूएलपी प्रमुख, सूरत. साथ में उपस्थित हैं श्री हेमंत हरि, शाखा प्रमुख, रामपुरा शाखा, सूरत तथा श्री सुभाष कुमार, शाखा प्रमुख, टेक्सटाइल मार्केट शाखा, सूरत.

दि. 19.08.20 को क्षे.का.,सूरत के सम्मेलन कक्ष में आयोजित विपणन अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान खुदरा अभियान में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु श्री संदीप शर्मा, सहायक प्रबंधक (विपणन) यू.एल.पी, सूरत एवं सुश्री ब्रिन्दा चौधरी, सहायक प्रबंधक (विपणन), यू.एल.पी, सूरत को प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए श्री नीरज तोमर, उप क्षेत्र प्रमुख, सूरत.

दि 04.07.20 को बैंक की सी. एस. आर योजना के अंतर्गत सांध्येर शाखा ने ओलपाड तालुका के माध्यम से स्कूल के बच्चों को बैग वितरित किया गया. स्कूल बैग वितरित करते हुए श्री महेश जोशी, शाखा प्रबंधक, सांध्येर शाखा एवं साथ में उपस्थित हैं सांध्येर शाखा के स्टाफ सदस्य.

अनर्जक आस्तियों की बेहतर निगरानी और अंचल में वसूली की बढ़ोत्तरी के लिए दि. 12.08.20 को क्षे. का. पुणे पूर्व और क्षे.का., नागपुर में आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा (एआरएमबी) की स्थापना की गयी. पुणे के जे एम रोड डेक्कन जिमख़ाना पर स्थित शाखा का शुभारंभ क्षे.का., पुणे (पूर्व) के क्षेत्र प्रमुख, श्री ओ.पी. बलोदी क्षे.का., पुणे (पश्चिम) की क्षेत्र प्रमुख, श्रीमती शारदा मूर्ति की उपस्थिति में अंचल के क्षेत्र महा प्रबन्धक, श्री प्रमोद कुमार गुप्ता द्वारा किया गया. विशेष एआरएमबी का लक्ष्य 25 करोड़ और उससे कम की अनर्जक आस्तियों की निगरानी और वसूली है.

क्षे.म.प्र.का., क्षे.का. भोपाल (सेंट्रल) व क्षे.का. भोपाल (दक्षिण) में ध्वजारोहण समारोह का आयोजन दि. 15.08.20 को किया गया, जिसमें क्षेत्र महाप्रबन्धक भोपाल, श्री अभिजीत बसाक ; क्षेत्र प्रमुख, भोपाल (सेंट्रल) श्री अखिलेश कुमार के कर कमलों से क्षेत्र महाप्रबन्धक कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल सेंट्रल प्रांगण में झंडावंदन किया गया. इस अवसर पर उप अंचल प्रमुख, श्री वेलेरियन केस्टेलिनो; उप महाप्रबंधक, श्री गुरतेज सिंह; उप क्षेत्र प्रमुख, भोपाल (सेंट्रल) श्री राजेश बाली; उप क्षेत्र प्रमुख, भोपाल (दक्षिण) श्री बी पी अधिकारी; सहायक महाप्रबंधक श्रीमती याचना पालीवाल; सहायक महाप्रबंधक, श्री मुकेश बब्बर के साथ-साथ स्थानीय शाखाओं के शाखा प्रमुख एवं स्टाफ सदस्य उपस्थित थे.

समामेलन की प्रक्रिया में दि. 25.06.20 को यूनियन बैंक के इंदौर क्षेत्र स्तर पर कॉर्पोरेशन बैंक एवं आन्ध्रा बैंक की शाखाओं का समामेलन कर इंदौर क्षेत्र का पुनर्गठन किया गया. इस अवसर पर क्षेत्र प्रमुख, इंदौर श्री मनोज कुमार; सरल प्रमुख, श्री अनुज कुमार ने केक काटकर उक्त आयोजन की शुरुआत की.

यूनियन समृद्धि केंद्र, उज्जैन, मिड कॉर्पोरेट शाखा एवं यू एल पी शाखा, इंदौर में समामेलन कार्यक्रम का आयोजन दि. 08.07.20 को किया गया. इस अवसर पर, केक काटकर समामेलन की प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया.

दि. 09.07.20 क्षेत्र महाप्रबन्धक, भोपाल, श्री अभिजीत बसाक का प्रथम बार क्षे.का. इंदौर में आगमन हुआ. इसी अवसर पर श्री बसाक द्वारा क्षेत्र प्रमुख श्री मनोज कुमार एवं सरल प्रमुख श्री अनुज कुमार की उपस्थिति में शाखा प्रमुखों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की गयी.

क्षे.का. इंदौर में दि. 20 से 25.07.20 के मध्य एच. आर सप्ताह मनाया गया. इस अवसर पर क्षेत्र प्रमुख, श्री मनोज कुमार स्टाफ सदस्यों को संबोधित करते हुए.

क्षे.का.,उदयपुर के रोल आउट कार्यक्रम में क्षेत्र प्रमुख श्री जितेंद्र सिंह तोमर ने केक काटकर विशेष पूजा अर्चना की. इस अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर के स्टाफ के अतिरिक्त आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक की स्थानीय शाखाओं के अधिकारी उपस्थित रहे.

दि. 20.08.20 को क्षे.का. जयपुर में एसेट रिकवरी मैनेजमेंट शाखा का उद्घाटन किया गया. इस अवसर पर क्षेत्र महाप्रबंधक, श्री राम कुमार जागलान; उप क्षेत्र महाप्रबंधक, श्री चन्द्र स्वरूप; उप महाप्रबंधक, श्री के वेणुगोपाल; सहायक महाप्रबंधक, श्री डी. एन. गुप्ता; सहायक महाप्रबंधक, श्री पी. एल. मीना एवं एआरएम शाखा प्रमुख श्री प्रदीप कुमार मेहर उपस्थित रहे.

समाचार (दक्षिण)

दि. 10.08.20 को क्षे.म.प्र.का., बेंगलुरु के एसएएमवी सेल व आस्ति वसूली शाखा का शुभारंभ श्री बी.श्रीनिवास राव, क्षेत्र महाप्रबंधक, बेंगलुरु द्वारा फीता काटकर किया गया. इस अवसर पर श्री गुरु सुब्रमण्यम, उप महाप्रबंधक (बाएँ) व शाखा प्रमुख, श्री आर. प्रभु, सहायक महाप्रबंधक (दायें) के साथ शाखा के सभी सदस्य.

दि. 24.07.20 को क्षे.म.प्र.का., विशाखापट्टनम में आयोजित एच आर सप्ताह 2020 में श्री बी श्रीनिवास सेट्टी, क्षेत्र महाप्रबन्धक; श्री जी श्रीनिवास मधु, उप अंचल प्रमुख तथा अन्य स्टाफ सदस्य.

दि. 05.08.20 को क्षे.का., बेंगलुरु (दक्षिण) के सभागार में बेंगलुरु अंचलाधीन सभी क्षेत्र प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक श्री बी.श्रीनिवास राव, क्षेत्र महाप्रबंधक, बेंगलुरु की अध्यक्षता व श्री पी. सीतारमैया, उप अंचल प्रमुख व श्री गुरु सुब्रमण्यम, उप महाप्रबंधक की उपस्थिति में संपन्न हुई. इस अवसर पर (खड़े हुए बाएँ से) क्षेत्र प्रमुख गण श्री एन. श्रीनिवास राव, क्षे.का., हुब्बाल्ली; श्री ए.रवींद्र, क्षेका, बेंगलुरु(उत्तर); श्री टी.नञ्जुंडप्पा, क्षेका, बेंगलूरु (दक्षिण); श्री डी. कनवारियाँ, क्षेका, बेलगावी; श्री सी.वी.मंजूनाथ, क्षेका, मैसूर; श्री सी.प्रभु, क्षेका, शिवमोग्गा; श्री टी.ए.नारायण, क्षेका, कलबूरगी तथा श्री आलोक कुमार, क्षेका, बेंगलूरु (पूर्व).

On 28.08.20, Onam festival celebrated in RO, Trivandrum. R.H., Smt Sreekala L.K, Deputy Regional Head, Mr. Rajesh Pillai addressed the function and gave festive wishes to the staff members.

कोविड–19 महामारी की वजह से उत्पन्न स्थितियों के कारण दि. 15.08.20 को आयोजित एक समारोह में क्षेत्र महाप्रबंधक, बेंगलुरु, श्री बी. श्रीनिवास राव (केंद्र में खड़े) द्वारा तिरंगा फहराकर 73 वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया. इस अवसर पर (बाएँ से) श्री ए. रवींद्र, क्षेत्र प्रमुख, क्षे.का., बेंगलुरु (उत्तर), श्री गुरु सुब्रमण्यम, उप महाप्रबंधक, श्री टी. नञ्जुंडप्पा, क्षेत्र प्रमुख, क्षे.का., बेंगलुरु (दक्षिण), श्री आलोक कुमार, क्षेत्र प्रमुख, क्षे.का., बेंगलुरु (पूर्व), श्री पी. सीतारमैया, उप अंचल प्रमुख, बेंगलुरु व समस्त स्थानीय सुरक्षा अधिकारी व गार्डस् उपस्थित रहें.

मदुरै क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण के उपरांत उपस्थित मान्यवरों के साथ क्षेत्र प्रमुख, मदुरै.

On 15.09.20, Shri V. Murali, Regional Head, Tiruchirapalli Region donating the cleaning and sanitization material to public utility conservancy workers on the eve of Swachh Bharat Abhiyan.

भारत सरकार द्वारा घोषित आकांक्षी जिला विरुधुनगर में दि. 15.09.20 को बैंक द्वारा ऋण पोषित SEEDS संस्था का दौरा करते हुए नाबार्ड के अध्यक्ष, डॉ. चिंताला. साथ में उपस्थित हैं मदुरै क्षेत्र प्रमुख, सुश्री आर. जास्मिन.

On the eve of MoU of Bancassurance tie-up between our Bank and LIC, a roll out function was organised at FGMO, Chennai on 20.07.20 for distribution of LIC policies at our Bank branches. Shri K. Kadiresan, Zonal Manager, LIC Director of Union Bank of India; Shri M.H. Padmanabham, FGM², Chennai; Shri B.P. Das, R.H., Chennai (North) and Shri E. Pulla Rao, Regional Head, Chennai South graced the occasion along with other staff members.

भारत सरकार द्वारा घोषित आकांक्षी जिला रामनाथपुरम में 'डीप सी फिशिंग' से जुड़े लगभग 16 लोगों को दि.07.09.20 को ऋण अनुमोदन पत्र देते हुए जिला अधिकारी, श्री राघवेंद्र राव और मदुरै क्षेत्र प्रमुख, सुश्री आर. जास्मिन.

समामेलन के उपरांत क्षेत्र प्रमुख श्री यु वी रजनी कांता राव जी की अध्यक्षता में क्षे.का., सेलम का शुभारंभ केक काटकर किया गया.

भारत सरकार द्वारा घोषित आकांक्षी जिला रामनाथपुरम में दि. 19.08.20 को लगभग 125 स्वयं सेवा समूहों (SHG) की महिला सदस्य एवं अन्य सदस्यों को ऋण अनुमोदन पत्र देती हुई मदुरै, क्षेत्र प्रमुख, सुश्री आर. जास्मिन.

Shri Ramanathan, General Manager (retired), Union Bank of India inaugurating the roll-out programme of Regional Office, Tiruchirappalli on 29-06-20.

दि. 24.07.2020 को क्षे.का., सेलम के अंतर्गत सरल लाइट का शुभारंभ किया गया. इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़े अंचल प्रमुख श्री एम एच पद्मनाभम, क्षेत्र प्रमुख श्री यु वी रजनी कांता राव, उप क्षेत्र प्रमुख श्री एम जयकुमार, सरल लाइट प्रमुख श्री के शिव रामकृष्णन तथा अन्य स्टाफ सदस्य.

दि. 29.06.20 को क्षे.का., मदुरै में केक काटकर रोल आउट कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें सुश्री आर. जास्मिन, क्षेत्र प्रमुख के साथ माइक्रोसॉफ़्ट टीम्स के माध्यम से एवं उप क्षेत्र प्रमुख श्री एम आर मणियम के साथ ई-आंध्रा और ई-कॉर्पोरेशन शाखाओं के शाखा प्रमुख भी उपस्थित रहे.

दि. 29.06.20 के रोल आउट समारोह में क्षे. का., विशाखापट्टनम के नए परिसर में तीन बैंकों साथ हैं, श्री बी श्रीनिवास सेट्टी, क्षेत्र महा प्रबन्धक, विशाखापट्टनम; श्री जी. श्रीनिवास मधु, उप अंचल प्रमुख, क्षे.म.प्र.का, विशाखापट्टनम; श्री अजय कुमार, उप महा प्रबन्धक, क्षे.का., विशाखापट्टनम तथा स्टाफ सदस्य.

On the eve of Independence Day Smt. Sreekala L K, Regional Head hoisted the flag in Regional Office, Thiruvananthapuram on 15.08.20. Mr. Manohar MR, R.H., Kollam was the chief guest. Mr. Biju Surendran, DRH, Kollam was also present. Security Manager Mr Binu Kumar organized the function. Health workers and nurses were fecilitated on this occasion.

क्षे.का., तिरुवनंतपुरम के रोल आउट समारोह में उपस्थित क्षेत्र प्रमुख एवं उप महा प्रबंधक, श्रीमती श्रीकला. एल. के एवं उप क्षेत्र प्रमुख, श्री राजेश पिल्लै तथा अन्य कार्यपालक गण.

क्षे.म.प्र.का. विजयवाड़ा के नए परिसर के उद्घाटन अवसर पर क्षेत्र महाप्रबंधक श्री वी. ब्रह्मानंद रेड्डी जी; श्री के. वी. राव उप अंचल प्रमुख; श्री वेगी रमेश, क्षेत्र प्रमुख विजयवाड़ा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.

दि. 01.07.20 को सनदी लेखाकार दिवस के अवसर पर असहाय व्यक्तियों को खाद्य सामग्री प्रदान करते हुए श्री जगन्नाथ शेट्टी, क्षेत्र प्रमुख, क्षे.का., मंगलूरु साथ में उपस्थित हैं–सनदी लेखाकार श्री एस. एस. नाईक, अध्यक्ष, आईसीएआई, मंगलूरु शाखा.

दि. 15.09.20 को क्षे.का., मंगलूरु द्वारा 'स्वच्छता ही सेवा' बैनर के तहत स्वच्छ भारत अभियान में शताब्दी लाइब्रेरी परिसर की सफाई करते हुए श्री जगन्नाथ शेट्टी, क्षेत्र प्रमुख; श्री सतीश रै, उप क्षेत्र प्रमुख एवं अन्य कार्यपालकगण

दि. 27.08.20 को आयोजित ओणम समारोह का उद्घाटन करते हुए श्री डी. महेश्वरय्या, क्षेत्रीय प्रमुख, क्षे.का., कोषिक्कोड

दि. 15.08.20 को स्वतंत्रता दिवस के दौरान ध्वजारोहण करते हुए श्री डी. महेश्वरय्या, क्षेत्रीय प्रमुख, कोषिक्कोड

दि.23.09.20 को क्षे.का., कोझिकोड़ में आयोजित शाखा प्रबंधकों की समीक्षा बैठक का उद्घाटन करते हुए श्री एम वी बालसुब्रमण्यम, क्षेत्र महा प्रबंधक, क्षे.म.प्र.का., मंगलूर

THE SELF RELIANT WOMAN

Self reliance for women has a deeper meaning. As Ralph Waldo Emerson has quoted "Be yourself, no base imitator of another, but your best self". Self reliance is a quality of a woman in the truest sense, with an inner meaning. Every woman is a person with great compassion and care towards fellow human beings. They treat everyone with the realisation that every human being born in this world is pure and perfect. It is the situation that made them whatever they are. The qualities of endurance, tolerance, acceptance made them self reliant. The qualities to forgive, excuse, condone go with the quality of her inborn nature, making her Unique in her own way. It's these qualities that a woman has been bestowed with the consecration of procreation, the sublime capability of reproduction bringing life to this world.

Mother Theresa, it's the quality of her self reliance that made her establish the Missionaries of Charity, with 4500 nuns, active in 133 countries, a home for HIV/AIDS, leprosy and tuberculosis patients.

Muniba Mazari, known as the Iron lady of Pakistan, survivor of a car accident at the age of 21, moves in a wheel chair, and has shortlisted in the 100 inspirational women by BBC, made to Forbes 30 under 30 list of 2016, known for her self reliance. She evolved to be one of the best motivational speakers of the world.

Arunima Sinha, an Indian mountaineer and sportsperson, the world's first female amputee to scale Mt. Everest, Mt. Kilimanjaro and many such peaks. She has also scaled Mt. Vinson in Antarctica and is a self reliant woman.

These are examples of ladies who have achieved greatness through self reliance, an in born nature of womanhood and have carved a niche for themselves in the world. There are millions and millions of such women all over the world, including you and me.

Self reliance is the uniqueness with which every individual is born. As per an anonymous quote, "Always be a first version of yourself and not a second rate version of someone else"

It is this uniqueness which needs to be manifested and exploration of bringing out the best of our own self, which lies within ourselves. Every woman's experience contributes to her wisdom which elevates her to a better individual. With this wisdom, the common responsibility of elevating humanity around us needs to be fulfilled making life a complete one, a well lived life which remains as an example for others to look up to, making them women who have treaded this world in a better way than their fellow counterparts.

Sasikala Raja
Hasthampatti, Ro Salem

'A Banker's Musings : Trials and Triumphs'

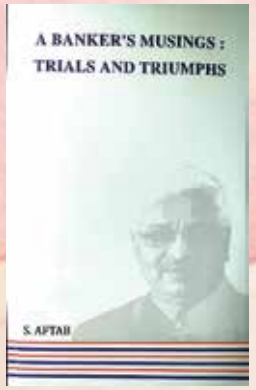

I had read somewhere a quote, which meant that an idle mind is a devil's workshop. I have a feeling that the essence carried in the saying is faultlessly correct. I thank the Almighty God that I have hardly got time to give my mind the luxury of resting. My first book is simply a product of my agile mind, which keeps me knocking to do something new that may help me attain inner satisfaction.

I was born in a family where only my parents and a couple of cousins were much older than me. So I inherited writing under the influence of my father, who himself was keen on writing. From my childhood days, I aspired to write something.

In the beginning, it was letters to the editors in newspapers and magazines. I graduated to write articles for school and college magazines, but once I landed in the bank, I didn't get time to pursue my writing skills, except, of course few articles in Union Dhara. I remember one of my articles on 'Mission 500' sometime in 2009 got me a prize too.

As it happens with all the bankers, one is too involved in the bank, without much care for the family. So till I was in the bank, I could not think of writing. Once I retired after 35 years as a banker, I again got jobs, which kept me very busy with work, and the latent potential was kept in hibernation.

It was only a result of self-imposed quarantine during the early days of Covid19 pandemic - a global crisis of never-before-experienced proportions that I experienced boredom. There were plenty of virgin books on my bookshelves, which were to be read. It was a sheer chance that I got hold of a book by Madam Sudha Murthy - THE DAY I STOPPED DRINKING MILK, a book of short stories from her life.

When I was reading the stories, I found them so simple, so original coming from the writer's heart and that ignited in me the urge to write my stories. For me, the easiest was to tread through my banking life, which had seen many ups and downs and were recorded/documented in one way or the other.

Then I started writing one story a day, and in three months, I had a collection of seventy-five stories.

The most challenging job was to edit the stories, make them factually correct, seek professional guidance etc. I made myself almost all-in-one except for the editing part, as I wanted someone else to read through the text and suggest changes. I shouldered the publisher's responsibility, obtaining ISBN and all related jobs with the book's printing, publication, and marketing.

In the process, I took the help of various friends and relatives, who did a yeoman's job. Then the final selection of stories was made through discussions with my wife, multiple friends, and even my daughters. All this happened on an inter-continental basis as people were spread worldwide and volunteered to help me.

Why should people read my book ?

When I look at a banker's life, I find that more than 90% of the bankers are very hard working, most of them are honest, and they do a lot for society at large. Unfortunately, the general public is not aware of the pains and the intricacies in a banker's life. As it happens in the life of other bankers, it happened in my life too. I wanted to share my experience with the readers.

I am confident that most of the bankers would relate my stories with their lives as bankers. The younger bankers may find the stories somewhat educative and eye-opening too. They can get an idea of the essential spirit of working in a bank. Apart from the cut-throat competition, there has to be an element of self-sacrifice, endurance, empathy, and honesty towards society, institution and the family.

The non-banker readers interested in storybooks would also find the book's content interesting as it weaves around actual happenings. The technicalities of banking jargons and processes have been kept to minimum so that the layman should not be bored by details.

Contents of the book : It is a short storybook, having 30+ stories, beginning with applying for the bank's job to the last day of my life with the bank. The stories are mostly in chronological order, with hardly a couple of overlapping. I have tried to make the stories enjoyable without disturbing the originality. I have avoided naming the people as it may infringe on the person's privacy, and in a few places, names have been intentionally changed. The book's stories give an idea of how the bankers used to work a few decades back. The irony is that despite the absence of computers and high-quality communication gadgets, the banks used to provide the services with almost the same ease, accuracy and efficiency. Can one imagine that we had Telex Machines in

those olden days, which was almost as fast as the present-day social media? The intercity and even inter-continental money transfers were done with present-day precision and promptness, despite the handicap of high-speed systems and devices.

Stories in the book : As I had worked at various stations spread in as many as eleven States, I have selected in my book the ones, which will attract the readers' interest most. For me, all the stories are close to my heart. Now on the rear side, when I visualize my book's contents, I expect that few stories shall attract a more devoted readership.

In 1998 January, there happened a devastating incident in Assam. Two armed policemen and our colleague, a branch manager, who had joined Assam duties, were brutally killed. The aftermath of the incident was more furious for me personally as I had been given the responsibility to airlift the body of a dear colleague from the north-easternmost State of the country, Arunachal Pradesh to his home village in interior Orissa. After that, the price of being dynamic kept on honking my peace for years together. I still feel that it was my grit and zeal which entailed me to sustain the vagaries.

Likewise, one story of education loan to a bright student, despite hurdles created by the bosses, gave me a lot of satisfaction as the life of the family changed after the bright student came out in life with flying colours and attained a position that must have made many envious of him.

One Hindi song Itni Shakti Hame Dena Data... has attained the status of corporate anthem for the bank. How it was started in Central Office is an incident in itself. An informal talk, the spurt of an idea, blurting it to the bank's top boss, gave birth to the bank's so-called corporate anthem. It will do an exciting reading.

As for as my personal life is concerned, the worst day in my life was 23rd July 2013, when travelling on the international circuit, with my wife and younger daughter, we missed a flight from Paris to Mumbai. In Paris, the Charles D' Gaulle Airport was our transit point, and we had to change a flight en-route from Newcastle upon Tyne in the UK to Mumbai. We missed the flight, we had no money, credit cards were not working and we had no visa for France. That was a real ordeal. Readers should like it and learn something too.

One story about our National Flag is very close to my heart. I opine that we as Indians should have the ultimate respect for our Nation, Constitution and the Tricolour as it gives our country's identity. Two incidents happened and I just wanted to pen it down and it came up quite convincing.

Most of my stories are quite positive, except for a couple of them but life is not always a bed of roses. Jigar Moradabadi, a renowned Urdu poet, has aptly penned philosophy of life in the following lines:

गुलशन परस्त हूं मुझे गुल ही नहीं अज़ीज़
कांटों से भी निबाह किए जा रहा हूं मैं

There is a repeated query about why the book is not listed with Amazon or Flipkart and when the eBook will be launched. E-Commerce portals require that the sellers utilizing the services must have GST, though there is no GST on printed books. My GST applications are yet to be approved and till such time, the book's sale is handled by the publisher-cum-author. Once the first print of the physical book is sold off, then we may think of launching the eBook after thorough editing the errors that must have crept in.

I look forward to a resounding success of the book, especially amongst Unionites.

S. Aftab
Retired GM, CO, Mumbai

जिंदगी की डगर

जिंदगी की डगर,
जो न समझे वो अनाड़ी है,
जो समझ–समझ कर चले, वो अग्रसर है.
जीवन अबूझ पहेली है,
जो कई भागों में विभाजित है.
युग बदला, समय बीता,
बीत गया माया–जाल.
विचार बदले, सभ्यता बदली,
बदल गयी पुरानी राह.
प्रति क्षण, प्रति पल,
पुरानी राह ही मार्ग दर्शाती है,
नये मार्ग के नये पथ पर
उद्वेलित करती है..
अर्वाचीन प्राचीन का सम्मिश्रण
नये युग का दिग्दर्शक है.
अनुभव ने नई तकनीक को संवारा है.
प्राकृतिक तकनीक अनुभव बिन बेबश है,
अनुभव तकनीक बिन निरर्थक है...
अनुभव तकनीक का समामेलन,
एक नये युग का निर्माता है.
देश को नये पथ पर ले जाने का,
नया मार्ग दर्शाता है.
समय अपने युग को दोहराता है,
मानव पर अट्हास कर चिढ़ाता है.
मानव, तू कितनी भी कर ले तरक्की,
प्रकृति की गोद विस्मृत न कर.
प्रकृति हर दिन नया रूप दर्शाती है,
मानव को जीवन जीने का
मार्ग दिखलाती है.
हमने प्रकृति को गुलाम बनाया था,
प्रकृति ने हमें ऊंचाई से गिराया है.
मानव प्रकृति का सहभागी बन,
प्रकृति को मित्रवत मान,
अपनी राह का रोड़ा न मान.

डॉ. मीना कुमारी
सेवानिवृत्त, दिल्ली

कोकम के कारनामें

कोकम को औषधीय फल माना जाता है जिसका फल, जूस, मसाले और दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. यह दिखने में सेब जैसा नजर आता है. कोकम फल का वैज्ञानिक नाम गार्सिनिया इंडिका (garcinia indica) है. सुंदर बैंगनी रंग के कोकम फल का स्वाद खट्टा होता है.

एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-इंफ्लामेट्री से भरपूर कोकम आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता हैं. कोकम में मौजूद एंटी-कार्सिनजेनिक तत्व गार्निकॉल, कैंसर के प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन जींस के उत्पादन को कम करता है. कोकम में उपस्थित आवश्यक फैटी एसिड पार्किसंस और अल्जाइमर रोग जैसी कमजोर मस्तिष्क स्थितियों को दूर करने में मदद करता है.

कोकम का ताज़ा ज्यूस पेट की जलन, बदहज़मी, पेट में रुकावट आदि से राहत देता है.

कोकम फल में बी-कॉम्प्लेक्स विटामिन, पोटैशियम, मैंगनीज और मैग्नेशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हृदय गति और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं. साथ ही स्ट्रोक और हृदय रोग के जोखिम को भी कम करने में लाभदायक हैं. इसके अलावा, इसमें कार्डियोप्रोटेक्टिव गुण (Cardioprotective-हृदय स्वास्थ्य के लिए सुरक्षात्मक गुण) भी पाया जाता है.

कोकम से मेटाबोलिज्म बढ़ता है. कोकम का हाइड्रोक्सी साइट्रिक एसिड नामक तत्व फैट बर्न करने और वजन कम करने में मदद करती है. कोकम जूस का सेवन करने से लिवर स्वस्थ रहता है.

कोकम बटर-कोकम बटर का इस्तेमाल ब्यूटी प्रोडक्ट में किया जाता है. कोकम साबुन, लिप बाम आदि प्रोडक्ट बनाने में काम आता है.

कोकम फल में एंटी-डायरिया गुण पाया जाता है, जिसके कारण कोकम फल के जूस का सेवन करने से यह डायरिया के उपचार में मदद करता है.

कोकम फल में एंटी-ट्यूमर एक्टिविटी तथा एंटी-पाइल्स के गुण पाए जाते हैं.

कोकम फल को शर्बत के रूप में इस्तेमाल करके सूर्य और अन्य कारणों से होने वाली त्वचा की जलन को कम करने और स्किन डैमेज को रोकने में मदद मिल सकती है. कोकम का सेवन फ्री रेडीकल्स को निष्क्रीय करके दिमाग को डैमेज होने से रोकता है.

कोकम से नुकसान – कोकम का अधिक सेवन पेट में परेशानी का कारण बन सकता है.

कोकम के अधिक सेवन से कफ एवं वात बढ़ता है.

हाई ब्लडप्रेशर से पीड़ित लोगों को अधिक मात्रा में कोकम का सेवन करने से बचना चाहिए.

गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए.

सुप्रिया नाडकर्णी
यूनियन धारा, कें.का.

लौकी की बर्फी

आवश्यक सामग्री :- लौकी-1 कि.ग्रा., चीनी-डेढ़ कप, घी-दो चम्मच, मलाई-डेढ़ कप, दूध-डेढ़ कप,

नारियल का बुरा-डेढ़ कप, इलायची-दो से तीन, ग्रीन फ्रूड पाउडर-एक चुटकी, मिल्क पाउडर-डेढ़ कप, ड्राई फूट, थोडी सी चांदी की बरक.

विधि :- 1 किलो लौकी लेकर उसको साफ पानी से अच्छे से धो लेंगे, उसके बाद लौकी के छिलके निकाल कर उसे दो भागों में काट कर उसके बीज निकाल लेंगे, ताकि बर्फी लच्छेदार बने. उसके बाद उसे कद्दूकस कर लेंगे. एक छन्नी की सहायता से कद्दूकस की हुई सारी लौकी का पानी निकाल लेंगे. एक पैन में दो चम्मच देसी घी लेंगे और गर्म हो जाने पर कद्दूकस की गई लौकी को उसमें डाल देंगे. इसे 2 से 3 मिनट पकाएगें और 5 मिनट के लिए ढ़क देंगे. फिर उसमें डेढ़ कप मलाई, डेढ़ कप दूध व डेढ़ कप चीनी डालकर इसे और पकने देंगे. फिर उसमें नारियल का बुरा, मिल्क पाउडर, इलायची और ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे और अच्छे से पकने देंगे. एक चम्मच घी और डालेंगे और फिर इसे तब तक पकने देंगे जब तक लौकी घी ना छोड़ दे. उसके बाद गैस को बंद कर देंगे.

अब एक ट्रे लेकर उसमें घी लगाकर, पैन से सारा मिश्रण निकालकर ट्रे में उसे अच्छे से जमा देंगे. उसके ऊपर चांदी की बरक लगाकर 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे. इसे आप मनचाहे आकार में काट कर सर्व कर सकते हैं.

तैयार है आपकी लौकी की बर्फी!

राजेश जोशी
यूनियन धारा, कें.का.

आपकी पाती
Opinion Gallery

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई की गृह पत्रिका '**यूनियन धारा**' का अप्रैल–जून 20 का कोविड 19 विशेषांक प्राप्त हुआ. सहृदय धन्यवाद. पत्रिका को देखते ही पढ़ने की इच्छा हुई. कोविड 19 विशेषांक में कोरोना से जुड़ी सभी विषय–वस्तु संग्रहणीय है. पत्रिका में सभी लेख, संस्मरण, कविता का समावेश कर इसे आकर्षक और रुचिकर बनाया गया है. पत्रिका की साज–सज्जा सुंदर है और प्रकाशित फोटोग्राफ बैंक की गतिविधियों को दर्शाते हैं विशेष रूप से 'कोरोना वैश्विक महामारी', 'कोरोना काल में आयुर्वेद की ओर', 'स्वास्थ्य सेवा : मौलिक अधिकार', Impact of corona on world economy?, 'लॉकडाउन के अनुभव', 'कोरोना काल में चरमराती अर्थव्यवस्था' आदि लेख ज्ञानवर्धक और पठनीय हैं. कविताओं में 'लॉकडाउन का फसाना' और 'वाह रे कोरोना', 'जिंदा हूँ मैं' रुचिकर हैं. आगामी अंक के लिए शुभकामनाओं के साथ–साथ संपादक मंडल को हार्दिक बधाई.

मनोज कुमार शुक्ला
सहायक निदेशक (राजभाषा), हिंदी अनुभाग परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार

हमें यूनियन बैंक द्वारा प्रकाशित '**यूनियन धारा**' गृह पत्रिका का अप्रैल–जून 20 अंक प्राप्त हुआ. कोविड–19 विशेषांक के रूप में प्रकाशित इस पत्रिका के सारे लेख प्रशंसनीय है, विशेषकर 'देश के मजदूर' नामक कविता अत्यंत प्रासंगिक है. कोरोना वायरस पर आधारित हिंदी तथा अंग्रेजी के कई लेख इसमें समाहित है. यह सब बहुत ज्ञानवर्धक है. कोविड–19 महामारी के प्रभाव का आकलन करने में इस पत्रिका के सभी लेखक सफल हुए हैं. सबको बधाइयाँ. आगे भी आपका यह सृजनात्मक प्रयास जारी रहे. 'यूनियन धारा' पत्रिका के इस कोविड 19 विशेषांक के संपादक तथा पूरी टीम को एक बार फिर से बधाइयाँ. आगामी अंकों के लिए भी शुभकामनाएं.

रिजिन राज एम के
हिंदी सहायक, भारतीय प्रबंध संस्थान, कोषिक्कोड

यह मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि '**यूनियन धारा**' द्विभाषिक पत्रिका का अप्रैल–जून अंक पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ. कोविड–19 पर आधारित विशेषांक काफी सराहनीय है. काफी सारे लेख पढ़ने का सौभाग्य मिला. जो कालक्रम के अनुसार सटीक हैं. पत्रिका की साज–सज्जा बहुत ही आकर्षक और बेहतरीन है. पत्रिका की सफलता के लिए बहुत–बहुत शुभकामनाएँ.

डॉ. सीमा चन्द्रन
सहायक आचार्य, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केरल.

आपके द्वारा प्रेषित '**यूनियन धारा**' का अंक–2 प्राप्त हुआ. बहुत–बहुत धन्यवाद. पत्रिका की साज–सज्जा बहुत ही सुंदर और मोहक है एवं प्रकाशित कविताएं और लेख रोचक और आकर्षक हैं. 'डिजिटल बैंकिंग क्षेत्र पर कोरोना का सकारात्मक प्रभाव' एवं 'व्यवहार/आचरण में आवश्यक तब्दीलियाँ' इस अंक को विशेष रूचिकर एवं संग्रहणीय बनाते हैं. इस सुंदर अंक को प्रकाशित करने के लिए आपको एवं संपादक मंडल को हार्दिक बधाई. मैं कामना करता हूँ कि पत्रिका की यह उत्कृष्टता सदैव बनी रहे.

वीरेन्द्र कुमार
उप प्रबंधक (राजभाषा) पंजाब नेशनल बैंक,
मण्डल कार्यालय,जबलपुर

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की कॉर्पोरेट तिमाही गृहपत्रिका '**यूनियन धारा–कोविड–19 विशेषांक**' की ई–प्रति हमें प्राप्ति हुई. पत्रिका का यह विशेषांक समसामयिक परिस्थिति अर्थात कोरोना महामारी से संबन्धित विषय– वस्तुओं को अपने में समेटे हुये है. इसमें प्रकाशित सभी लेख व रचनाएँ कोविड महामारी से उत्पन्न वर्तमान परिदृश्यों की सजीव एवं अर्थपूर्ण प्रस्तुति करते हैं. अभिनव जैन द्वारा रचित 'देश के मजदूर' और मनीष कुमार द्वारा रचित 'प्रकृति–एक वरदान' शीर्षकीय कविताएं मार्मिक और प्रिय लगीं. इसके साथ ही नरेंद्र कुमार अग्रवाल का आलेख 'कोविड महामारी का आम जन पर प्रभाव' सेवानिवृत्त जीवन से 'क्या इंसान इस दुनिया के नहीं हैं?' आलेख भी काफी प्रभावशाली हैं. समग्र रूप से पत्रिका विषय की विविधताओं को समेटती है. इस पत्रिका में देश के विभिन्न शहरों की शाखाओं व कार्यालयों से रचनाकारों की सक्रिय सहभागिता एवं समस्त दिशाओं से गतिविधियां एवं समाचारों का समेकन बहुत ही सराहनीय प्रयास है. निश्चित रूप से आपकी यह गृहपत्रिका सभी कर्मचारियों को एक रचनात्मक मंच प्रदान करने का सफल प्रयास है. कुल मिलाकर एक बेहतरीन व उत्कृष्ट विशेषांक के सफल प्रकाशन के लिए 'यूनियन धारा' के संपादक मंडल एवं पूरी टीम को बधाई तथा आगामी अंकों के लिए शुभकामनाएँ. बधाई व शुभकामनाओं सहित,

शकील अहमद
प्रबंधक (राजभाषा), बैंक ऑफ बडौदा, अहमदाबाद क्षेत्र1

Union Dhara, R.N.27989/76

धरती का एक छोर और चारों ओर जल ही जल
सांय सांय करती हवाएं, धड़कती मुझ पर हर पल
मैं खड़ा हूँ यहां, धरती के इस सुदूर कोने में
आपको दिखाऊंगा राह, रात की घनघोर स्याही में ।

कविता : डॉ. सुलभा कोरे
यूनियन धारा, कें.का., मुंबई

छायाचित्र : विकास विजयकर
मंजूसर शाखा, बड़ौदा

Printed and Published by Dr. Sulabha Shrikant Kore, on behalf of Union Bank of India and Printed at Jayant Printery LLP, 352/354, Murlidhar Temple Compund, Near Thakurdwar Post Office, J.S.S. Road, Mumbai - 400 002 and Published at Union Bank of India, 239, Union Bank Bhavan, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021. Editor - Dr. Sulabha Kore.